भारत-चीनः
सरहद पर तनाव

हरिद्वार कुंभ में आस्था
पर भारी महामारी

कहां है हनुमान का
जन्मस्थान!

5 मई, 2021 40 रुपए

इंडिया टुडे

नई दिल्ली में 16 अप्रैल को कोविड से मरे पिता का शव देखकर बिलखते शख्स को सांत्वना देता रिश्तेदार

कोविड-2.0

नया खौफ, उखड़ती सांसें

कहर बरपाती दूसरी लहर के बीच जिंदगी के साथ आजीविका भी बचाने की दोहरी चुनौती

RNI NO 45823/86 REGISTERED NO. DL(ND)-11/6042/2021-22-2023; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2021-23; FARIDABAD/46/2020-22

www.indiatodayhindi.in

OC

VISIT…

INDIA TODAY

We tell the story

Not the moral of the story

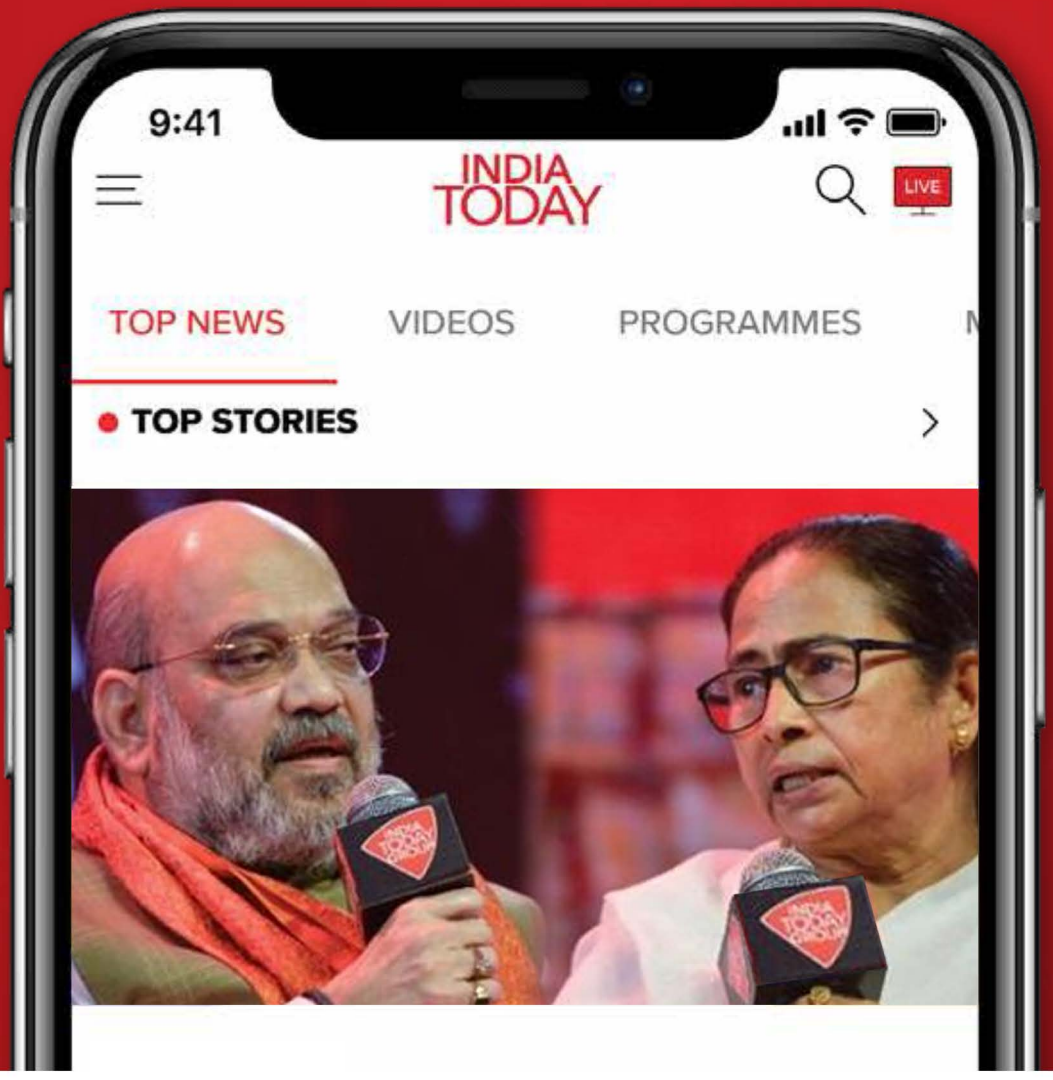

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

प्रधान संपादक की कलम से

हमारा देश युद्धरत है,'' जनरल वी.पी. मलिक ने 18 अप्रैल को ट्वीट किया. आखिरी बार युद्ध में सेना की अगुआई करने वाले भारतीय सेना प्रमुख होने के नाते वे बेहतर जानते हैं. देश में हर दिन 2,000 लोग कोविड-19 से हारकर जान गंवा रहे हैं, जो 1999 में 11 हफ्ते चले करगिल युद्ध में हताहत सैनिकों की तादाद से चार गुना हैं. मगर एक अहम फर्क है—यह महामारी कहीं दूर सरहद पर जनरलों और पेशेवर सैनिकों के बीच लड़ी जा रही जंग नहीं है. दूसरी लहर की सूनामी हमारे कस्बों और शहरों में आ धमकी है, हमारे दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को आगोश में ले रही है, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा उठी है, लोगों को अस्पताल में बिस्तर, ऑक्सीजन सिलिंडर और मृतकों की अंत्येष्टि के लिए श्मशान में समय लेने के लिए भी छीना-छपटी पर मजबूर कर रही है. 15 अप्रैल से रोज 2,00,000 से ज्यादा लोग एक दिन में संक्रमित हो रहे हैं, जो पिछले साल महामारी की शुरुआत के बाद दुनिया भर में नए मामलों की सबसे बड़ी तादाद है. भारत के 1.5 करोड़ सक्रिय मामलों में से 80 फीसद दस राज्यों—दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और राजस्थान—में हैं. दूसरी लहर की मृत्यु दर पहली की तरह भले 1 फीसद हो, लेकिन यह ज्यादा संक्रामक है जो खौफनाक रफ्तार से देश की चीरती चली जा रही है.

सक्रिय मामले हर 10 दिन में दोगुने हो रहे हैं. राष्ट्रीय टेस्ट पॉजिटिव दर इस हफ्ते औसतन 13.5 फीसद रही और 20 अप्रैल को एकाएक 20 फीसद पर जा पहुंची (डब्ल्यूएचओ मौजूदा उछाल सरीखी स्थिति से बचने के लिए इसे 5 फीसद से नीचे रखने की सिफारिश करता है). कुछ राज्यों में पॉजिटिव दर 30 फीसद है, जिसका अर्थ है हर तीन में एक शख्स का टेस्ट पॉजिटिव निकलना. भारत अब अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ग्रस्त देश है, जहां हालात और बिगड़ सकते हैं. सरकार को भी इस हकीकत की सुध आई इसीलिए उसने टीके 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए खोल दिए.

21 अप्रैल, 2021 का आवरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल को देशव्यापी लॉकडाउन की संभावना को खारिज कर दिया. पिछले साल मार्च में, जब विशेषज्ञ वायरस को ठीक से अभी समझ ही रहे थे, भारत ने 68 दिनों का जो लॉकडाउन लगाया था, उससे अर्थव्यवस्था को गंभीर नुक्सान पहुंचा. इस बार प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था की सेहत को देश की सेहत जितना ही जरूरी बताते हुए कोविड के संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए माइक्रो-कंटेनमेंट जोन और स्व-अनुशासन पर जोर दिया. हफ्तों भीषण गलतियां करने, आरोप-प्रत्यारोप मढ़ने, विदेशी वैक्सीनों को मंजूरी देने में हीला-हवाली करने और टुकड़ों में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने के बाद सरकार ने दवाइयों या वैक्सीनों की कमी से इनकार किया है. उसने नियम-कायदों में ढील और निजी क्षेत्र को आने की इजाजत दे दी. यह स्वागतयोग्य कदम था लेकिन उस दिन नए मामले पहले ही 2,90,000 और टेस्ट पॉजिटिविटी दर 17 पर जा पहुंची थी.

राज्य खुद अपनी रणनीतियों पर चल रहे हैं. दूसरे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य दिल्ली ने हफ्ते भर का लॉकडाउन लगाया है. महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ऐसे ही उपायों पर गौर कर रहे हैं. यह अब भी साफ नहीं है कि दूसरी लहर कब तक टिकेगी. लेकिन एक चीज तय है. हम एक अनदेखे और तेजी से रूप बदलने वाले दुश्मन से दो-चार हैं, जो अनियंत्रित छोड़ दिए जाने पर देश भर में कहर बरपा सकता है. संक्षेप में कहें तो हम एक संपूर्ण युद्ध झेल रहे हैं जो 1918 के स्पेनिश फ्लू से मिलता-जुलता है. युद्ध केवल सेना नहीं लड़ती, बल्कि राज्यसत्ता के समूचे संसाधनों के बल पर पूरा देश लड़ता है, यह लड़ाई भी व्यक्ति या सरकारें अलग-अलग नहीं लड़ सकतीं. इसके लिए समन्वित केंद्रीय नजरिये और सभी राष्ट्रीय संसाधनों के संयोजन की जरूरत होती है. कुछ कदम हैं जो सरकारों और राज्यों को युद्ध स्तर पर उठाने होंगे. पहला, हमें अपनी टेस्ट की सुविधाओं को मजबूत करना होगा. ज्यादातर शहरों में टेस्ट के नतीजे मिलने में पहले के छह घंटों के मुकाबले अब चार दिन लग रहे हैं. अगर तेजी से पर्याप्त टेस्ट नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि संक्रमण किस हद तक है.

पहली लहर में 80 फीसद मामले बगैर लक्षणों वाले थे, 20 फीसद को अस्पताल में भर्ती कराने और उनमें से 5 फीसद को आइसीयू तथा 1 फीसद के वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी थी. दूसरी लहर में भी यही सच है, सिवा इसके कि संक्रमितों की कुल तादाद कहीं ज्यादा है. हमें इस अदृश्य, तेजी से बढ़ते दुश्मन के जीनोम का पता लगाने पर संजीदगी से ध्यान देने की जरूरत है. जीनोम सीक्वेंसिंग, यानी पैथोजीन की जेनेटिक संरचना का अध्ययन, आरंभिक चेतावनी की प्रणाली है. इससे हम जान सकते हैं कि वायरस कहां-कहां और कैसे-कैसे घूम रहा है. सरकार वायरस के रूप बदलने की स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चेतावनियों के आगे बहरी हो गई थी. एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने हमसे कहा कि हम नए रूपों के क्लिनिकल लक्षणों पर नजर रखने में नाकाम रहे इसीलिए हम ऑक्सीजन की बढ़ती मांग सरीखी चुनौतियों के लिए तैयार नहीं हो सके. हमें संक्रमण की लहरें थामने के लिए वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाना होगा और सभी को जल्द टीका लगाना होगा. यह रॉकेट साइंस नहीं है—बीमार देश की कीमत वैक्सीन की कुछ अरब शीशियों की कीमत से कहीं ज्यादा है.

महामारी ने दहशत फैला दी है. जीवनरक्षक दवाइयों, इंजेक्शनों और ऑक्सीजन सिलिंडरों की जमाखोरी हो रही है. पिछले साल की तरह प्रवासी मजदूरों के जत्थों के अपने घरों की तरफ उमड़ पड़े हैं. सरकार को चाहिए कि चौबीसों घंटे सातों दिन काम करने वाले आपातकालीन नियंत्रण कक्ष बनाए और अपनी काबिलियत में लोगों का भरोसा बहाल करे. अगर इलेक्शन वॉर रूम संभाल सकती और देशव्यापी राजनैतिक अभियान चला सकती है तो दहशत से भी लड़ सकती है. डिजिटल इंडिया, यानी वह देश जहां दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा स्मार्टफोन यूजर और दुनिया का सबसे नफीस पहचान पत्र कार्यक्रम आधार है, अगर जरूरत में अपने लोगों के काम नहीं आया, तो यह शर्म की बात होगी.

हमारी आवरण कथा 'नया डर, उखड़ती सांसें' कोविड की दूसरी लहर की भयावहता और उससे लड़ने की रणनीतियां सामने रखती है. इसे देश भर में फैले ब्यूरो की रिपोर्ट के साथ एसोसिएट एडिटर सोनाली अचार्जी ने लिखा है. साफ है कि इस लड़ाई को लड़ना और जीतना ही होगा. आतंक के विरुद्ध अमेरिका की लड़ाई का हिस्सा रहे पूर्व अमेरिकी रक्षा मंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने कहा था, ''कुछ खतरे हमें पता हैं, कुछ खतरे पता हैं पर पूरी तरह नहीं पता हैं और कुछ खतरों के बारे कुछ भी नहीं पता है.'' वायरस के नए रूपों पर रिसर्च, असरदार दवाओं और प्रभावी वैक्सीन के बावजूद महामारी रौद्र रूप धारण करती जा रही है. लिहाजा कहना होगा कि हम अनजाने खतरों के समुद्र में तैर रहे हैं. लगातार सतर्कता रखना, हर जानकारी पर नजर रखना, रणनीतियां विकसित करना, एकजुट रहना और सामुदायिक स्तरों पर जवाबदेही लेना ही समाधान है. हम बतौर देश काफी आपदाएं झेल चुके हैं. हम इससे भी उबर ही जाएंगे.

अरुण पुरी

(अरुण पुरी)

इंडिया टुडे
www.indiatodayhindi.in

चेयरमैन और प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वाइस चेयरपर्सन: कली पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर: राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: मनोज शर्मा
एडिटर: अंशुमान तिवारी
सीनियर एडिटर: मोहम्मद वक़ास
एसोसिएट एडिटर: शिवकेश मिश्र, शुभम शंखधर
असिस्टेंट एडिटर: मनीष दीक्षित, सुजीत ठाकुर
राज्य ब्यूरो: आशीष मिश्र (लखनऊ), अमिताभ श्रीवास्तव (पटना), रोहित परिहार (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटर: नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर: चंद्रमोहन ज्योति
चीफ डिजाइनर: असित रॉय
ग्रुप फोटो एडिटर: बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंट: यासिर इकबाल, राजवंत रावत, चंद्रदीप कुमार, मंदार सुरेश देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चर: प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चर: सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफ: अभिनव पुगला
एसोसिएट पब्लिशर: अनिल फर्नांडीस
इंपैक्ट टीम
सीनियर जनरल मैनेजर: जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजर: मयूर रस्तोगी (नॉर्थ), उपेंद्र सिंह (बेंगलूरु)
डिप्टी जनरल मैनेजर: इंद्रनील चटर्जी (ईस्ट)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर: विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजर: दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजर: विपिन बग्गा (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजर: राजीव गांधी (नॉर्थ)
रीजनल सेल्स मैनेजर: सैयद आसिफ सलीम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजर: पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

INDIA TODAY GROUP

वर्ष: 35; अंक: 23; 29 अप्रैल-5 मई, 2021; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोन: 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजें:** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवा:** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोन: दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्स: (0120) 4078080. ई-मेल: wecare@intoday.com
- **सर्कुलेशन कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालय:** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोन: 022-66063355 फैक्स: 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोन: 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरु-560 025 फोन: 2212448, 226233, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN. फैक्स: 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालय: एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.
- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित. संपादक: राज चेंगप्पा**

सुर्खियां
कोरोना की चपेट में कुंभ
पेज 10

अर्थात्: जवाबदेही का बही-खाता
पेज 14

फुरसत
खेल: टोक्यो की तैयारी में जुटे भारतीय खिलाड़ी
पेज 46

सवाल-जवाब/इरफान पठान: रिटायरमेंट और नए काम पर
पेज 50

भीतर

यासिर इकबाल

आवरण कथा

दूसरी लहर का कहर

कोविड की नई लहर ने चिकित्सा के इंतजामों को ध्वस्त कर दिया, लोग बेड, ऑक्सीजन तथा टेस्ट के लिए तरस रहे हैं और आजीविका पर भी संकट के बादल छाए

26 ग्राउंड जीरो राज्य
भय और निराशा
कोविड 19 वायरस से लड़ाई के क्रम में संसाधन जवाब दे गए हैं, बेड का अकाल और टेस्ट नतीजों के लंबे इंतजार से हालत बदतर

38 अर्थव्यवस्था
कारोबारियों का संकट
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया पर राज्यों की पाबंदियों से कारोबार पहले से ठिठके हुए हैं

32 प्रवासी
दोहरी मार
लॉकडाउन की आशंका से रोजगार पर संकट और गृह राज्य में कमाई का कोई साधन न होने से बढ़ी प्रवासियों की मुश्किल

43 शिक्षा
फिर से सोचने की जरूरत
महामारी के चलते 10वीं-12वीं की परीक्षाएं रद्द करना या टालना विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कितना उचित है? शिक्षा को नए रोडमैप की जरूरत

आवरण फोटो : दानिश सिद्दीकी/रॉयटर्स

पाठकों के लिए सूचना: कभी-कभी आपको इंडिया टुडे पत्रिका में 'इम्पैक्ट फीचर' या 'एडवरटोरियल' या 'फोकस' के पन्ने नजर आएंगे. ये विज्ञापन होंगे और इन्हें बनाने में पत्रिका के संपादकीय स्टाफ शामिल नहीं होते.

INDIA TODAY GROUP

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी वस्तु, सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

कुंभ पर कोरोना की छाया
पेज 10

सुर्खियां

पौराणिकता को आधुनिक बना गए नरेंद्र कोहली
पेज 12

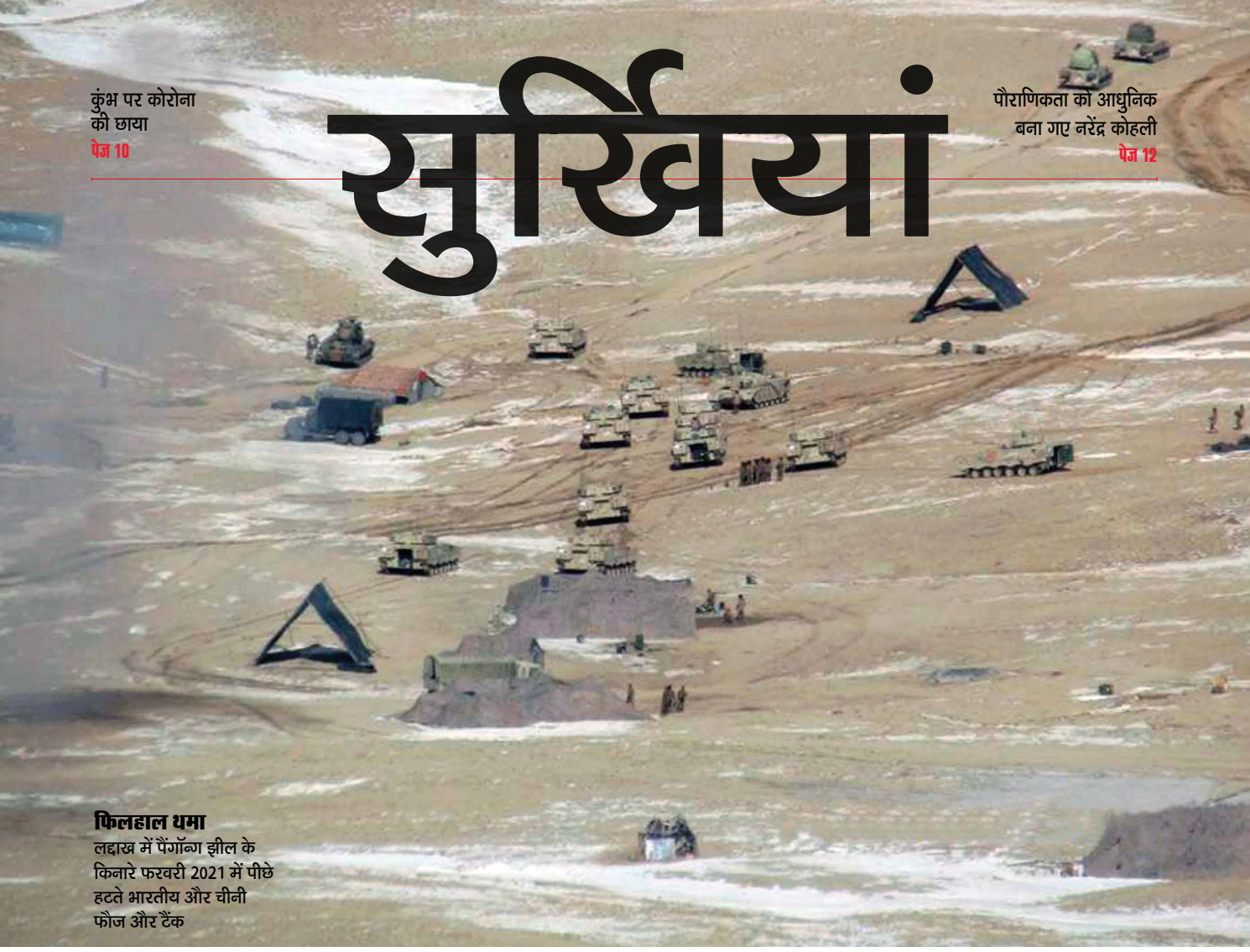

फिलहाल थमा
लद्दाख में पैंगॉन्ग झील के किनारे फरवरी 2021 में पीछे हटते भारतीय और चीनी फौज और टैंक

हैंडआउटः भारतीय सेना

भारत-चीन

सरहद पर फिर तनातनी

संदीप उन्नीथन

इस बात के दो महीने से थोड़ा ही अधिक वक्त बीता है जब पेगॉन्ग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी तटों से और कैलाश रेंज से सैकड़ों भारतीय और चीनी जवान, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां पीछे हटी थीं और अब, गर्मियों में लगता है कि छोटे स्तर की एक तनावपूर्ण तनातनी बरकरार रहने वाली है. भारतीय और चीनी टुकड़ियां लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट एक-दूसरे के आमने-सामने डटी रहने वाली हैं.

भारतीय सैन्य अधिकारियों के मुताबिक, टुकड़ियों की संख्या बहुत अधिक नहीं है—शायद एक प्लाटून या 32 जवान—जो दोनों जगहों पर चीनी तैनाती के जवाब में डटे हैं. यह तैनाती पिछले जून से जारी है जब भारतीय सेना और पीएलए (पीपल्स लिबरेशन आर्मी) एलएसी के अपने दृष्टिकोण बिंदु से 2 किमी पीछे हट गए थे. पीएलए फिलहाल दोनों जगहों पर भारत के नजरिए से एलएसी के करीब 700 मीटर भीतर है.

10 फरवरी के बाद दोनों पक्षों की ओर से टकराव के बिंदु खाली करने की कारवाई के बाद भी ये दोनों ठिकाने बने हुए हैं. उस वक्त रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि इन मुद्दों को 'बाद में उठाया जाएगा'. अब तक यह मुमकिन नहीं हो पाया है. एक भारतीय सैन्य अधिकारी ने कहा कि बातचीत के दौरान चीनी इन जगहों से पीछे हटने से इनकार कर दिया. उनके मुताबिक, ऐसा शायद इस वजह से हुआ कि भारत ने टकराव के दूसरे पहलुओं पर अपनी बात पूरी नहीं की, जिनमें चीनी ऐप्स पर बंदिश को ढीला करना भी शामिल था. चीन ने एलएसी पर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरीज तैनात कर रखी हैं और तिब्बत के पठार पर अपनी टुकड़ियों के लिए स्थायी ढांचे बना लिए हैं.

19 अप्रैल को, चीनी के सैन्य मुखपत्र *पीएलए डेली* ने कहा कि बीजिंग ने करीब 17,000 फुट की ऊंचाई पर लंबी दूरी की क्षमता वाले प्रिसीजन रॉकेट आर्टिलरी की तैनाती कर दी है. नई दिल्ली ने संकेत दिए हैं कि बिना पूरी तरह के पीछे हटे हुए, रिश्ते पहले जैसे नहीं हो सकते.

उनीस अप्रैल को नई दिल्ली में एक कॉनक्लेव में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, ''चीनियों ने, बिना उकसावे के ही सीमा पर बहुत अधिक संख्या में फौजी जमा किए.'' उन्होंने कहा, ''यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सीमा पर शांति और स्थायित्व में बाधा पहुंचाकर अपने बाकी के रिश्ते को बनाए नहीं रख सकते. यह बात मैं पिछले एक साल से कह रहा हूं और इसमें कुछ बदला नहीं है.''

10 फरवरी को फौज के पीछे हटने के बाद से और अधिक फौज के पीछे हटने को लेकर दो बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है. 20 फरवरी को दसवें दौर की बातचीत ने पैंगॉन्ग झील इलाके और कैलाश रेंज से पीछे हटने पर मुहर लगाई थी लेकिन दोनों पक्ष तीन टकराव बिंदुओं पर समझौते तक नहीं पहुंच पाए. 10 अप्रैल को अगले दौर की हुई बातचीत में भी मामला अटका ही रहा. विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि बाकी बचे हुए पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ फौज के पीछे हटने से जुड़े मुद्दों का समाधान लंबित है. बयान में कहा गया है, ''अन्य क्षेत्रों में पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी होने से दोनों पक्षों के लिए अमन और शांति की पूर्ण बहाली करने और द्विपक्षीय संबंधों को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त होगा.''

बेशक यह 'दूसरे क्षेत्र' का संदर्भ हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट से जुड़ा है. दोनों ही इलाके पैंगॉन्ग त्सो झील से उत्तर में स्थित हैं. इसके साथ ही देप्सांग पठार का मसला भी है जहां भारतीय सेना को अपनी गश्त चौकी पर कई साल से पहुंचने से रोका जा रहा है.

सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि चीनी एलएसी के साथ बनी अपनी पोस्ट से तब तक नहीं हिलेंगे, जब तक 1 जुलाई को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का शताब्दी समारोह न शुरू हो जाए. हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट पर चीनी नाफरमानी ने उन्हें हैरान कर रखा है. लेह स्थित 14 कोर के पूर्व जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा कहते हैं, ''चीनियों को इस इलाके में खतरा महसूस नहीं होता है क्योंकि हम यहां और अधिक सेना तैनात नहीं कर सकते या हालात को अधिक संगीन नहीं बना सकते.'' वे कहते हैं, ''उन जगहों तक पहुंचने का रास्ता मारसिमिक ला से जाता है, जो अगले छह महीनों तक बंद रहने वाला है.''

भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) ऐसे 65 पेट्रोल पॉइन्ट्स की निगरानी कर रही है जिसकी पहचान चाइन स्टडी ग्रुप (सीएसजी) ने 1970 के दशक के मध्य में की थी. सीएसजी चीन के मामले में भारत की शीर्ष निर्णायक निकाय है. इसने भारत के एलएसी के दृष्टिकोण की सीमाओं के तहत इन पॉइन्ट की पहचान की है. बेहद ऊंचाई पर मौजूद इस रेगिस्तान में आबादी नगण्य है और यह चीनी सलामी स्लाइसिंग का निशाना रहा है, और इसी लिए एलएसी के साथ इन पेट्रोल पॉइन्ट्स को स्थापित किया गया था, ताकि भारतीय दावा बना रहे.

अब तनातनी जारी है. अमेरिका के शीर्ष खुफिया निकाय नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल को रिपोर्ट करने वाले थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक फ्यूचर्स ग्रुप ने 7 अप्रैल की अपनी रिपोर्ट में आशंका व्यक्त की है कि भारत और चीन ऐसे संघर्ष में उलझ सकते हैं जो दोनों देशों की सरकारें नहीं चाहती.

हॉट स्प्रिंग्स में ही 21 अक्तूबर 1959 को सीआरपीएफ के 10 जवानों पर पीएलए ने घात लगाकर हमला किया था और उन्हें मार डाला था. यह उन छोटे संघर्षों में एक था जिसकी वजह से भारत और चीन आखिरकार युद्ध में उलझ गए. लेकिन 2021 में यह परिदृश्य थोड़ा दूर की कौड़ी लगता है. पीएलए शांति और अमन कायम करने वाले कई समझौतों को तोड़कर पिछले साल एलएसी पर अपने दो डिवीजन के साथ क्यों आगे बढ़ आई, इसके सटीक कारण अभी भी साफ नहीं हैं. लेकिन नई दिल्ली के आला नियंता इस बात को जानते हैं कि यह कोई सीमा संघर्ष नहीं है बल्कि यह बीजिंग की अपने विएतनाम, फिलीपीन्स और ताइवान जैसे पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद पर पंजा लड़ाते रहने की आम आदत जैसी है.

भारत और चीन एक बार एकदम आमने-सामने की पोजीशन से पहले ही पीछे हट चुके हैं. 15 जून, 2020 को, गलवन घाटी में हुए तीखे संघर्ष में 20 भारतीय जवानों और पांच पीएलए सैनिकों की मौत हो चुकी है. भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के एलएसी से कई बिंदुओं पर करीबन 1.5 किमी पीछे हटने का सत्यापन कर रहे थे, जहां वे घुस आए थे. इसमें गोगरा पोस्ट, हॉस स्प्रिंग्स और पैंगॉन्ग त्सो शामिल हैं.

भारत और चीन के बीच तनाव घटाने की त्रिस्तरीय प्रक्रिया में फौज का पीछे हटना महज पहला कदम है. आमने-सामने की स्थिति से पीछे हटना और आखिरकार जंग के हालात को खत्म करना निश्चित रूप से टकराव दूर करने का पहला कदम है. लेकिन पीएलए की दो डिवीजन और टैंक अभी भी उस सैन्य क्षेत्र में बने हुए हैं, जहां पिछली मई में नई दिल्ली से आंख बचाकर चुपके से तैनात कर दिया गया था. जाहिर है, अगली बड़ी तनातनी का मुकाम कुछेक घंटों के नोटिस के भीतर ही तैयार किया जा सकता है. तो, क्या भारत इसके प्रति सतर्क है.■

टकराव के बिंदु

भारत और चीन के बीच एलएसी पर इन जगहों से पीछे हटने के लिए बातचीत जारी

हॉट स्प्रिंग्स
पीएलए ने भारतीय सेना को पेट्रोल पॉइन्ट पीपी17ए पर पहुंचने से रोका. करीबन 40-50 फौजी बिल्कुल नजदीक में (600-800 मीटर के भीतर) तैनात हैं

गोगरा पोस्ट
ल्हासा के साथ कारोबार का एक पुराना पोस्ट, यह पीएलए और भारतीय टुकड़ियों के बीच टकराव का गवाह रहा है

देप्सांग पठार
इसका करीब दो-तिहाई हिस्सा चीन के कब्जे में है. पीएलए ने भारतीय सेना को पांच पेट्रोल पॉइंट तक जाने नहीं दिया है. भारतीय सेना ने पीएलए के गश्ती दल को बॉटलनेक के पश्चिम उनके दावे की जगह तक जाने नहीं दिया

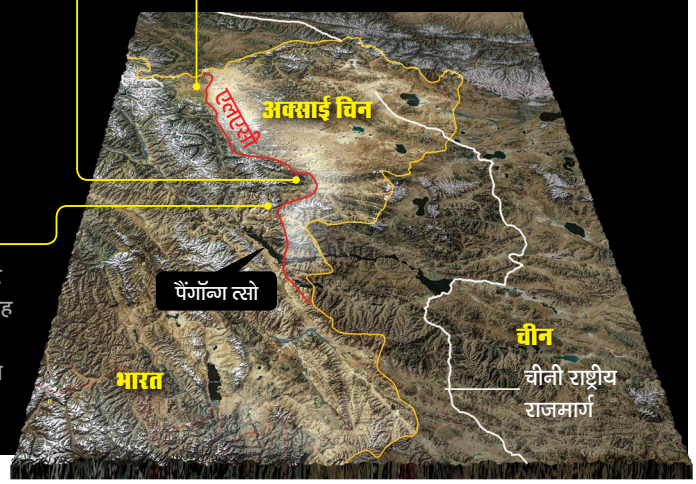

ग्राफिक: तन्मय चक्रवर्ती

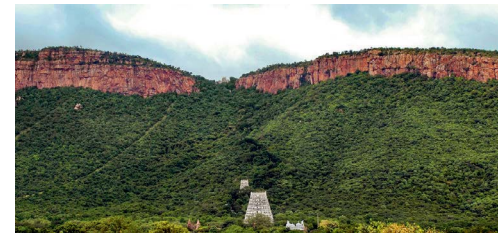

दावा
अंजनाद्रि को हनुमान जन्मस्थान घोषित करने के बाद टीटीडी विशेषज्ञ समिति के सदस्य और (ऊपर) तिरुमला पर्वत श्रृंखला व वेंकटेश्वर मंदिर

जन्मस्थान विवाद

हनुमान के जन्मस्थान!

अमरनाथ के. मेनन

रामनवमी पर 21 अप्रैल को सबसे दौलतमंद हिंदू तीर्थ के संरक्षक तिरुपति तिरूमला देवस्थानम (टीटीडी) ने 'मिथकीय, उत्कीर्णित और ज्योतिषीय साक्ष्य' पेश किए जिसमें दावा है कि तिरुमला ही भगवान हनुमान की जन्मस्थली है. दावे को बल देने के लिए दिसंबर, 2020 में टीटीडी ने आठ सदस्यों वाली समिति बनाई गई जिसमें संस्कृत और वेदों के विद्वान शामिल थे, यहां तक कि उसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिक भी थे ताकि हनुमान जन्मभूमि से जुड़े 'अकाट्य' साक्ष्य पेश हो सकें. यह काम तब किया गया था जब पिछले साल जून में टीटीडी की ओर से आयोजित धर्म सभा में प्रतिभगियों ने सवाल उठाए कि जन्मस्थान को लेकर अनिश्चितता क्यों है. इस संदर्भ में हनुमान जी के भक्तों ने एक जैसे उच्चारण वाली कई जगहों के नामों का उल्लेख किया था.

अब टीटीडी ने घोषणा की है कि देवस्थानम के तहत आने वाली सात पहाड़ियों में से एक अंजनाद्री ही हनुमान का जन्मस्थान है. यह निर्णय प्राचीन हिंदू शास्त्रों के संदर्भों के साथ ही उनका ज्योतिषीय गणनाओं के साथ मिलान करके किया गया है. समिति की अध्यक्षता राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के कुलपति मुरलीधर शर्मा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ''वाल्मीकि रामायण (श्लोक 81 से 83) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक तपस्या के बाद इन्हीं पवित्र पर्वतों पर अंजना ने हनुमान को जन्म दिया था. उन्हें आंजनेय कहा गया और इसलिए पहाड़ी का नाम अंजनाद्री पड़ा.'' रिपोर्ट में महाभारत का संदर्भ भी दिया गया है जहां, ''भीमसेन के साथ बातचीत के दौरान, हनुमान जी कहते हैं कि वे वायुदेव का आशीर्वाद से पंजीकस्तला नाम की एक अप्सरा के पेट से पैदा हुए जो एक शाप के कारण वानर स्त्री यानी अंजना हो गई थी.'' समिति ने तिरुमला मंदिर में उत्कीर्ण 1491 के एक शिलालेख का संदर्भ भी दिया है, और दूसरे संदर्भित शिलालेख का समय 1545 है जिसमें अंजनाद्री को जन्मस्थान बताया गया है.

इन उत्कीर्णनों के साथ ही, भारतीय साहित्य में भी जन्मस्थान के कई संदर्भ हैं. अंजनाद्री महात्म्य, जिसकी डिजिटल पांडुलिपि ब्रिटिश लाइब्रेरी में उपलब्ध है, साफ तौर पर अंजनाद्री को हनुमान जी का जन्मस्थान बताती है. एपिग्राफिका इंडिका में भी अंजानाद्री के संदर्भ दिए गए हैं. शोध के लिए पैनल ने मोटे तौर पर शिव, ब्रह्म, ब्रह्मांड, वाराह और मत्स्य पुराणों के शास्त्रीय साक्ष्यों पर भरोसा किया है.

बहरहाल, कुछ इतिहासकारों ने यह कहते हुए अपना शक प्रकट किया है कि कुछ ऐसे और भी स्थान हैं जो आंजनेय की जन्मभूमि होने का दावा पेश करते हैं. कर्नाटक में हंपी के पास अंजेयानाद्री नाम की पहाड़ी है, झारखंड में गुमला से 21 किमी दूर पर अंजन गांव है, गुजरात के नवसारी इलाके में अंजन पहाड़ है, हरियाणा का कैथल और महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रयंबकेश्वर से 7 किमी दूर भी एक अंजनेरी है. इन सभी स्थानों का जन्मस्थान होने का दावा है.

तिरुमला का दावा है कि सात पहाड़ियों में से एक अंजनाद्री भगवान हनुमान का जन्मस्थान है पर कर्नाटक हंपी के पास मौजूद आंजनेयाद्री के साथ प्रतिदावा कर रहा है

कर्नाटक ने पहले ही विवाद खड़ा कर दिया है और कहा है कि हनुमान जी का जन्मस्थान कोप्पल जिले में अनेगुंडी में किष्किंधा में उसकी सीमा में स्थित है. हंपी से सटी किष्किंधा की पहाड़ियों का रामायण में भी जिक्र है जिसमें इस स्थान को वही जगह बताया गया है जहां पर राम और लक्ष्मण हनुमान से मिलते हैं. अंजनेयाद्री पहाड़ी की चोटी पर हनुमान जी का एक मंदिर है जिसमें पत्थर पर राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां उकेरी हुई हैं और परिसर में अंजना देवी का भी मंदिर है. कर्नाटक के कृषि मंत्री बी.सी. पाटिल कहते हैं वे ''इस इलाके को तीर्थस्थल के रूप में विकसित कर रहे हैं और इसे हनुमान जन्मस्थल के तौर पर बना रहे हैं.''

टीटीडी पैनल के गठन के ठीक बाद, कर्नाटक पर्यटन विभाग अंजनेयाद्री पहाड़ी को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने की परियोजना की घोषणा की. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येद्दियुरप्पा खुद हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं. राज्य के पर्यटन मंत्री सी.पी योगेश्वर के मुताबिक, 50.2 करोड़ रुपए के लागत की एक परियोजना राज्य मंत्रिमंडल से स्वीकृति के लिए तैयार है. लेकिन जन्मस्थान के लिए एक और दावेदार है. शिमोगा में रामचंद्रपुर मठ के प्रमुख राघवेश्वर भारती का दावा है कि असल जन्मस्थल कर्नाटक के तटीय कस्बे गोकर्ण का कडल बीच है.

विवाद देखते हुए टीटीडी अब जुटाए साक्ष्यों की किताब प्रकाशित करने की योजना बना रहा हैं. टीटीडी के श्री वेंकटेश्वर हायर वैदिक स्टडीज के परियोजना निदेशक और आंजनेय जन्मभूमि समिति के समन्वयक अकेल्ला विभीषण शर्मा कहते हैं, ''तिरुमला हिंदू धर्म का मुख्य स्रोत है. हमारा कर्तव्य है कि हम शंकाएं दूर करें और हनुमान जन्मभूमि से जुड़े तथ्यों को स्थापित करें.'' ■

देबज्योति चक्रवर्ती

बंगाल की जंग

अकेली योद्धा

रोमिता दत्ता

पार्क स्ट्रीट के सामने मेयो रोड पर प्रसिद्ध गांधी प्रतिमा कोलकाता में विरोध दर्ज करने का राजनैतिक दलों और सामान्य नागरिक समूहों के पसंदीदा स्थलों में एक है. पिछले 13 अप्रैल को ममता बनर्जी भी चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए वहीं पहुंचीं. न कोई नारेबाजी, न नाफरमानी का कोई ऐलान, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बस चुपचाप मूर्ति के नीचे बैठी रहीं और पेंटिंग करने में खोई रहीं. समर्थन में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेताओं ने थोड़ी दूरी पर डेरा डाल रखा था.

एक दिन पहले चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए ममता के प्रचार करने पर 24 घंटे की रोक लगा दी थी, तो उन्होंने उसे ''अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक'' बताते हुए ट्विटर पर तीखा विरोध जताया था. लेकिन गांधी प्रतिमा के पास वे संयम की प्रतिमूर्ति बनी रहीं. चुनाव आयोग ने प्रतिबंध ममता के कथित दो बयानों के कारण लगाया था. कथित तौर पर 5 अप्रैल को ताड़केश्वर में एक समुदाय विशेष को संबोधित करने वाले बयान के लिए और 8 अप्रैल को कूचबिहार में महिलाओं से यह अपील की कि 'जरूरत पड़ने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों का घेराव करें.' इस चुनाव में आयोग के साथ ममता की यह पहली भिड़ंत नहीं थी. इसके पहले चुनाव आयोग ने नंदीग्राम के बोयाल मतदान केंद्र में गड़बड़ियों के उनके आरोपों को मानने से इनकार कर दिया था, जहां वे अपने पूर्व सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव में खड़ी हैं.

सोची-समझी रणनीति

ममता के गुस्से को बंगाल भाजपा नेताओं दिलीप घोष, राहुल सिन्हा और सायंतन बसु के कथित रूप से भड़काऊ भाषणों पर चुनाव आयोग की आरंभिक निष्क्रियता ने भी हवा दी थी. कोलकाता के प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय के समाजशास्त्री प्रशांत रॉय के अनुसार गांधी प्रतिमा के नीचे ममता का धरना एक सोची-समझी रणनीति थी. वे कहते हैं, ''यह उनके जुझारूपन और चुनाव आयोग तथा सीआरपीएफ जैसी संस्थाओं पर हमलों के कारण पैदा हुई नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास था. उनके प्रशंसकों में इससे सहानुभूति पैदा होगी कि कैसे वे लगभग अकेले ही भाजपा से लड़ रही हैं. अकेली योद्धा की यह छवि ममता को महिला मतदाताओं के और करीब ले जाने में मदद करती है.''

जया बच्चन जैसी सांसद का समर्थन भी ममता की 'अकेली योद्धा' वाली छवि में काम आया. इस महीने की शुरुआत में कोलकाता में टीएमसी के लिए प्रचार करने की अपनी योजना की

विरोध का अंदाज चुनाव आयोग की 24 घंटे की पाबंदी के खिलाफ कोलकाता में धरने पर बैठीं ममता बनर्जी

घोषणा करते हुए समाजवादी पार्टी की सांसद ने कहा था, ''अनेक अत्याचारों के खिलाफ लड़ रही अकेली महिला के लिए मेरे मन में अत्यंत सम्मान है. ममता जी पर कितने तरह के अत्याचार किए गए.'' बाद में जया बच्चन कोलकाता के रोड शो के दौरान व्हीलचेयर पर सवार ममता को गले से लगाया और मानो टीएमसी के नारे 'बांग्ला निजेर मेये के चाई (बंगाल अपनी बेटी को चाहता है)' को सार्थक बना दिया.

इससे पहले, टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने मार्च में नंदीग्राम में कथित हमले में ममता के पैर में लगी चोट को भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी राजनीतिक जमीन पर खड़े रहने के संघर्ष का प्रतीक बताया था.

महिलाओं को लुभाना

तृणमूल कांग्रेस भाजपा को निपट पुरुषवादी मानसिकता का साबित करने का कोई मौका जाया नहीं जाने देती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में 'दीदी-ओ-दीदी' जैसी टिप्पणी की, तो तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा बिफर पड़ीं. मोइत्रा ने एक टीवी चैनल से कहा, ''ये प्रधानमंत्री हैं जो मौजूदा महिला मुख्यमंत्री से ऐसी घटिया किस्म की चुहलबाजी कर रहे हैं.'' इसके बाद महिला और बाल विकास मंत्री शशि पांजा ने मोदी के तंज को 'राज्य की महिलाओं का अपमान' करार दिया था.

ममता की पार्टी भाजपा को वार करने का कोई मौका जाया नहीं जाने दे रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'दीदी ओ दीदी' टिप्पणी पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तीखा प्रहार किया

बंगाल की 10 करोड़ आबादी में लगभग आधी महिलाएं हैं जो ममता सरकार के 12,000 करोड़ रुपए के कल्याण पैकेज की प्रमुख लाभार्थी हैं. इस पैकेज में लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और लड़कियों के विवाह के लिए अनुदान शामिल है. स्त्री-पुरुष समानता को मुद्दा बनाने के लिए 'स्वास्थ्य साथी' कार्ड परिवारों की महिला प्रमुख के नाम पर जारी किए जाते हैं. इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस भाजपा-शासित राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं का भी धड़ल्ले से हवाला दे रही है; उदाहरण के लिए, पिछले सितंबर में उत्तर प्रदेश का हाथरस बलात्कार कांड.

टीएमसी भले ममता पर अभद्र हमलों के लिए भाजपा पर निशाना साध रही हो लेकिन विपक्षी दल इस खुली जंग में लगातार नई युक्तियां तलाश रहा है. हाल ही में उसने ममता और टीएमसी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के बीच कथित बातचीत के अंश सार्वजनिक किए हैं. भाजपा ने इस क्रम में पहली ऑडियो क्लिप नंदीग्राम में 1 अप्रैल को मतदान से कुछ दिन पहले जारी की थी जिसमें कथित तौर पर ममता भाजपा में चले गए अपने पूर्व कार्यकर्ता प्रलय पाल से मदद मांग रही थीं. एक अन्य क्लिप में ममता कथित तौर पर शीतलकुची के टीएमसी उम्मीदवार पार्थ प्रतिम रॉय को निर्देश दे रही हैं कि वे 10 अप्रैल को सीआइएसएफ की गोलीबारी में चार लोगों की मौत के मामले को तूल दें. दिलचस्प बात यह है कि टीएमसी ने इन ऑडियो क्लिपों को फर्जी नहीं बताया है. बल्कि, ममता ने भाजपा पर अपनी जासूसी करने और गोपनीयता भंग करने की निंदा की है. ममता ने कहा, ''वे हमारी रोजमर्रा की बातचीत चोरी से सुन रहे हैं और हमारे फोन की टैपिंग कर रहे हैं. मैं इस मामले में सीआइडी जांच का आदेश दूंगी और इसमें शामिल किसी को भी नहीं बख्शूंगी.''

भारी-भरकम भाजपा

पैसे या धनशक्ति के मामले में ममता की पार्टी भाजपा की चुनावी मशीनरी का शायद ही मुकाबला कर सके. केंद्रीय मंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री और सांसद एक दिन में 10-12 रैलियां कर रहे हैं, तब टीएमसी की एकमात्र स्टार प्रचारक ममता तीन या चार कार्यक्रमों में पहुंच पाती हैं. उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी एक दिन में दो से तीन रैलियों को संबोधित कर रहे हैं. ममता को स्टार प्रचारकों की कमी महसूस होती है. टीएमसी के पूर्व मंत्री पूर्णेंदु बोस ने कहा, ''दीदी पैर में चोट खाने के चार दिन बाद ही वापस चुनाव प्रचार लग गई थीं क्योंकि उन्हें लगा कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई में एक भी दिन बर्बाद नहीं किया जा सकता.''

भाजपा की रणनीति रही है कि वह ममता की हर रैली की जवाबी रैली करके टीएमसी को संचार साधनों में ज्यादा जगह पाने से रोके. ममता ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं कि क्या प्रधानमंत्री को बंगाल में मतदान के दिन प्रचार करने और कैबिनेट बैठकों में लिए गए फैसलों की जानकारी सार्वजनिक करने की अनुमति दी जा सकती है. हुगली जिले में 3 अप्रैल को, मोदी ने बंगाल के लगभग 70 लाख किसानों को आश्वासन दिया था कि अगर भाजपा सत्ता में आई, तो उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18,000 रुपए की बकाया राशि मिलेगी.

मोदी और शाह यह मानकर चल रहे हैं कि ममता का शासनकाल समाप्त हो गया है. पिछले 1 अप्रैल को मोदी ने दक्षिण 24-परगना में टिप्पणी की कि ममता की शारीरिक भाषा से पता चलता है कि उन्होंने अपनी आसन्न हार को महसूस कर लिया है. कलकत्ता विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर शोभनलाल दत्त गुप्ता कहते हैं, ''राजनीति का सारा संबंध धारणाओं से है और भाजपा ऐसी धारणा का निर्माण कर रही है कि वह पूरी ताकत से बंगाल में सत्ता में आने वाली है. इससे विशेष रूप से अनिर्णय में पड़े मतदाताओं को लुभाने में मदद मिलती है. भाजपा ऐसे मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है.''

दीदी भाजपा को बंगाल की सत्ता में आने के लिए अयोग्य करार देने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. इस क्रम में वे भाजपा-शासित त्रिपुरा में कुशासन का उल्लेख करने से लेकर गुजरात दंगों की चर्चा, महिलाओं की सुरक्षा का मामला, मुसलमानों के लिए एनआरसी (नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर) और सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) लागू होने के खतरे, या फिर बंगाल के 'बंगालियाने' पर 'सांस्कृतिक हमले' के खतरे तक सभी का जिक्र कर रही हैं.

रॉय का कहना है, ''ममता भावनाएं कुरेदते हुए अंतिम प्रयास कर रही हैं. भाजपा के 'डबल-इंजन' सरकार के वादे के मुकाबले वे टीएमसी के सत्ता में वापस आने पर समाज कल्याण योजनाओं का आश्वासन दे रही हैं.'' टीएमसी की अंतिम बात यह है कि बंगाल के लोगों को अपनी 'पहरेदार दीदी' और भाजपा की 'दादागीरी (गुंडागर्दी)' के बीच चुनाव करना है. जो भी हो मतगणना दिवस (2 मई) भी अब नजदीक आता जा रहा है. बेशक, दांव ऊंचे हैं मगर दीदी का हर दांव भाजपा पर फिलहाल भारी दिखता है. ■

कुंभ मेला

कोरोना का ग्रहण भारी

अनिलेश एस. महाजन और अखिलेश पांडेय

इस साल कुंभ में 21 अप्रैल को रामनवमी के पर्व स्नान पर भी महज 82 हजार लोगों ने गंगा स्नान किया. यह संख्या पिछले वर्षों के सामान्य स्नान की तुलना में भी काफी कम थी. हरिद्वार में पिछले कुंभ में पर्व स्नान पर करीब 10 लाख लोगों ने डुबकी लगाई थी. इस बार कोविड ने ऐसा आतंक बरपाया है कि 27 अप्रैल को आखिरी शाही स्नान के पहले ही घाटों पर भीड़ छंटने लगी है. कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों से कई अखाड़ों के अधिकांश संत हरिद्वार से विदा हो चुके हैं. मसलन, जिन 13 अखाड़ों के लिए आखिरी शाही स्नान का विशेष महत्व है, उनमें बस सात ही अखाड़े हरिद्वार में रह गए हैं.

18 अप्रैल तक विभिन्न आश्रमों के 80 संत कोविड पॉजिटिव पाए गए. 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर वामी कपिल देव कोविड की वजह से स्वर्ग सिधार गए. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है. विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार भी पॉजिटिव पाए गए. 11 मार्च को महाशिवरात्रि से 20 अप्रैल तक हरिद्वार में 8,251 लोग कोरोनावायरस संक्रमण से ग्रस्त पाए गए.

हालांकि, कोविड-19 बढ़ते प्रकोप से अखाड़ों का विवाद नहीं निबटा. कुंभ के समापन को लेकर अखाड़े बंट गए हैं. कोविड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर तीन शाही स्नान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को प्रतीकात्मक रूप से आयोजित करने की अपील की थी. उसके बाद सबसे बड़े जूना

रामेश्वर गौड़

अखाड़े और कुछ सहयोगी अखाड़ों ने कुंभ समाप्ति की घोषणा की और देवताओं को विसर्जित कर अपने कैंप खाली कर दिए. लेकिन निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़ों के संतों ने बैरागी कैंप में बैठक कर निर्णय लिया कि हरिद्वार महाकुंभ मेला प्रतीकात्मक नहीं हो सकता. वे अब भी 27 अप्रैल को होने वाले चौथे शाही स्नान को प्रत्यक्ष रूप से करने पर डटे हैं. निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष श्रीमहंत राजेंद्र दास कहते हैं, ''केंद्र और राज्य सरकारों के जो भी दिशानिर्देश होंगे, उनका पालन जरूर होगा.'' निर्वाणी अखाड़े के अध्यक्ष महंत धर्मदास के मुताबिक, प्रतीकात्मक कुछ नहीं होता. कुंभ में देवी, देवता, मां गंगा प्रत्यक्ष रहती हैं, इसलिए बैरागी अखाड़े प्रत्यक्ष शाही स्नान करेंगे. जूना अखाड़ा और उसके सहयोगी अग्नि और आह्वान अखाड़ों की ओर से देवता विसर्जित कर कुंभ समापन की घोषणा किए जाने से नाराज शंकराचार्य परिषद के सर्वपति शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि कुंभ समाप्त करने वाले साधु-संत शास्त्र नहीं जानते, वे कालनेमि के समान हैं. कुंभ एक नियत तिथि से शुरू होकर नियत तिथि पर ही समाप्त होता है. यह किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर शुरू या समाप्त नहीं होता. उनका कहना है कि जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर को कोई हक नहीं है कि वे कुंभ समाप्ति की घोषणा करें. वे आगे कहते हैं, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर हुई वार्ता के बाद आचार्य महामंडलेश्वर इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने कुंभ स्नान को प्रतीकात्मक रूप से किए जाने के सुझाव पर कुंभ समाप्ति की घोषणा ही कर दी जबकि इसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आचार्य महामंडलेश्वर का कोई पद नहीं होता है. केवल शंकराचार्य की अनुपस्थिति के कारण ही यह पद तत्कालीन व्यवस्था के तहत बनाया गया था. इसका अब कोई औचित्य है ही नहीं.''

उन्होंने कहा कि संतों को नेताओं की चाटुकारिता बंद करनी चाहिए. कुंभ के संबंध में अगर किसी को कुछ करने का अधिकार है तो वह केवल शंकराचार्य को है. महाकुंभ के आखिरी शाही स्नान से पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं. श्रीमहंत राजेंद्र दास और वैष्णव संप्रदाय के संतों ने सरकार से संन्यासी अखाड़ों के शाही स्नान करने पर रोक लगाने की मांग कर दी है. राजेंद्र दास का कहना है कि संन्यासी अखाड़ों ने कुंभ मेले से पहले ही मेला विसर्जन कर दिया है. अब उनके शाही स्नान करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है.

कोरोना प्रकोप फैला
12 अप्रैल को हरिद्वार के घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़

कोरोना का कहर

लेकिन इस विवाद से अलग, कोरोना का कहर बरपा रहा है. कुंभ के दौरान कई अखाड़ों के साधु-संतों में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलने से मेला प्रशासन में भी हड़कंप मच हुआ. हरिद्वार में मंगलवार 20 अप्रैल को कुल 609 नए कोरोना पॉजिटिव मिले. हरिद्वार में मिले 609 मामलों में से 79 लोग बाहरी राज्यों के हैं. इनके अलावा पंचायती अखाड़ा, शंभू पंचायती अटल अखाड़ा और शांति कुंज में भी कोरोना के कई केस मिले हैं. जिला स्वास्थ्य

कोरोना का खौफ कुंभ में इस कदर व्याप्त हो गया है कि दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने महाकुंभ से लौटने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोविड की आरटी पीसीआर जांच और होम आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया है

विभाग के आंकड़ों के अनुसार, हरिद्वार में कोविड संक्रमण फैलने की असली वजह बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालु हैं. उन्हीं की वजह से कोविड का प्रसार हुआ है. इनमें हरिद्वार जिले के एक्टिव केस मात्र 28.12 फीसदी है जबकि 71.88 फीसदी मरीज बाहरी राज्यों के हैं. हरिद्वार महाकुंभ में 11 से 14 अप्रैल तक लगातार तीन बड़े स्नान हुए. इनमें 49 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई. इनमें कोविड संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के श्रद्धालु बड़ी तादाद में शामिल थे.

11 अप्रैल से पहले जिले में औसतन 150 से 200 संक्रमित मिल रहे थे. 10 अप्रैल को 217 संक्रमित थे, लेकिन 11 अप्रैल को इनकी संख्या बढ़कर 372 हो गई.12 अप्रैल के शाही स्नान के अगले दिन संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 843 पहुंच गया. 10 से 19 अप्रैल तक जिले में कुल 5,909 संक्रमित मिले हैं. इनमें सीमा, मेला क्षेत्र और जिले की सभी तहसील क्षेत्रों की जांच शामिल हैं.

हरिद्वार के सीएमओ डॉ. एस.के. झा के अनुसार, बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालुओं की भीड़ के बाद संक्रमण अचानक तेज हुआ है. महामंडलेश्वर कपिल देव दास की कोरोना से मौत के बाद अखाड़ों की छावनियों में रैंडम कोविड सैंपलिंग के लिए टीमें गठित की गईं. अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरि गिरि महाराज सहित सभी प्रमुख संतों के जूना अखाड़े में सैंपल लिए गए, सैंपल देने वाले संतों से रिपोर्ट आने तक आइसोलेट रहने के लिए कहा गया. कुंभ मेला आईजी संजय गुंज्याल का दावा था कि मेला क्षेत्र की सीमाओं पर श्रद्धालुओं के कोविड सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है. कोविड-19 टेस्ट का नेगेटिव सर्टिफिकेट न होने पर एक अप्रैल से 14 अप्रैल तक 56,000 श्रद्धालुओं को सीमा से ही वापस लौटाया गया. हालांकि यह काम इतना आसान नहीं है.

राज्य ने पहले ऐलान किया था कि श्रद्धालुओं के हरिद्वार में प्रवेश के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट और मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है, लेकिन मेला को देखकर लगता है कि यह नियम बस कागज पर शोभा पाता है.

दूसरी समस्या यह है कि मेले से जो लोग अपने इलाकों और लोगों के बीच लौट रहे हैं, वे कोरोना का प्रकोप फैलाने का बड़ा कारण बन रहे हैं. यह कोविड के देश भर में प्रसार की बड़ी वजह बन रहा है. मध्य अप्रैल में संक्रमण के मामले 1.4 करोड़ तक पहुंच चुका है. 17 अप्रैल को 2,50,000 नए मामले मिले. ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे कई राज्यों ने लौटते श्रद्धालुओं की टेस्टिंग और क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है. लेकिन संख्या बड़ी भारी है इसलिए न दूसरे राज्यों के लिए इतना आसान है, न उत्तराखंड के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट करना. ऐसे आयोजन में कोरोना फैलने की काफी आशंका के बाद प्रधानमंत्री को प्रतीकात्मक कुंभ की बात याद आई.

बहरहाल, जो होना था, वह तो हो चुका है. मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि स्नान के दिन कोविड-प्रोटोकॉल का पालन करवाना मुसीबत को न्योता देना हो सकता था इसलिए जिन दिनों स्नान नहीं थे, उन दिनों घाटों पर चेकिंग की गई. ■

स्मृति

नरेंद्र कोहली 1940-2021

पौराणिक को आधुनिक बनाया उन्होंने

इन दिनों किसी व्यक्ति के जाने पर लिखना जैसे लिखना नहीं रहा. उसे दुबारा पढ़ना हो गया है. अवाक्, स्तब्ध, क्षुब्ध, दुखी, प्रार्थनारत या स्मृतिबद्ध जैसे शब्द यकायक पट्टियों में बदल गए हैं जिन्हें आप हर सूचना के बाद क्रम से रखते जाते हैं. जब सूचनाओं की मार से कुछ उबरते हैं तो पलटकर तमाम प्रसंगों की नब्ज टटोलने लगते हैं.

नरेंद्र कोहली उस कोरोना-कालखंड में गए हैं जो स्वयं फिलहाल जाने से इंकार कर रहा है. वे उस वक्त में भी गए हैं जबकि उनके लेखन-जीवन के नए प्रशंसक-संसार ने समकालीन राजनीतिक प्रासंगिकता को संबोधित करना शुरू ही किया था.

कोहली, 'कहानी' काल के थे. जिन्हें भीष्म साहनी और अमृत राय संपादित नई कहानियां याद हों, वे पाएंगे कि उन पन्नों पर पहले जमशेदपुर और फिर दिल्ली से नरेंद्र कोहली का पता मिलता है. 1966 में वे 'सार्थकता' जैसा डार्क ह्यूमर लिख रहे थे. एक चौकीदार, महिला का अंतर्वस्त्र लिए लिए फ्लैट-दर-फ्लैट घूम रहा है—ये आपका है? 1967 में *कगार का निषेध* की पारिवारिकता और 1971 में *हलवाई की शरारत* का हल्का-फुल्का आनंद उनकी आरंभिक दुनिया को समझने के लिए काफी हैं. वे व्यंग्य कथाओं के करुण हस्ताक्षर उठाते थे. *शम्बूक का वध*' और *आश्रितों के विद्रोह* के साथ *पांच एब्सर्ड उपन्यास* या *एक और लाल तिकोन* तक वे सामाजिक अंतर्विरोधों से भावुक सच्चाइयों को अलग करते हुए पहुंचे तो उनका लक्ष्य स्पष्ट हो चुका था. वे उस दिशा में जा रहे थे जहां उन्हें स्वाभाविक विश्राम मिलता और वे अपने उद्वेग को संपूर्ण रचनात्मक वेग में बदल पाते.

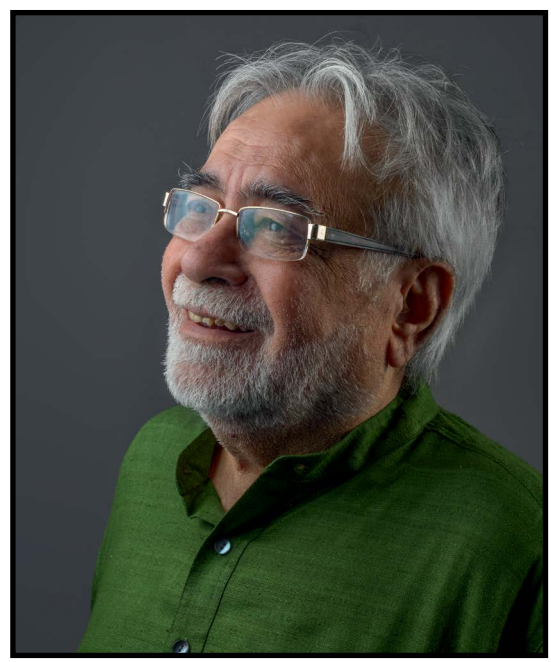

शेखर घोष

वे 'वाम' से 'राम' की तरफ मुड़े.

मुख्यधारा का साहित्य प्रगतिशील आलोचनाओं के ठाठ से अभिषिक्त होता है. और, उनकी *दीक्षा* में क्या था? खुद कोहली ने एक जगह कहा है, ''एक ओर वे लोग थे जो यह कह रहे थे कि यह सामंती, साम्राज्यवादी, पुरानी मान्यताओं को स्थापित करने वाला लेखक है, इसलिए प्रगतिशील नहीं है. दूसरी तरफ वे लोग थे, जो यह कह रहे थे कि यह तो कम्युनिस्ट रामायण हो गई, इसमें तो आज के सारे सिद्धांत आ गए. क्या व्यक्ति का विकास नहीं होता? एक वह समय था, जब मैं प्रगतिशील लेखक संघ का उपाध्यक्ष था, एक समय वह था जब मैं सीपीएम के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगता फिरता था. लेकिन अब मैं दूसरी तरह का व्यक्ति हूं और मुझे लगता है कि मेरी अपनी स्वाभाविक दिशा यही थी और है.''

इस तरह पारिवारिक करुणा, पीड़ा और डार्क ह्यूमर का रचनाकार अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए पुराकथाओं के रहस्यवाद में उतर गया. उन्हें एहसास हुआ कि ठेठ भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में उतरे बिना वैचारिक अधिष्ठान संभव नहीं है. बाबा नागार्जुन में सुदामा की झलक देखने से शुरू *अभिज्ञान,* कृष्ण-कथा के वैभव में उतर गया. उन्होंने रामकथा के बाद *महाभारत* पकड़ी और *महासमर* में आध्यात्मिकता को ज्याद गहरा पाया. आखिर, विवेकानंद तक पहुंचे.

देखना दिलचस्प है कि कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की *वंशी की धुन* इसकी पूर्ववर्ती है और हाल का समकाल देवदत्त पटनायक की पॉप-व्याख्याओं और अमीश त्रिपाठी के जनरेशन-जेड के *वारियर ऑफ मिथिला* से आक्रांत है. धर्म को डिकोड किया जा रहा है. पुनर्व्याख्याओं का दौर है. विवेकानंद जैसे चरित्र फिर लोकप्रिय विमर्श के केंद्र में हैं. सत्ता और राष्ट्रवाद के अंतर्संबंधों की फिर से पड़ताल हो रही है. कुछ खोए हुए शब्द फिर से सतह पर हैं, कुछ दबे हुए संदर्भ अपनी ही शक्ति से पुनर्जीवन पा रहे हैं. ऐसे समय में नरेंद्र कोहली सहज ही प्रतिधारा के प्रिय संबोधन बन गए हैं.

उनकी लोकप्रियता और मुख्यधारा की स्वीकार्यता के बीच स्वाभाविक द्वंद्व था. जाहिर है इसके पीछे के कथित 'वैचारिक शत्रुत्व' को वे न सिर्फ रेखांकित करते थे बल्कि उन्होंने समय-समय पर अपने प्रत्याख्यान को शब्द भी दिए.

उन्होंने हमेशा डूबकर लिखा. लिखने के प्रति जुनून के चलते नियमित प्राध्यापकी छोड़ी. वे लक्ष्य के प्रति निर्ममता की हद तक समर्पित थे. उनके व्यक्तिगत जीवन में हर धारा के मित्र थे. शिष्य मंडली में भांति-भांति के लोग थे.

और, खुद उनके शब्दों में, कई ऐसे थे जो उन्हें बेहद प्रेम करते थे, घर आते थे लेकिन 'वैचारिक शत्रुओं के साथ' होने से सार्वजनिक मंच साझा करने से भी बचते थे.

लेकिन, क्या इसमें कोई संदेह है कि 'पौराणिक आधुनिकतावाद' के उनके विपुल रचना संसार का एक विशाल पाठक वर्ग उनके साथ हमेशा अपना अंतर साझा करने के लिए खड़ा रहेगा?

यशवंत व्यास *चर्चित लेखक और व्यंग्यकार हैं*

आज तक

देश का नं. 1 हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है

अर्थात्

जवाबदेही का बही-खाता

अंशुमान तिवारी

भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी गई गुजरी है कि इसे राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ के काबिल भी नहीं समझा जाता. इसकी अहमियत सरकारी मेलों और तीर्थ यात्राओं जितनी भी नहीं है. यह बात 2018 में एक बड़े अफसर ने कही थी जो सेहत का महकमा संभाल चुके थे और स्वाइन फ्लू की तबाही से लड़ रहे थे.

सरकारें हमें कभी अपने दायित्व नहीं बतातीं, वे तो केवल श्रेय के ढोल पीटती हैं और बहुतेरे उन पर नाच उठते हैं. तबाही, हाहाकार और मौतों के बाद ही ये जाहिर होता है कि जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को लेकर योजनाबद्ध और नीतिगत गफलत हमेशा बनाए रखी जाती है.

हमें आश्चर्य होना चाहिए कि महामारी की पहली लहर में जहां छोटे-छोटे बदलावों के आदेश भी दिल्ली से जारी हो रहे थे वहीं, ज्यादा भयानक दूसरी लहर के दौरान राज्यों को उनकी जिम्मेदारियां गिनाई जाने लगीं. जबकि पहली से दूसरी लहर के बीच कानूनी तौर पर कुछ नहीं बदला.

बीते साल कोविड की शुरुआत के बाद केंद्र ने महामारी एक्ट 1897/अध्यादेश 2020) और आपदा प्रबंधन कानून 2005 का इस्तेमाल किया था. इन दोनों केंद्रीय कानूनों के साथ संविधान का अनुच्छेद 256 अमल में आ गया और राज्यों के अधिकार सीमित हो गए. इन्हीं कानूनों के तहत बीते बरस लॉकडाउन लगाया, बढ़ाया, हटाया गया और असंख्य नियम (केंद्र के 987 आदेश) तय हुए जिन्हें राज्यों ने एक साथ लागू किया. यह स्थिति आज तक कायम है.

अब जबकि भयानक विफलता के बीच बीमार व मरने वाले राजनीतिक सुविधा के मुताबिक राज्यों के तंबुओं में गिने जा रहे हैं तो यह सवाल सौ फीसदी मौजूं है कि अगर आपका कोई अपना ऑक्सीजन की कमी से तड़पकर मर गया या जांच, दवा, अस्तपाल नहीं मिला तो इसका दिल्ली जिम्मेदार है या सूबे का प्रशासन?

भारत में स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है लेकिन सेहत से जुड़ा प्रत्येक बड़ा फैसला केंद्र लेता है, स्वास्थ्य सेवाएं देना राज्यों की जिम्मेदारी लेकिन वह कैसे दी जाएंगी यह केंद्र तय करता है. बीमारी नियंत्रण की स्कीमों, दवा के लाइसेंस, कीमतें, तकनीक के पैमाने, आयात, निजी अस्पतालों का प्रमाणन, अनेक वैज्ञानिक मंजूरियां, ऑक्सीजन आदि के लिए लाइसेंस, वैक्सीन की स्वीकृतियां सभी केंद्र के पास हैं. तभी तो कोविड के दौरान जांच, इलाज से लेकर वैक्सीन तक प्रत्येक मंजूरी केंद्र से आई.

स्वास्थ्य पर कुल सरकारी खर्च का 70 फीसदी बोझ, राज्य उठाते हैं जो उनकी कमाई से बहुत कम है इसलिए केंद्र से उन्हें अनुदान (15वां वित्त आयोग-70,000 करोड़ रुपए पांच साल के लिए) और बीमारियों पर नियंत्रण के लिए बनी स्कीमों के माध्यम से पैसा मिलता है. इस सबके बावजूद भारत में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च जीडीपी का केवल 1.26% (प्रति व्यक्ति में श्रीलंका से कम) है.

हकीकत यह है कि अधिकांश लोगों की जिंदगी निजी स्वास्थ्य ढांचा ही बचाता है. हमें उसकी लागत उठानी होती है जो हम उठा ही रहे हैं. नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के मुताबिक, भारत में स्वास्थ्य पर 70 फीसदी खर्च निजी (अस्पताल, उपकरण, दवा, जांच) क्षेत्र से आता है. केंद्र और राज्य केवल टैक्स वसूलते हैं. सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हेल्थ ब्यूरोक्रेसी को पालने के लिए चलती हैं. सरकारें भी चाहती हैं कि कम से कम लोग उनसे सस्ता इलाज मांगने आएं.

सरकारें बहुत कुछ कर नहीं सकती थीं, सिवाय इसके कि भारी टैक्स निचोड़ कर फूल रहा हमारा निजाम आंकड़ों और सूचनाओं की मदद से कम से कम निजी क्षेत्र के जरिए ऑक्सीजन, दवा, बेड की सही जगह, समय और सही कीमत पर आपूर्ति की अग्रिम योजना बना लेता और हम बच जाते. इनसे इतना भी नहीं हुआ. लोग क्षमताओं की कमी से नहीं सरकारों के दंभ और लापरवाही से मर रहे हैं.

अगर नसीहतें ली जानी होतीं तो कोविड के बीच बीते बरस ही 15वें वित्त आयोग ने सुझाया था कि स्वास्थ्य को लेकर समवर्ती सूची में नए विषय (अभी केवल मेडिकल शिक्षा और परिवार नियोजन) जोड़े जाने चाहिए ताकि राज्यों को अधिकार मिलें और वे फैसले लेने की क्षमताएं बना सकें. 2017 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जन स्वास्थ्य (महामारी प्रबंधन) अधिनियम का एक प्रारूप बनाया था, जिसमें केंद्र और राज्य की जिम्मेदारियां तय करने के प्रावधान थे. पता नहीं किस वजह से इसको फाइलों में हमेशा के लिए सुला दिया गया.

हम ऐसी सरकारों के दौर में है जो दम तोड़ती व्यवस्था से कहीं ज्यादा बुरे प्रचार से डरती हैं. श्मशानों पर भीड़, ऑक्सीजन की कमी से तड़पते लोग, ट्विटर पर जांच और दवा के लिए गिड़गिड़ाते संदेश-प्रचार संसार के लिए मुसीबत हैं इसलिए तोहमतें बांटने का प्रचार तंत्र सक्रिय हो गया है.

पश्चिम की तुलना में पूरब का सबसे बड़ा फर्क यह है कि यहां के राजनेता गलतियां स्वीकार नहीं करते, नतीजतन पहले चरण में डेढ़ लाख मौतों के बाद भी कुछ नहीं बदला. अब हम भारतीय राजनीति के सबसे वीभत्स चेहरे से मुखातिब हैं जहां महामारी और गरीबी के महाप्रवास के बीच असफल सरकारों ने हमें राज्यों के नागरिकों में बदलकर एड़ियां रगड़ते हुए मरने को छोड़ दिया है.

@anshuman1tiwari

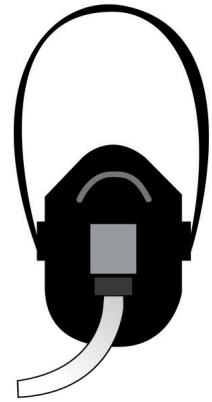

हम ऐसी सरकारों के दौर में हैं जो दम तोड़ती व्यवस्था से कहीं ज्यादा बुरे प्रचार से डरती हैं

इलस्ट्रेशनः असित रॉय

INDIA TODAY

HIDDEN STORIES SURFACE

ONLY ON GROUND ZERO

Get all sides of the elections

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

दूसरी लहर खौफनाक कहर और बचाव

कोरोना वायरस के ज्यादा संक्रामक रूप में लौटने के साथ चौतरफा घिरा देश चुनौतियों से निपटने और किसी तरह लड़ाई जारी रखने में जुटा

सोनाली अचार्जी; साथ में ब्यूरो रिपोर्टें

लखनऊ के गोमतीनगर के बाशिंदे पूर्व जिला जज रमेश चंद्रा और उनकी पत्नी मधु ने 13 अप्रैल को बुखार और गले में तकलीफ महसूस की. फटाफट कोविड-19 टेस्ट करवाए. दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई. अगले दो दिनों में जब मधु की हालत बिगड़ गई तो पूर्व जज ने शहर के अस्पतालों को एंबुलेंस के लिए ताबड़तोड़ फोन किए. एंबुलेंस नहीं आई तो उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट और मुख्यमंत्री दफ्तर के अफसरों को भी फोन करके गुहार लगाई. कोई नतीजा नहीं निकला. उनकी पत्नी 15 अप्रैल को परलोक सिधार गईं. मगर उनकी मुश्किल घड़ी का यहीं अंत नहीं हुआ. पत्नी की देह को शमशान ले जाने के लिए शववाहन के इंतजाम में चंद्रा को जमीन-आसमान एक करने पड़े. रोते हुए चंद्रा कहते हैं कि चार घंटे तक ऊंचे पदों पर बैठे अपने दोस्तों को फोन करता रहा और तब कहीं जाकर एक गाड़ी भेजी गई जिससे वे उनका अंतिम संस्कार कर सके.

स्वास्थ्य सेवा ढांचे के ढह जाने के इस दु:स्वप्न से गुजरने वाले चंद्रा अकेले नहीं हैं. और यह सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, देश के हर मेट्रो, हर शहर, कस्बे में कोविड-19 के संक्रमण की दूसरी दानवी लहर के प्रकोप के आगे चिकित्सा ढांचे के ध्वस्त होने का कहर बरपा है. वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि 18 अप्रैल को खत्म सप्ताह में औसतन रोज 2,60,000 लोग संक्रमित हो रहे थे, जो सितंबर 2020 में कोविड की पहली लहर के शिखर की तुलना में 2.5 गुना थे. बदतर यह कि इसके घटने के आसार दिखाई नहीं देते. सक्रिय मामलों के दोगुने होने की दर पहली लहर की चोटी के करीब 49 दिनों के मुकाबले 11 दिन है, जो बेहद चिंताजनक है. महामारी के तेज ज्वार को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जहां पांच फीसद से कम टेस्ट पॉजिटिव दर की सिफारिश करता है, वहीं हमारा राष्ट्रीय औसत 13.5 फीसद है और 20 अप्रैल को दिल्ली में यह खौफनाक हद तक 33 फीसद था. हमारे अस्सी फीसद सक्रिय मामले 10 राज्यों में हैं (*देखें साथ की रिपोर्ट दहशत और नाउम्मीदी*)—महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान—जहां इलाज की मांग चिकित्सा व्यवस्था पर भारी पड़ रही है.

कोई शक नहीं कि देश केंद्र और राज्य सरकारों की लापरवाही की भारी कीमत चुका रहा है. सरकार ने इस साल की शुरुआत में कोविड पर बेमौके फतह का ऐलान करके कोविड-19 पर नियंत्रण और रोकथाम के उपायों में कटौती करना शुरू कर दिया. इसने लोगों को भी इस हद तक गुमराह कर दिया कि उन्होंने कोविड के मुआफिक बर्तावों को घूरे के ढेर में डाल दिया, मास्क को तिलांजलि दे दी और हरिद्वार के कुंभ मेले और

अमित दवे/रॉयटर्स

अहमदाबाद के एक अस्पताल के बाहर एंबुलेंस में मरीज का ऑक्सीजन मास्क ठीक करता स्वास्थ्यकर्मी

विधानसभा चुनाव से गुजर रहे पांच राज्यों की चुनाव रैलियों सरीखे भीड़ भरे आयोजनों में हिस्सा लेने लगे. दिल्ली के आइसीजीईबी (इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐंड बॉयोटेक्नोलॉजी) के डायरेक्टर डॉ. वीरेंदर सिंह चौहान कहते हैं, ''एक अरब लोगों के देश से महामारी इतनी तेजी से रुखसत नहीं हो सकती. अगर हम सावधान न रहें तो दूसरी लहर की आशंका हमेशा होती है. हम खुशकिस्मत थे कि 3-4 महीने शांति रही, हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए था.''

दूसरी लहर की चुनौतियां संक्रमणों की भारी-भरकम तादाद से निपटने तक सीमित नहीं हैं. वायरस के नए, ज्यादा संक्रामक रूपों और किस्म-किस्म के कई सारे लक्षणों को लेकर भी चिंता है. यही नहीं, जांच करने, पता लगाने, इलाज करने और टीके लगाने की भी जबरदस्त कमी है. लोगों में कोविड के मुआफिक बर्ताव सख्ती से लागू करने की तो बात ही छोड़ दें. बिल्कुल सामने खड़े मेडिकल संकट से निपटना बेशक पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन हमारे ऊपर तीसरी लहर के हमले को रोकने की खातिर अभी तक की गई भीषण गलतियों से सीखना और दोहराने से बचना भी मुफीद होगा.

अंधेरे में उड़ना बंद करें

विशेषज्ञों को पता था कि दूसरी लहर कहीं आसपास ही मंडरा रही है. आइसीएमआर (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद) के एक राष्ट्रीय सेरोलॉजिकल सर्वे (जो खून की जांच के जरिए एंटीबॉडी का पता लगाता है और किसी व्यक्ति के कोविड के संपर्क में आने का संकेत है) ने बताया कि दिसंबर 2020 तक 80 फीसद देश संक्रमित नहीं हुआ था. इसका मतलब था कि एक अरब लोग अब भी बीमार पड़ सकते थे. इसी के आसपास देश की अनेक वैज्ञानिक संस्थाएं कोविड के बदले हुए रूपों की इत्तला देने लगीं—ब्राजील का, दक्षिण अफ्रीका का, ब्रिटेन का और एक चौथा भारतीय स्ट्रेन (बी.1.167) जिसके दो बदले हुए रूप थे. इन तमाम रूपों में उनकी नोकदार प्रोटीन में रूपांतरण देखे गए जो मानव कोशिका से ज्यादा आसानी से जकड़े रहने में उनकी मदद करते थे और इसलिए ज्यादा संक्रामक थे. पिछले साल दोहरे रूपांतरण वाले भारतीय स्ट्रेन के संक्रमण का मुश्किल से ही कोई मामला था पर आज यह 10 राज्यों और अप्रैल की शुरुआत में महाराष्ट्र के 60 फीसद नमूनों में पाया जा सकता है. सीएसआइआर (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद) के डायरेक्टर अनुराग अग्रवाल कहते हैं कि अमेरिकी अध्ययनों से पता चला कि भारतीय स्ट्रेन का एल452आर रूपांतरण इसे 20 फीसद ज्यादा संक्रामक बनाता है. सीसीएमबी (सेंटर फॉर सेल्यूलर ऐंड मॉलीक्यूलर बॉयोलॉजी) के डायरेक्टर राकेश मिश्रा के अनुसार, ''इस बार यह ज्यादा संक्रामक कोविड है और जल्द ही हम इसे भारत में प्रबल रूप बनते देख सकते हैं.''

नए चिंताजनक रूपों के बारे में डब्ल्यूएचओ की वैश्विक चेतावनियों के बावजूद इस साल जनवरी में ही सरकार ने जीन सीक्वेसिंग की रफ्तार तेज करने के लिए 10 प्रयोगशालाओं का एक कंसोर्शियम बनाया, जिसे आइएनएसएसीओजी या इनसाकोग (इंडियन सार्सकोव2 जेनोमिक्स कंसोर्शियम) कहा गया. धीमी रफ्तार के लिए न केवल धनकी कमी बल्कि स्पष्ट दिशा की कमी को भी दोषी ठहराया जा सकता है. इंसाकोग को

11 दिन
की दर से संक्रमण के मामले फिलहाल दोगुने हो रहे हैं

49 दिन
की दर से संक्रमण के मामले दोगुने हो रहे थे सितंबर 2020 में

5 फीसद नमूनों का तैयार करने के लिए कहा गया है. फिलहाल दिन के 2,50,000 मामलों के हिसाब से इसका मतलब 12,500 नमूने होगा. भारत फिलहाल बामुश्किल 1 फीसद कर पा रहा है. जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और आइएमए (भारतीय चिकित्सा एसोसिएशन) के पूर्व चेयरमैन डॉ. के.के. अग्रवाल कहते हैं, ''हम देख सकते हैं कि न केवल वायरस इस बार ज्यादा फैला है बल्कि ऑक्सीजन की मांग भी ज्यादा है. नए रूपों के नैदानिक लक्षणों पर नजर रखे बगैर हम नई चुनौतियों के लिए तैयार नहीं हो सकते थे.'' सीसीएमबी के निदेशक राकेश मिश्रा जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर को रोकने के लिए भारत को देश भर में इन रूपों की प्रगति पर नजर रखनी चाहिए और किसी भी प्रकोप से निपटने के लिए मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के वाजिब कदम उठाने चाहिए.

तीसरी लहर की रोकथाम के लिए हमें देश में प्रचलित **म्यूटेंट स्ट्रेन** में आ रहे बदलावों पर **नजर** रखने की दरकार है

नए खतरे

आइसीएमआर अब इन भारतीय रूपों की ज्यादा नजदीक से निगरानी करने लगा है. अभी तक के राष्ट्रीय डेटा के आधार पर आइसीएमआर के प्रमुख डॉ. बलराम भार्गव कहते हैं कि मौतों के लिहाज से दूसरी लहर अब तक 'कम प्रचंड' मालूम देती है. इसकी 1.2 फीसद मृत्यु दर पहली के मुकाबले थोड़ी कम है. अलबत्ता कुल आंकड़ों की बात करें तो संक्रमणों की ज्यादा तादाद को देखते हुए मौतों की संख्या कहीं ज्यादा है. 20 अप्रैल को भारत में कोविड से 2,000 लोगों की जानें गईं, जो एक दिन में मौतों की सबसे ज्यादा तादाद थी.

यही नहीं, पहली लहर में जहां लोग सूखी खांसी, जोड़ों में तेज दर्द और सिरदर्द के लक्षण बता रहे थे, दूसरी लहर में सांस फूलने की ज्यादा शिकायत कर रहे हैं. इससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव आ गया है. आइसीएमआर की नेशनल क्लिनिकल कोविड-19 रजिस्ट्री बताती है कि पिछली बार के 41.7 फीसद के मुकाबले इस बार लक्षणों वाले 47.5 फीसद मरीज सांस फूलने की शिकायत कर रहे हैं. डॉ. भार्गव कहते हैं, ''इसका असर ऑक्सीजन की मांग पर पड़ा है और उसकी मांग अच्छी-खासी बढ़ गई है.'' सरकार की टास्क फोर्स की 19 अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक, देश भर के 40 केंद्रों के आंकड़ों के हिसाब से अस्पताल में भर्ती मरीजों की ऑक्सीजन की मांग इस बार 54.5 फीसद है, जो सितंबर 2020 में कोविड के शिखर की मांग से 13 फीसद अंक ज्यादा है. इससे देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी पैदा हुई है, जिसके चलते महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों ने तमाम बड़े अस्पतालों में

पंकज तिवारी

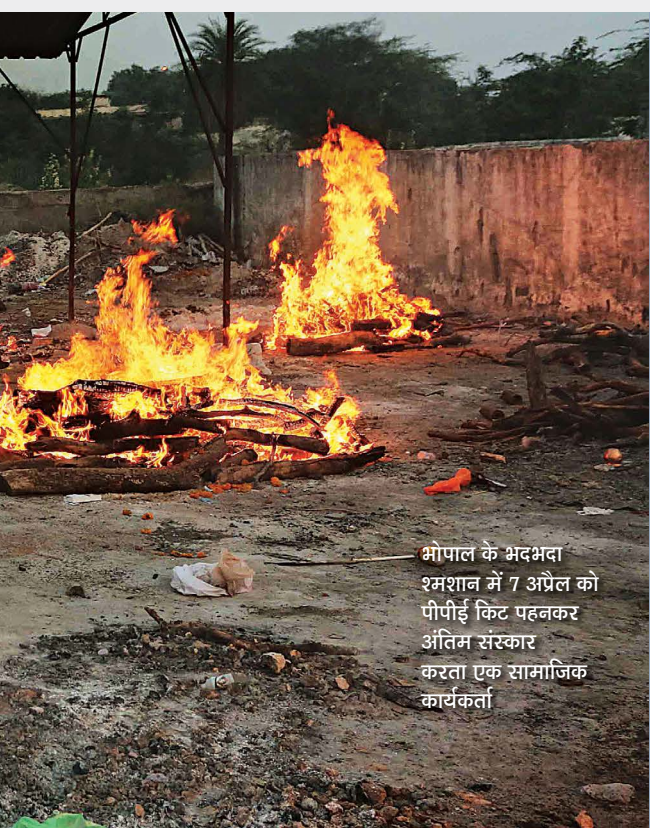

भोपाल के भदभदा श्मशान में 7 अप्रैल को पीपीई किट पहनकर अंतिम संस्कार करता एक सामाजिक कार्यकर्ता

कोविड विस्फोट

संकेत यही हैं कि इस बार वायरस अधिक तेजी से फैल रहा है

8% से 16%

टेस्ट पॉजिटिव होने की दर 4 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच हुई; यह 12 दिनों में दोगुनी हुई

20 लाख

सक्रिय मामले 20 अप्रैल तक. पिछली लहर का चरम सितंबर 2020 में इससे आधा ही था

म्यूटेंट स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक हैं

60%

भारतीय स्ट्रेन अब महाराष्ट्र के 60 फीसद मामले में पाए गए, जबकि महीने भर पहले 20 फीसद ही थे

20%

अधिक संक्रमणकारी नया स्ट्रेन; वजहः एल452आर म्यूटेशन, यह सीडीसी का कहना है

सांस लेने में परेशानी आम शिकायत

13%

ऑक्सीजन की ज्यादा मांग इस लहर की चपेट में अस्पताल पहुंचने वालों में

लेकिन अभी तक न मृत्यु दर अधिक है, न युवाओं में ज्यादा संक्रमण लग रहा है

सिर्फ 1%

ही ज्यादा 30 वर्ष से कम आयु के युवा इस लहर में संक्रमण के शिकार हो रहे हैं

1.2%

मृत्यु दर मौजूदा लहर में, पहली लहर जैसी ही

मौत के विभिन्न मद के आंकड़े भी पहले जैसे

80%

बिना लक्षण वाले मामले

20%

को अस्पताल में दाखिले की जरूरत

5%

को आइसीयू की जरूरत

1%

को वेंटिलेटर की दरकार

स्रोतः स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, आइसीएमआर, राज्यसभा रिपोर्ट, सितंबर 2020

यासिर इकबाल

दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल के सामने एक बैंकेट हॉल का नजारा, जिसे कोविड वार्ड में बदला गया है

इन्फ्रास्ट्रक्चर पड़ताल
पहली लहर बनाम दूसरी

	सितंबर 2020 (पहली लहर का चरम)	अप्रैल 2021 (दूसरी लहर की शुरुआत)
संक्रमण के रोजाना औसत मामले	85,000	200,000
औसत सक्रिय मामले	1,000,000	2,000,000
कुल कोविड केंद्र की संख्या	15,403	18,800
कुल आइसोलेशन बिस्तर	1,554,022	1,852,265
ऑक्सीजन वाले कुल बिस्तर	232,505	155,168
कुल आइसीयू बिस्तर	63,758	75,867
टेस्टिंग लैब	1,623	2,449
औसत रोजाना टेस्ट	1,000,000	1,300,000
केंद्र के दिए वेंटिलेटर	34,228	6,303

स्रोतः स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, आइसीएमआर, राज्यसभा रिपोर्ट, सितंबर 2020

इलाज का तरीका

इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां और उनका असर

रेमडेसिविर

एंटी-वायरल

दी जाती है: मध्यम से तीव्र मामलों में

असर: गिलीड के तीसरे चरण के परीक्षणों से पता चला कि हल्के मरीजों के लिए पांच दिन के कोर्स से 65% से ज्यादा ने 11वां दिन सुधार दर्शाया. हालांकि डब्ल्यूएचओ का कहना है कि कोविड के खिलाफ इस दवा का असर साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है

भारत में उत्पादन: छह कंपनियां बनाती हैं जिनकी उत्पादन क्षमता प्रति माह 38.8 लाख शीशियां हैं. कंपनियां 127 दूसरे देशों के लिए भी यह दवा बनाती हैं. 14 अप्रैल को केंद्र ने कहा कि उत्पादन अगले महीने दोगुना करने के लिए फास्ट-ट्रैक मंजूरी देगा

कीमत: ब्रांड के मुताबिक 100 मिली. की शीशी 899 रु.3,490 रु. में

फैबिफ्लू

एंटीवायरल

दी जाती है: हल्के से मध्यम मामलों में

असर: ग्लेनमार्क के चरण 3 का डेटा बताता है कि करीब 70 फीसद मरीज मानक देखभाल हासिल करने वाले 44 फीसद की तुलना में चौथे दिन ठीक

भारत में उत्पादन: पांच कंपनियां बनाती हैं—हेटरो, सिप्ला, ग्लेनमार्क, सन फार्मास्यूटिकल्स, जेनारा फार्मा

कीमत: ब्रांड के आधार पर 35-75 रुपए प्रति टैबलेट

ऑक्सीजन की पूर्ति के एसओएस संदेश केंद्र को भेजे क्योंकि इनमें कई अस्पतालों में उस दिन की जरूरत पूरी करने लायक ऑक्सीजन भी नहीं बची थी.

हालांकि डॉ. भार्गव कहते हैं कि ऑक्सीजन की मांग में बढ़ोतरी का अनिवार्य मतलब यह नहीं है कि नई लहर ज्यादा जानलेवा है. मसलन, कोविड से पैदा फेफड़ों के गंभीर संक्रमण के लिए जरूरी वेंटिलेटर की आवश्यकता पिछले साल जहां 37.3 फीसद थी, वहीं मौजूदा लहर में यह 27.8 फीसद है. नेशनल कोविड-19 रजिस्ट्री के आंकड़ों के हिसाब से, लक्षणों वाले मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने के मामले भी पिछली लहर के 87.4 फीसद के मुकाबले मौजूदा लहर में घटकर 74.5 फीसद पर आ गए हैं. (पिछले साल 80 फीसद मामले बगैर लक्षण वाले थे जबकि 20 फीसद को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत थी, जिनमें 5 फीसद को आइसीयू और 1 फीसद को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी थी.) विशेषज्ञ मानते हैं कि दूसरी लहर के आंकड़े भी आखिर में इसके बराबर ही हो सकते हैं, वहीं कुल आंकड़े बनिस्बतन छोटे वक्त में कहीं ज्यादा हैं. साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन के डायरेक्टर डॉ. रोमेल टिक्कू

एजीथ्रोमाइसिन

एंटी बायोटिक

दी जाती है: हल्के से मध्यम लक्षण के मामलों में

असर: परीक्षण नहीं. अध्ययनों में मृत्यु दर में कमी और गंभीर अवस्था से बचाव पाया गया

भारत में उत्पादन: सिप्ला, फाइजर, ग्लेनमार्क, सन फर्मा जैसी पचास कंपनियां

कीमत: ब्रांड के मुताबिक 60-65 रु. प्रति स्ट्रिप

ब्लड प्लाज्मा

कोविड के भले-चंगे हुए मरीजों का प्लाज्मा

दिया जाता है: मध्यम से गंभीर मामलों में

असर: भारत और विदेशों में परीक्षण अभी चल रहे हैं. बीएमजे जर्नल में प्रकाशित आइसीएमआर के एक अध्ययन ने पाया कि गंभीर अवस्था तक बढ़ने को रोकने में इसका सीमित असर है

भारत में उत्पादन: ठीक हो चुके मरीजों से 30 दिनों बाद लिया जाता है

कीमत: अस्पताल के मुताबिक, 10,000 रुपए-20,000 रुपए

टोसिलिजुमाब

आइएल-6 ब्लॉकर

दी जाती है: मध्यम से तीव्र मामलों में

असर: अध्ययन जारी. न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपे एक हालिया अध्ययन ने पाया कि इनटुबेशन रोकने में इसका सीमित असर है

भारत में उत्पादन: सिप्ला बनाती है, जिसका रोशे के साथ निर्यात का करार भी है. 13 अप्रैल को कंपनी ने बताया कि मौजूदा मांग के हिसाब से दवा की किल्लत हो सकती है

कीमत: 34,000 रु.-40,000 रु. प्रति शीशी

डेक्सामिथासोन

स्टेरॉइड

दिया जाता है: मध्यम से गंभीर मामलों में

असर: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिकवरी ट्राइल में पाया गया कि कोविड के गंभीर मामलों में यह मौत से एक तिहाई तक बचाव करती है

भारत में उत्पादन: कई फर्म बनाती हैं, जायडस सिप्ला का 80% बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा है

कीमत: 30 रुपए से 50 रुपए प्रति स्ट्रिप

स्रोतः ग्लेनमार्क, जीलीड, बीएमजे, नेटमेड्स

इसकी तस्दीक करते हैं, जो एक साल से ज्यादा वक्त से आइसीयू में कोविड मरीजों का इलाज करते रहे हैं. वे कहते हैं, ''लक्षण मिलते-जुलते ही हैं. कुछ मामलों में फेफड़ों का शुरुआती संक्रमण है, लेकिन फेफड़े के गंभीर संक्रमण तक पहुंचने वाले लोगों का कुल अनुपात पिछले साल जितना ही है.'' हालांकि वे यह भी कहते हैं, ''पिछले साल हमने करीब 8,000 मामले देखे. अब हम 25,000 मामले देख रहे हैं क्योंकि यह वायरस ज्यादा संक्रामक है. एक ही बार में पूरा परिवार संक्रमित हो रहा है.''

दूसरी लहर की एक और चुनौती संक्रमित हो रहे लोगों के आयु वर्ग से जुड़ी है. पिछली लहर में 30 साल के कम उम्र के लोगों के 31 फीसद मामलों में राष्ट्रीय डेटा भले महज 1 फीसद अंकों की भिन्नता दिखाता हो, लेकिन ज्यादा बारीकी में जाएं तो 0-19 साल की उम्र के लोगों के मामलों में करीब 2 फीसद अंकों की थोड़ी-सी बढ़ोतरी हुई है और 20-39 साल के लोगों में संक्रमित होने में इसी से मिलता-जुलता इजाफा हुआ है. राज्यों में भी भिन्नताएं हैं. मसलन, महाराष्ट्र में जनवरी के बाद 10 साल से कम उम्र के 88,827 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं और राज्य के कुल सक्रिय मामलों (21 अप्रैल को 6,83,856) में 52 फीसद 40 साल से कम उम्र के लोगों के हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी ऐसी ही स्थिति से दो-चार है. दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रमुख और कोविड पर सरकार की टास्कफोर्स के सदस्य डॉ. रणदीप गुलेरिया कहते हैं, ''ज्यादातर मामलों में हल्के लक्षण दिखे लेकिन वे दूसरों को संक्रमित करने में समर्थ हैं. नौजवानों का जिम्मेदार होना बेहद जरूरी है क्योंकि वे इसे ऐसे कमजोर वर्गों में फैला सकते हैं, जिनमें गंभीर लक्षण विकसित हो सकते हैं.'' वे कहते हैं कि बहुत कुछ बीमारी का जल्द पता लगने और इलाज पर निर्भर है.

जांच की बड़ी आजमाइश

अप्रैल में जब मामलों में कई गुना उछाल आया, जांच केंद्रों ने मांग पूरी करने में खुद को असहाय पाया. भारत में फिलहाल 2,449 जांच प्रयोगशालाएं हैं, जिनके पास रोज औसतन 13-15 लाख जांच करने की क्षमता है, जबकि पिछली लहर के दौरान 1,623 प्रयोगशालाएं रोज दस लाख टेस्ट ही कर सकती थीं. लैब मालिक कहते हैं कि इस बार मुख्य अंतर यह है कि कोविड की जांच का पैमाना पिछले साल सीमित था. आज ज्यादातर राज्यों में मांग पर टेस्ट करना मुमकिन है. इसके नतीजतन बगैर लक्षणों वाले लोग भी दहशतजदा होकर टेस्ट करवा रहे हैं और इसका परिणाम यह हुआ है कि मांग बढ़ गई है. जांच के

खस्ताहाली के शिकार राज्य

बढ़ते मामलों के बीच दवाइयों, ऑक्सीजन, अस्पताल बिस्तरों की किल्लत झेल रहे 10 राज्य

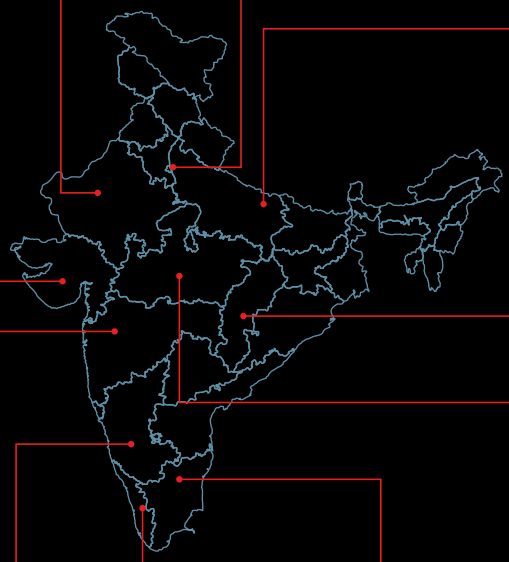

राजस्थान
- 85,571
- 11,000
- 7,638
- 8,036
- 3.6 दिन
- ✖ ऑक्सीजन

दिल्ली
- 76,887
- 23,000
- 19,608
- 2,668
- पहले ही कम
- ✖ ऑक्सीजन

उत्तर प्रदेश
- 223,544
- 28,000
- 154,428
- 15,400
- 2.75 दिन
- ✖ ऑक्सीजन, रेमडेसिविर

गुजरात
- 76,500
- 10,000
- 79,994
- 27,180
- 13 दिन
- ✖ ऑक्सीजन

छत्तीसगढ़
- 129,000
- 13,000
- 26,042
- 10,432
- 4 दिन
- ✖ रेमडेसिविर

महाराष्ट्र
- 6,83,856
- 58,000
- 3,50,340
- 3,840
- पहले ही कम
- ✖ ऑक्सीजन, रेमडेसिविर

मध्य प्रदेश
- 78,271
- 12,000
- 13,849
- 7,352
- 3 दिन
- ✖ रेमडेसिविर, ऑक्सीजन

- सक्रिय मामले
- रोजाना नए मामले
- कुल बिस्तर
- 20 अप्रैल को उपलब्ध बिस्तर
- मौजूदा दर से बिस्तर कितने दिन उपलब्ध *
- ✖ राज्य ने जो अन्य कमियां बताईं

कर्नाटक
- 142,084
- 15,000
- 13,500
- 7,000
- 2.3 दिन
- ✖ कुछ नहीं

केरल
- 118,670
- 13,000
- 35,834
- 15,968
- 6 दिन
- ✖ वैक्सीन

तमिलनाडु
- 79,804
- 10,000
- 191,301
- 29,334
- 14.6 दिन
- ✖ ऑक्सीजन

*मान लें कि 20 फीसद मामलों में अस्पताल में दाखिले की दरकार पड़ती है और हरेक को 14 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है

स्रोत: राज्यों के स्वास्थ्य विभाग

नतीजे के इंतजार का औसत समय, जो एक महीने पहले 24-48 घंटे था, अब बढ़ गया है और कुछ राज्यों में तो रिपोर्ट मिलने में चार दिन का लंबा वक्त लग रहा है.

मसलन, दिल्ली में 19 सरकारी और 23 निजी लैब ने 18 और 19 अप्रैल को 1,80,000 नमूनों की जांच की. राज्य सरकार ने भी दफ्तरों को अपने कर्मचारियों का हरेक पखवाड़े टेस्ट करवाने का फरमान जारी किया है. कई लैब का कहना है कि वे रोज तिगुने नमूनों की जांच कर रही हैं और दस्ताने, फ्लास्क, स्वाब और दूसरे सुरक्षा उपकरणों सरीखी एक बार इस्तेमाल की जाने वाली चीजें खत्म होने के करीब पहुंच गई हैं. नोएडा स्थित राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम संस्थान ने सरकार के साथ रोज 4,000 नमूने लेने का करार किया है और अब उसे हर रोज 6,000 नमूने मिल रहे हैं. डॉ. डैंग्ज लैब ने जांच में 150 फीसद की बढ़ोतरी होती देखी है और ऑनलाइन पोर्टल के खुलने के 20 मिनट के अंदर टेस्ट स्लॉट भर जाते हैं. राजधानी और महाराष्ट्र दोनों में टेस्ट करने वाली थायरोकेयर का कहना है कि जनवरी में वह अपनी क्षमता का 20 फीसद काम ही कर रही थी, लेकिन मध्य मार्च से मांग में हरेक हफ्ते 100 फीसद का उछाल आया है. दिल्ली की सबसे प्रमुख टेस्ट लैब महाजन इमेजिंग सेंटर के संस्थापक हर्ष महाजन कहते हैं, ''शहर में पॉजिटिव दर में कई गुना इजाफा हुआ है. लेकिन हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर सीमित है. इसे रातोरात बढ़ाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारी टेस्टिंग मशीनें आयातित हैं और यह सब फिर से स्थापित करने में कुछेक हफ्ते लगते हैं. निजी निवेश भी सीमित ही होगा क्योंकि शहर में टेस्ट की अधिकतम कीमत 800 रुपए तय है.''

आरटी-पीसीआर टेस्ट के असरदार होने को लेकर भी चिंताएं हैं. कई लोगों को शक है कि ये वायरस के नए स्ट्रेन का पता लगा सकते हैं या नहीं. डॉ. भार्गव भरोसा दिलाते हैं,

यासिर इकबाल

उत्तर प्रदेश में नोएडा सेक्टर 30 के जिला अस्पताल में टेस्टिंग के लिए कतार

''इस्तेमाल की जा रही टेस्ट किट कोविड वायरस के एक से ज्यादा जीन का पता लगाने के लिए डिजाइन की गई हैं और तमाम नए रूपों के खिलाफ भी भरोसेमंद हैं.'' जहां तक कई टेस्ट में झूठे नेगेटिव आने की बात है, डॉ. डैंग्ज लैब सीईओ डॉ. अर्जुन डैंग दो वजहें गिनाते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है. पहली वजह तो खराब ढंग से नमूने लेना है. दूसरी गलत समयावधि में टेस्ट किया जाना है. वे कहते हैं, ''कोविड संपर्क में आने के औसतन 5-6 दिन बाद टेस्ट में दिखाई देता है. अगर लोग किसी संक्रमित व्यक्ति से मिलने के फौरन बाद टेस्ट के लिए आते हैं तो इसका नतीजा नेगेटिव होगा, जिससे झूठा बोध पैदा हो सकता है. प्रयोगशालाओं को पक्का करना चाहिए कि उनके किट आइसीएमआर से मंजूर हो और सार्स-कोव2 के सही जीन का पता लगा रहे हों.'' डॉ. टिक्कू यह और जोड़ते हैं कि किसी में कोविड के सारे लक्षण हों, तो दूसरा टेस्ट भी किया जाना चाहिए ताकि यह पक्का किया जा सके कि वह व्यक्ति कोविड नेगेटिव है. तीसरी वजह खुद टेस्ट किट हो सकती है.

इलाज के लिए जहां टेस्ट करना जरूरी है, पिछले साल इसके बाद उसके संपर्क में आए लोगों का पता लगाने का जबरदस्त अभियान छेड़ा गया था ताकि पक्का किया जा सके कि वायरस फैले नहीं. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियम कहते हैं कि पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए 80 फीसद लोगों को तीन दिनों के भीतर अलग-थलग कर दिया जाना चाहिए. उत्तर प्रदेश में संपर्क में आए लोगों का पता लगाने की वजह से ही राज्य विशाल पहली लहर से बच निकलने में कामयाब रहा था—पिछले साल 75 जिलों में करीब 93 फीसद संपर्कों का पता लगाया और उनकी जांच की गई थी. इसमें 70,000 कार्यकर्ताओं की मेहनत लगी थी. शिखर पर भी पिछले साल राज्य में 60,000 सक्रिय मामले थे. इस बार मामले तिगुने हैं और सूत्रों का कहना है कि संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए मानवबल तत्काल बढ़ाने की जरूरत है. ज्यादातर राज्यों में संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और संक्रमितों को अलग-थलग करने की कोशिशें कम की गई हैं. जांच के नतीजे आने में देरी के साथ वायरस के तेजी से फैलाव को रोकने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कहते हैं, ''करीबी संपर्कों का मतलब केवल पारिवारिक सदस्य ही नहीं, बल्कि वह कोई भी व्यक्ति है जो संपर्क में आया हो. जिले ढीले पड़ गए थे और केवल परिवार के सदस्यों का पता लगा रहे थे जबकि वायरस पॉजिटिव व्यक्ति से मिलने वाले लोगों के जरिए फैल रहा था.'' राज्यों को समुचित कॉन्टेक्ट ट्रैसिंग पक्का करने की जरूरत है. वरना विकल्प और बदतर है—संक्रमण की श्रृंखला को रोकने के लिए लॉकडाउन.

बिस्तरों के लिए नींद हराम

पिछली लहर में केंद्र ने कोविड के इलाज के तीन श्रेणियों में बांटा था—समर्पित कोविड अस्पताल (डीसीएच), समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र (डीसीएचसी) और समर्पित कोविड देखभाल केंद्र (डीसीसीसी). कागजों पर आंकड़े असरदार दिखाई देते हैं—देश भर में 18,800 कोविड सुविधा केंद्र हैं, जिनमें कुल मिलाकर 18 लाख आइसोलेशन बेड, 1,55,168 ऑक्सीजन बेड और 75,867 आइसीयू बेड हैं. मौजूदा लहर में केंद्र ने 6,303 वेंटिलेटर भी बांटे हैं. बिस्तरों की संख्या भी पिछली बार से, जब सक्रिय मामले और रोज नए मामले आज की गिनती से आधे थे, लगभग 3,00,000 ज्यादा है. तो भी इन आंकड़ों से जिस बात की झलक नहीं मिलती, वह यह कि दूसरी लहर के प्रमुख केंद्रों पर बिस्तरों की भीषण कमी है और उनके पास कोविड के इलाज की समुचित सुविधाएं भी नहीं हैं. असल में कई राज्यों के लिए इलाज अप्रैल से ही व्यवस्थागत दुस्वप्न बन गया है, जिसमें महाराष्ट्र और दिल्ली बिस्तरों की भीषण कमी से दो-चार हैं. मोटे तौर पर ऐसा इसलिए है क्योंकि इन राज्यों में नए मामले लोगों के अच्छे होने में लगने वाले समय से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं. एक व्यक्ति को औसतन 14 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है, जो गंभीर लक्षण विकसित होने पर और लंबा भी खिंच सकता है.

20 अप्रैल को दिल्ली में महज 33 आइसीयू बेड और 2,627 ट्रीटमेंट बेड थे, जबकि शहर में रोज करीब 23,000 नए मामले आ रहे हैं. अगर इनमें 20 फीसद या 4,600 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत हो, तो फिलहाल मौजूद बिस्तर बेहद नाकाफी हैं. दिलचस्प यह है कि केंद्र ने नवंबर 2020 में दिल्ली में कोविड के लिए 6,000 आइसीयू बिस्तरों का वादा किया था. आज मौजूदा क्षमता में महज 4,500 बिस्तरों का इजाफा हुआ है. सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ मालिनी ऐसोला कहती हैं, ''दिल्ली की पिछली लहर के दृश्य दिमाग में आते हैं. तभी से हमने तैयारी क्यों नहीं की?''

संकट राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित नहीं है. मध्य प्रदेश ने 31 मार्च को कहा था कि उसके पास 20,139 आइसोलेशन, ऑक्सीजन और आइसीयू बिस्तरों का प्रावधान है और चिंता की जरूरत नहीं है. राज्य में तब केवल 2,332 नए मामले और 17,096 सक्रिय मामले थे. दो हफ्तों के भीतर राज्य में 68,576 सक्रिय मामले थे, जिनमें 12,248 नए संक्रमण थे और संक्रमित लोगों की कुल तादाद ने राज्य में बिस्तरों की स्थापित क्षमता को पीछे छोड़ दिया था. इंदौर और भोपाल सबसे बुरी तरह ग्रस्त मालूम देते हैं, जहां राज्य के बहुतायत मामले हैं. इन शहरों में बच्चों के अस्पताल सहित हर दूसरे अस्पताल को अब कोविड सुविधा केंद्र में बदल दिया गया है और फिर भी बिस्तरों की क्षमता उछाल भरती मांग को पूरा नहीं कर सकती. बोझ कम करने के लिए डॉक्टर हल्के असर वाले मरीजों को घर पर ही अलग-थलग रहने या भरोसेमंद अस्पताल से होमकेयर पैकेज लेने की सलाह दे रहे हैं.

ऑक्सीजन ने फुलाया दम

तमाम बड़े शहरों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई ने बेहद अहमियत अख्तियार कर ली. इनमें दिल्ली भी था, जहां कुछ सबसे बड़े अस्पतालों ने खतरनाक ढंग से कम आपूर्ति की इत्तला दी. संकट थामने के लिए केंद्र और राज्यों को आपातकालीन उपाय करने पड़े. देश में रोज 7,287 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बनाने की क्षमता है. 12 अप्रैल को मसलन उसने दैनिक उत्पादन क्षमता की महज 3,848 एमटी या 54 फीसद ऑक्सीजन ही इस्तेमाल की थी. मांग और बढ़ने के अनुमान के बीच ज्यादातर राज्यों ने ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है. इस बीच, यह क्षमता 50,000 एमटी तक बढ़ाने के लिए केंद्र ने नए मैन्यूफैक्चर को राजी किया और इतनी ही ऑक्सीजन आयात करने की निविदा जारी कर दी. केंद्र ने शीर्ष 12 कोविड प्रभावित राज्यों को 20 अप्रैल, 25 अप्रैल और 30 अप्रैल की स्थिति के अनुसार उनकी अनुमानित मांग पूरी करने के लिए 4,880 एमटी, 5,619 एमटी और 6,593 एमटी ऑक्सीजन जारी कर दी. तेजी से आपूर्ति पक्की करने के लिए रेलवे को समर्पित ग्रीन कॉरिडोर के जरिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने के लिए लगाया गया.

कहीं भी हालात उतने खराब नहीं हैं जितने महाराष्ट्र में हैं. यहां मेडिकल ऑक्सीजन की खपत राज्य की 1,250 टन प्रतिदिन की पूर्ण उत्पादन क्षमता पर पहुंच गई है. राज्य में 6,38,000 सक्रिय मामले हैं और उनमें 10 फीसद यानी करीब 60,000-65,000 मामले ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, जो किसी भी राज्य से ज्यादा हैं. महाराष्ट्र अब रोज छत्तीसगढ़ से 50 टन और गुजरात से 50 टन ऑक्सीजन ले रहा है. उसे गुजरात के जामनगर स्थित रिलायंस के संयंत्र से और 100 टन मिलने की भी उम्मीद है.

राज्यों को ऑक्सीजन के विवेकसम्मत इस्तेमाल के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं. वाशी, मुंबई के फोर्टिस हीरानंदानी अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन की विशेषज्ञ डॉ. फाराह इंगले कहती हैं, ''अकेले ऑक्सीजन मरीज को नहीं बचा सकती. कई लोग घर पर सिलेंडरों की जमाखोरी कर रहे हैं. मुनासिब यही है कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल सही वक्त पर चिकित्सा देखभाल और निगरानी के साथ किया जाए.''

वेंटिलेटरों की भी कमी है, खासकर उन शहरों में जहां उनकी सबसे ज्यादा मांग है. गुजरात की मैक्स वेंटिलेटर कंपनी को, जो महीने में 1,000 वेंटिलेटर बना सकती है, इस साल पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले छह गुना ज्यादा ऑर्डर मिले हैं. कंपनी के डायरेक्टर अशोक पटेल कहते हैं, ''अहमदाबाद और सूरत में ऐसे अस्पताल हैं जो वेंटिलेटर की कमी का सामना कर रहे हैं. मैं 600 वेंटिलेटर दे चुका हूं और अभी 800-1,000 के ऑर्डर और हैं.'' वे यह भी कहते हैं कि ज्यादातर राज्य सरकारें ऐसे वेंटिलेटरों का तरजीह देती हैं जिनका इस्तेमाल नॉन-इनवेसिव ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भी किया जा सके. अलबत्ता केवल बुनियादी ढांचे को बढ़ाना काफी नहीं होगा, जब तक कि इसका इस्तेमाल करने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित न किया जाए. वेंटिलेटर से लैस 10 बिस्तरों के आइसीयू के लिए हर 24 घंटों में 48 नर्सों, छह तकनीशियनों और नौ डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, जिसकी लागत प्रति मरीज 5.02 लाख रुपए आंकी जाती है. महाराष्ट्र में ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों की मांग पूरी करने के लिए पुणे ने नई भर्तियों की मंजूरियों को फास्ट-ट्रैक किया है. अगली कतार के करीब 16,000 कर्मियों ने तेजी से भर्ती की खातिर बेहतर वेतन का प्रोत्साहन लाभ देने के लिए एक दिन का वेतन भी दिया है.

दवाइयों का टोटा

देश भर में कोविड की दवाइयों का अंधाधुंध इस्तेमाल एक और चिंता की बात हो गया है. लखनऊ, भोपाल, मुंबई और दिल्ली सरीखे शहरों से रेमडेसिविर नहीं मिलने और फैबिफ्लू, एजीथ्रोमाइसिन तथा पैरासिटामोल सरीखी कोविड की अन्य दवाइयों के लिए 24-72 घंटे इंतजार करने की खबरें आईं. रेमडेसिविर की कमी खास तौर पर जबरदस्त थी. भारत में यह फिलहाल छह कंपनियां बनाती हैं और राज्यसभा की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में प्रति माह इसकी 38.8 लाख शीशियों के उत्पादन की क्षमता है, जो सामान्य हालात में आपूर्ति के लिए काफी होती. लेकिन इन कंपनियों ने

मिलिंद शेल्टे

मुंबई के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर 17 अप्रैल को कुछ ऐसा था नजारा

वैक्सीन सप्लाई के खुलेपन का **असर** तो बाद में दिखेगा. पहले तो दूसरी लहर के **संकट** से निपटना है

निर्यात के वायदे भी कर रखे हैं, जिन पर केंद्र ने फिलहाल रोक लगा दी है. सरकार इस दवाई की मैन्यूफैक्चरिंग के लिए फास्ट-ट्रैक मंजूरियां भी देगी, ताकि मई के मध्य तक उत्पादन दोगुना बढ़ाकर 78 लाख शीशियां प्रति माह किया जा सके.

हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है. यह कोविड के इलाज के लिए अनिवार्य दवाई नहीं है. वहीं डब्ल्यूएचओ अब भी कह रहा है कि इसके असरदार होने को लेकर कोई ठोस डेटा नहीं है. डॉ. टिक्कू कहते हैं, ''रेमडेसिविर प्रयोगात्मक दवाई है, यह सही वक्त पर प्रशिक्षित पेशेवर के हाथों ही दी जानी चाहिए.'' तमाम वायरल बीमारियां आत्मनियंत्रक हैं. इसका अर्थ है कि शरीर उन्हें खुद-ब-खुद लड़कर खत्म कर सकता है. दवाई शरीर को केवल तभी मदद करती है जब वायरल संक्रमण हल्का या तीव्र हो. यही नहीं, पहले 5-7 दिनों के दौरान स्टेरॉइड देना असल में वायरस को अपनी नकल तैयार करने में मदद ही करता है. ऐसे ज्यादा से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं जिनमें लोग झूठे नुस्खा दिखाकर दवाइयां खरीद रहे हैं, ऐसे में सरकारें खुद अपनी समझ से दवाइयां लेने और कोविड की बेहद जरूरी दवाइयों की जमाखोरी करने के खिलाफ सलाह देने के अभियान तेज कर रही हैं.

मसलन तेलंगाना में, जहां रेमडेसिविर की कमी है, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने मरीज का आधार कार्ड देखने के बाद वितरण को आसान बनाने और दवा का अंधाधुंध दुरुपयोग तथा कालाबाजारी खत्म करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है. स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी हरेक मामले में इसकी सलाह देने के खिलाफ अस्पतालों को संवेदनशील बनाया है क्योंकि यह सीमित इस्तेमाल के लिए है. तेलंगाना के सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक डॉ. जी. श्रीनिवास राव सावधान करते हैं, ''कोविड की पहली लहर के दौरान कोविड पॉजिटिव मरीजों की बड़ी संख्या को ताकतवर स्टेरॉइड टोसिलिजुमाब विवेकहीन ढंग से दिया गया. उन्हें इस दवा के इस्तेमाल की वजह से तकलीफ उठानी पड़ी. रेमडेसिविर के मामले में भी वही गलती दोहराई जा रही है. यह सभी कोविड मरीजों के लिए नहीं है. इन दिनों घरों से लेकर अस्पतालों तक हर जगह इसका दुरुपयोग हो रहा है.''

आगे विकट लड़ाई

पिछले साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में दुनिया का सबसे कठोर लॉकडाउन लगा दिया था. 20 अप्रैल को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने इस बार इसकी संभावना को सिरे से खारिज कर दिया, बावजूद इसके कि दूसरी लहर में मामलों की संख्या कहीं ज्यादा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अर्थव्यवस्था की सेहत राष्ट्र की सेहत जितनी ही जरूरी और अहम है और वायरस के संक्रमण की शृंखला तोड़ने के लिए माइक्रो-कंटेनमेंट जोन और आत्म-अनुशासन की जरूरत है. विशेषज्ञों का कहना है कि अस्पतालों और संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए यह बेहद जरूरी है. दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में एक औसत डॉक्टर अब करीब 12-14 घंटे काम करता है. कोविड देखभाल के एक से ज्यादा साल ने उन्हें थका दिया है. आइएमए के पूर्व प्रेसीडेंट डॉ. अग्रवाल कहते हैं, ''स्थानीय लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला अहम है. अगर आपको ज्यादा बिस्तर और वेंटिलेटर मिल भी जाएं तो स्वास्थ्यकर्मी तो सीमित ही रहेंगे. आप रातोरात लाखों डॉक्टर, नर्स और तकनीशियन नहीं बना सकते.''

केंद्र राज्यों और जिलों से लगातार कह रहा है कि वे लॉकडाउन के साथ-साथ माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं. पिछले साल सबसे पहले राजस्थान के भीलवाड़ा में इस्तेमाल की गई इस रणनीति में अधिकारी पॉजिटिव मामलों को अलग-थलग रखते हैं, जबकि क्लस्टर के भीतर सीमित आवाजाही संक्रमण को फैसले से रोकती है. दिल्ली में 1 अप्रैल से 18 अप्रैल 2021 के बीच कंटेनमेंट जोन की संख्या में 507 फीसद का उछाल आया. स्वास्थ्य सचिव भूषण के मुताबिक, फरवरी में राज्यों ने मामलों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी देखी, लेकिन कंटेनमेंट जोन की संख्या नहीं बढ़ी. मौजूदा उछाल में इसका भी योगदान रहा है.

केंद्र यह भी उम्मीद कर रहा है कि व्यापक टीकाकरण से संक्रमण का फैलाव कम करने या कम से कम मामलों की तीव्रता घटाने में मदद मिलेगी. उत्पादन और डिलिवरी पर केंद्रीय नियंत्रण इस कोशिश का गला घोंट रहा है और ऐसे में अब तक वैक्सीन की केवल 12.80 करोड़ खुराकें लगाई गई हैं, जिससे महज 1.7 करोड़ लोगों या 1.28 फीसद आबादी का पूर्ण टीकाकरण हुआ है. पिछले हफ्ते, स्वागत योग्य कदमों की शृंखला में, टीकाकरण को 1 मई से न केवल 18 साल से बड़ी उम्र के सभी लोगों के लिए खोल दिया गया, बल्कि राज्यों को भी अपने दम पर वैक्सीन खरीदने की इजाजत दे दी गई. उम्मीद है कि वैक्सीन कार्यक्रम को उदार बनाने से इसकी मांग और वितरण बढ़ेगा. चिंता इस बात की है कि आपूर्ति उन 40 करोड़ अतिरिक्त लोगों की मांग को पूरा कर पाएगी या नहीं जो टीकाकरण को 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए खोलने के सबब से इसके पात्र हो जाएंगे.

अलबत्ता देश को सबसे अहम कदम यह उठाने की जरूरत है कि वह कोविड के मुआफिक व्यवहार पर काम करे. प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों से आह्वान किया कि वे कोविड के बारे में जागरूकता फैलाने और कोविड अनुशासन लागू करने के लिए स्थानीय समितियां बनाएं. उन्होंने बच्चों से भी आग्रह किया कि वे परिवार के बड़ों से कहें कि वे बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाएं. डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, मास्क पहनना और 2 फुट की दूरी रखना संक्रमण में 85 फीसद तक कटौती करता है. यह भारत में फिलहाल मौजूद दोनों वैक्सीनों से भी ऊंची प्रभाव दर है. मगर भारत में मास्क साक्षरता में एक गंभीर खामी है. स्वच्छ वायु समाधान फर्म निर्वाणा बीइंग के संस्थापक जय धर गुप्ता कहते हैं, ''दुनिया में ऐसा कोई सूती कपड़ा नहीं है जो कोविड वायरस जितने छोटे कण को बाहर रख सके. कम से कम एन95 मास्क की जरूरत तो है ही. यही नहीं, मास्क पहनने के तरीके को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं आई है. नाक और ठोड़ी इससे ढकी होनी चाहिए. तीसरे, सांस लेने योग्य मास्क का न होना सेहत के लिए विनाशकारी है क्योंकि खुद अपनी ही कार्बन डाइऑक्साइड को सांस में लेना जहरीला है.''

यूरोप में सामुदायिक मास्क के मानक हैं. महामारी के सबसे जरूरी बचावों में से एक के लिए अभी भारत को इससे मिलता-जुलता कुछ शुरू करना है. चुनिंदा ढंग से लॉकडाउन संक्रमण के हमारे मौजूदा बोझ को कम करने में कारगर हो सकते हैं, वहीं युद्ध स्तर पर टीकाकरण और व्यापक रूप से मास्क पहनना तीसरी लहर को रोकने के लिए बेहद अहम है. इस बीच राज्यों को दूसरी लहर से पुख्ता हो चुके चिकित्सा के संकट को संभालने पर पूरा ध्यान देना चाहिए. कोविड अभी कहीं जाने वाला नहीं है. आप खुद अपनी जिम्मेदारी और अपनी कीमत पर ही इसे अनदेखा कर सकते हैं. यह सबक हम बेहद मुश्किल रास्ते से गुजरकर फिलहाल सीख ही रहे हैं. ■

दहशत और नाउम्मीदी

सभी राज्यों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराईं, अस्पतालों में बिस्तर पाने के लिए हाथ-पैर मार रहे मरीज, कोविड टेस्ट रिपोर्ट आने में कई-कई दिन लग रहे और ऑक्सीजन तथा जरूरी दवाइयों की भारी किल्लत

रायटर्स/दानिश सिद्दीकी

एलएनजेपी अस्पताल में कोविड के मरीज

कालकाजी अंत्येष्टि स्थल के बाहर 16 अप्रैल को सिर पर प्लास्टिक कवर लगाए लोगों की एक पूरी कतार बैठी थी. दुख में दहकती उनकी आंखों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था. वे 12 परिवारों के लोग थे, जिनके प्रियजनों को कोविड ने छीन लिया था. 21 वर्षीय विधि छात्रा सुहाणिनी अरोड़ा कहती हैं, ''मेरी मां को वेंटिलेटर दिलाने के लिए दोस्तों, परिचितों और रिस्तेदारों को दो दिन फोन करना पड़ा. मैंने रेमडेसिविर इलाज के लिए भी 18,000 रु. खर्च किए. जब तक उनके लिए आइसीयू की व्यवस्था हम कर पाते, उन्हें सांस लेने में तकलीफ काफी बढ़ गई थी और 18 घंटों के भीतर उनकी मौत हो गई.''

इसके पहले कोविड की तीन लहर झेल चुकी दिल्ली में ऐसा मुकाम पहले कभी नहीं दिखा था. 19 अप्रैल को शहर की पॉजिटिव दर 30 फीसद थी यानी हर तीसरे आदमी का टेस्ट करने पर पॉजिटिव पाया जाएगा. नवंबर में पॉजिटिव दर 11.03 फीसद थी और मोटे तौर पर उसी अनुपात में टेस्ट होते थे. शहर में संक्रमण के इतने सक्रिय मामले कभी नहीं दिखे. 19 अप्रैल को यह आंकड़ा 76,887 था, जो दो बार लहरों के चरम के वक्त भी 42,000 था. एक दिन के मामलों में रिकॉर्ड टूट रहा है. 24 घंटे में सबसे अधिक 8,593 मामले 11 नवंबर को दर्ज हुए थे. 20 अप्रैल को यह तीन गुना से ज यादा 28,395 था. दिल्ली में एम्स के निदेशक, रणदीप गुलेरिया कहते हैं, ''हम बहुत सारे युवाओं को संक्रमित होते देख रहे हैं. लोगों ने इस बीमारी को बहुत हल्के में ले लिया.''

संक्रमण के मामले घटने लगे तो कोविड वाले अस्पताल भी दूसरी बीमारियों के इलाज में ध्यान देने लगे, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे भारी संक्रमण प्रकोप वाले राज्यों से आने वालों की जांच-पड़ताल में ढिलाई बरती जाने लगीं और मार्च में सामाजिक आयोजनों की छूट दे दी गई. सरकार ने भी तैयारी के मद में शहर को कमतर कर दिया. 21 अप्रैल को दिल्ली में सिर्फ 2,345 खाली बिस्तर थे, जिनमें 27 आइसीयू थे. प्रमुख अस्पतालों में 11-16 घंटे की ऑक्सीजन आपूर्ति ही बची थी.

लोगों की शिकायत है कि लगातार दो-तीन दिन तक फोन करते रहने के बाद अस्पताल में बिस्तर मिल पा रहा है. ग्राफिक आर्टिस्ट 39 वर्षीय सुमित कौर को एलएनजेपी अस्पताल में दोस्तों की मदद से ही बिस्तर मिल पाया. वे पूछती हैं, ''अगर 2,000 बिस्तर खाली थे तो मुझे एक क्यों नहीं मिला? हेल्पलाइन पर फोन करने पर इंतजार करने को कहा गया.'' पिछले दो हफ्तों में सिर्फ 2,000 बिस्तर ही अतिरिक्त तैयार किए गए. अगर संक्रमण लगने वाले 20 फीसद लोगों को भी अस्पताल में भर्ती करने की दरकार हुई तो शहर में रोजाना 5,600 नए बिस्तरों की जरूरत पड़ेगी. लोग कोविड दवाइयों की किल्लत और टेस्ट रिपोर्ट में देरी से घबराए हुए हैं. तैयारियों में ढिलाई ने काफी कीमत ली है. दिल्ली में मौत भी पहले से ज्यादा हो रही है. कुल मृत्यु दर तो वही (1.4 फीसद) बनी हुई है, लेकिन जानकार कहते हैं कि इससे सही तस्वीर नहीं उभरती क्योंकि कुल मामले साल भर से बढ़ते रहे हैं.

> ''बहुत-से **युवाओं** को संक्रमण हो रहा है. असल में हमने बीमारी को बहुत **हल्के** में ले लिया.''
>
> **डॉ. रणदीप गुलेरिया**
> *निदेशक, एम्स, दिल्ली*

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब यह कहा कि दिल्ली का स्वास्थ्य तंत्र अब और झेलने के काबिल नहीं है, वह यकीनन बेहद दुखद दिन था. उम्मीद की जानी चाहिए कि लॉकडाउन के हफ्ते भर बाद जब दिल्ली के लोग सड़कों पर उतरें तो उन्हें कोविड का डर न सताए. डर बीमारी का ही नहीं है, बल्कि समय पर इलाज न मिल पाने का है.

—सोनाली अचार्जी

पॉजिटिव दर* (20 अप्रैल)	सक्रिय मामले (1 मार्च से 20 अप्रैल तक)	कोविड से मौत (1 मार्च से 20 अप्रैल तक)
32.8%	266,077	1,727

**कुल हुए कोविड टेस्ट में से पॉजिटिव रहे नतीजों का प्रतिसत ही पॉजिटिव रेट कहलाता है. डब्ल्यूएचओ ने कोविड पर काबू के लिए यह दर 5 प्रतिशत से नीचे अनुशंसित की है.*

रायपुर में एक इनडोर स्टेडियम को बनाया गया कोविड केंद्र

छत्तीसगढ़

पिछले साल संक्रमण के मामलों की बहुत कम संख्या, ठीक होने की अच्छी दर और राज्य का बड़ा हिस्सा कोविड से अछूता रहा तो छत्तीसगढ़ को काफी वाह-वाही मिली थी. लेकिन राज्य कोविड की दूसरी लहर की चपेट में है. 19 अप्रैल तक संक्रमण के 1,29,000 सक्रिय मामले के साथ यह देश में चौथा सबसे बुरी तरह ग्रस्त राज्य है.

छत्तीसगढ भी मान बैठा था कि कोविड का बुरा दौर गुजर गया. राजधानी रायपुर में रोजाना पॉजिटिव मामलों की तादाद 30 से कम हो गई थी. कई लोगों को आशंका है कि मार्च में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 40,000 दर्शक क्षमता वाले रायपुर स्टेडियम में आयोजित टी20 क्रिकेट टुर्नामेंट ही कोविड के भयानक प्रसार का कारण बना.

छत्तीसगढ़ में फिलहाल अस्पतालों में बिस्तरों, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवाइयों की भारी किल्लत है. राज्य में कुल 26,042 कोविड बिस्तर हैं, जिनमें 8,088 ऑक्सीजन वाले और 2,550 आइसीयू बिस्तर हैं. 20 अप्रैल को सिर्फ 2,006 ऑक्सीजन बिस्तर और 171 आइसीयू बिस्तर खाली थे. ये भी तेजी से भर रहे थे. रायपुर में स्वास्थ्य सेवाओं पर इसलिए भी दबाव है क्योंकि करीब आधा दर्जन पड़ोसी जिलों से भी यहां मरीज पहुंचते हैं.

स्वास्थ्य विभाग की योजना 1,000 नए आइसीयू बिस्तर तैयार करने और निजी अस्पतालों में 50 फीसद बिस्तर कोविड मरीजों के लिए आरक्षित करने की है. इसके अलावा, 6,000-7,000 ऑक्सीजन वाले बिस्तर तैयार करने की कोशिश चल रही है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि हालात नाजुक हैं लेकिन आंकड़ों के मामले में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जा रही है, इसी वजह से शुरू में ज्यादा मामले प्रकाश में आए. उनका कहना है कि टेस्ट अधिक होने से मामले भी ज्यादा दिख रहे हैं. टेस्ट के बारे में राज्य का दावा सही हो सकता है. 2.3 करोड़ की आबादी वाले राज्य में रोजाना 48,000 टेस्ट हो रहे हैं और उसमें इजाफा किया जा रहा है. इसके तुलना में पड़ोसी मध्य प्रदेश की आबादी 7.23 करोड़ (2011 जनगणना) है जबकि रोजाना सिर्फ 50,000 टेस्ट ही हो रहे हैं.

कोविड मौतों के मामलों में भी छत्तीसगढ़ पारदर्शिता बरत रहा है, 19 अप्रैल को दर्ज 165 मौत में 104 कोविड से बताई गई जबकि बाकी कोविड मरीजों की मौत अन्य बीमारियों से हुई. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंह देव ने कहा, ''हम पूरी पारदर्शिता बरत रहे हैं क्योंकि हम इसे इस संकट से निपटने के लिए अनिवार्य मानते हैं.'' दवाइयों की किल्लत पर वे कहते हैं सरकार ने रेमडेसिविर के 90,000 वायल का ऑर्डर दे दिया है और 45,000 वायल की और खरीद की प्रक्रिया चल रही है.

अधिकारियों को आशंका है कि 30 अप्रैल तक राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,70,000 हो जाएगी. रायपुर एम्स के निदेशक डॉ. नितिन नगारकर ने मीडिया में कहा कि राज्य में करीब 70,000 ऑक्सीजन बिस्तर की जरूरत पड़ेगी. फिलहाल तो छत्तीसगढ़ काफी दूर है.

—राहुल नरोन्हा

ईपीए-ईएफई/संजीव गुप्ता

भोपाल के पास एक गांव में वैक्सीनेशन कार्यक्रम

पॉजिटिव दर (20 अप्रैल)
24.76%

सक्रिय मामले (1 मार्च से 20 अप्रैल तक)
171,602

कोविड से मौत (1 मार्च से 20 अप्रैल तक)
848

मध्य प्रदेश

इस साल 21 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कोविड रणनीति की समीक्षा बैठकें फिर शुरू कीं. ये बैठकें पिछले साल संक्रमण के मामले कम होने लगे तो छोड़ दी गई थीं. लेकिन कोविड की दूसरी लहर का प्रकोप बढ़ा तो राजधानी भोपाल और वाणिज्यिक केंद्र इंदौर का स्वास्थ्य ढांचा अप्रैल के पहले हफ्ते में ही चरमरा गया. सरकार की शुरुआत में मास्क पहनने की अपील, रात को/सप्ताहांत में कर्फ्यू लगाने, महाराष्ट्र से जुड़े जिलों में स्क्रीनिंग की संख्या बढ़ाने जैसी कोई कार्रवाई काम न आई. एक वरिष्ठ अफसरशाह का दावा है कि राजस्व घाटे के मद्देनजर पूरी तरह लॉकडाउन के ऐलान का कई हलकों से विरोध हो रहा है. वे यह भी कहते हैं, ''भोपाल में रात के कर्फ्यू के वक्त भी शराब की दुकानें खुली रहीं.''

18 अप्रैल को पूरे मध्य प्रदेश में 38,915 कोविड बिस्तर उपलब्ध थे जबकि संक्रमण के सक्रिय मामले 68,576 थे और उस दिन 12,248 नए मामले दर्ज हुए थे. भोपाल और इंदौर में तब से आइसीयू के बिस्तर भरे पड़े हैं. कोविड की वजह से करीबी दोस्त गंवा बैठने वाले भोपाल के जयेश दुग्गल कहते हैं,

अभिषेक चौहान

पॉजिटिव दर (20 अप्रैल)
30.81%

सक्रिय मामले (1 मार्च से 20 अप्रैल तक)
261,483

कोविड से मौत (1 मार्च से 20 अप्रैल तक)
2,432

रेमडेसिविर के 90,000 वायल का ऑर्डर दिया गया है और 45,000 वायल की खरीद की प्रक्रिया जारी है.

''बचपन के दोस्त अस्पताल मालिक भी कोई मदद कर पाने की स्थिति में नहीं थे.'' टेस्ट भी नाकाफी हो रहे हैं. 18 अप्रैल को करीब 54,000 आरटी-पीसीआर टेस्ट हुए लेकिन टेस्ट रिपोर्ट आने में देरी हो रही है, जिसका असर इलाज पर पड़ रहा है.

फैविपीरवीर, रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब जैसी जरूरी दवाइयों का स्टॉक अप्रैल के दूसरे हफ्ते में खत्म हो गया. इसलिए कालाबाजारी हर तरफ बेइंतहा है. रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन 20,000 रु. में बिक रहा है. इससे भी बदतर यह कि भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज से रेमडेसिविर इंजेक्शन के तकरीबन 850 वायल चोरी हो गए. यही हाल ऑक्सीजन सप्लाई का है. 18 अप्रैल को शहडोल मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में कम से कम छह मौत दर्ज हुई. डॉक्टरों का कहना है कि यह ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से हुई जबकि अधिकारी इससे इनकार करते हैं. स्वास्थ्य विभाग की योजना 30 अप्रैल तक 70,000 कोविड बिस्तर बढ़ाने की है, जिसमें 9,300 आइसीयू और 27,000 ऑक्सीजन बिस्तर होंगे. ऑक्सीजन की आपूर्ति में इजाफे के लिए करीब 2,000 ऑक्सीजन कंसेनट्रेंटर मशीन भी खरीदी जा रही हैं.

—राहुल नरोन्हा

गुजरात

गुजरात में अप्रैल के पहले 20 दिनों में कोविड के मामलों में करीब पांच गुना उछाल दर्ज हुई है. राज्य में 1 अप्रैल को 2,410 नए मामले और नौ मौतें हुईं. 19 अप्रैल को ये आंकड़े 11,043 मामले और 117 मौत थे. करीब 37 फीसद सक्रिय मामले अहमदाबाद में थे.

राज्य में कुल 79,944 कोविड बिस्तर हैं, जिनमें से सरकार का दावा है कि 18 अप्रैल को करीब 34 फीसद बिस्तर खाली थे. मगर जमीन पर तस्वीर अलहदा नजर आती है. सात जिलों अमरेली, खेड़ा, मेहसाणा, पाटन, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर और वलसाड़ में एक भी खाली बिस्तर नहीं है. कोविड के लिए तय अस्पतालों के बाहर लंबी कतारों की खबरें हैं. कुछ जगहों पर लोग ऑक्सीजन के सपोर्ट पर ऑटोरिक्शा में इंतजार कर रहे थे. अहमदाबाद अस्पताल ऐंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन के वाइस-प्रेसीडेंट डॉ. अनीश चंद्राना ने कहा कि अस्पताल नए मरीजों के लिए जगह खाली करवाने की खातिर मरीजों को हफ्ते से भी कम वक्त में छुट्टी दे रहे हैं. मुख्यमंत्री विजय रूपानी कहते हैं कि लंबी कतारों के बावजूद हर किसी को बिस्तर मिल रहा है.

गुजरात हाइकोर्ट ने 17 अप्रैल को सरकार से पूछा कि वह कोविड का प्रकोप रोकने की खातिर लॉकडाउन पर विचार क्यों नहीं कर रही है. गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री और फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भी लॉकडाउन लगाने की मांग की. मगर उप-मुख्यमंत्री नितिन पटेल कहते हैं कि लॉकडाउन का असर जहां नौकरियों और कारोबार पर पड़ेगा, लेकिन इससे संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने में मदद मिलने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. बुरी तरह प्रकोप वाले जिलों में से एक वलसाड के व्यापारी ऐसा नहीं सोचते. उन्होंने 20 अप्रैल से खुद अपनी तरफ से 10 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया. वलसाड में 19 अप्रैल को 2,101 नए मामले आए. सूरत की कपड़ा इकाइयां 17-18 अप्रैल को बंद रहीं, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि कम से कम एक हफ्ते का लॉकडाउन वक्त का तकाजा है.

रूपानी सरकार ने ऑक्सीजन की सारी आपूर्तियां चिकित्सा उद्देश्यों के लिए रखने का फैसला लिया है. रोज 20,000 वायल की आपूर्ति के साथ गुजरात के पास रेमडेसिविर का पर्याप्त भंडार है. राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना—मुख्यमंत्री अमृतम योजना—के तहत जिनके बीमे की मियाद 31 मार्च को खत्म हो गई, उनके लिए यह तीन महीने बढ़ा दी गई है.

—किरण डी. तारे

पॉजिटिव दर (20 अप्रैल)
7.03%

सक्रिय मामले (1 मार्च से 20 अप्रैल तक)
157,862

कोविड से मौत (1 मार्च से 20 अप्रैल तक)
1,204

विभांशु कपरिया

सूरत से अपने गांव-घर लौटते प्रवासी मजदूर

महेश टिक्ली

नागपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर बिस्तर की प्रतीक्षा में एक कोविड मरीज

सक्रिय मामले
(1 मार्च से 20 अप्रैल तक)
1,798,892

पॉजिटिव दर
(20 अप्रैल)
23.3%

कोविड से मौत
(1 मार्च से 20 अप्रैल तक)
9,159

महाराष्ट्र

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 13 अप्रैल को लॉकडाउन का ऐलान किया तब तक महाराष्ट्र में रोज औसतन 60,000 नए मामलों दर्ज होने लगे थे. ये फरवरी के आखिर के मुकाबले करीब चार गुना थे. लॉकडाउन के दौरान दवाई, स जी और किराने के सामान सरीखी जरूरी चीजों की दुकानों को सुबह 7 से शाम 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है. 20 अप्रैल से किराने की दुकानों के खुलने का समय सुबह 7 से दोपहर 11 बजे कर दिया गया. होटल, बार, रेस्तरां, जिम, स्पा और सैलून बंद पड़े हैं.

राज्य में आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए करीब 500 प्रयोगशालाएं हैं, लेकिन बढ़ते बोझ की वजह से टेस्ट और रिपोर्ट में देर हो रही है. टेस्ट के लिए औसतन दो दिन बाद का समय मिलता है जबकि रिपोर्ट आने में तीन दिन लग जाते हैं. स्वास्थ्य मंत्री राजेश तोपे कहते हैं कि 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, लेकिन यह मुश्किल दिखाई देता है.

महाराष्ट्र की पॉजिटिविटी दर 19 अप्रैल को 16.19 फीसद थी. राज्य रेमडेसिविर की कमी भारी है. राज्य की कोविड-19 टास्कफोर्स के प्रमुख डॉ. संजय ओक कहते हैं कि रेमडेसिविर जिंदगी बचाने की गारंटी नहीं है, पर यह अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि कम करने में मददगार है. रेमडेसिविर के काले बाजार में 20,000-30,000 रुपए प्रति वायल जितनी ऊंची कीमत पर बिकने की खबरें हैं. ठाणे के बाशिंदे अनुरुद्ध पाटील हैरान रह गए जब एक डीलर ने एक शीशी के लिए उनसे 22,000 रु. मांगे. पाटील कहते हैं, ''मुझे पिता के लिए तीन शीशियां चाहिए थीं. खुशकिस्मती से एक दोस्त ने अपनी मां के लिए खरीदी शीशियों में से बाकी बची मुझे दे दीं. तीन शीशियों के लिए मुझे महज 3,600 रु. देने पड़े,''

राज्य सरकार ने हेल्पलाइन शुरू की है जहां मरीज रेमडेसिविर के लिए नाम लिखवा सकते हैं. अस्पतालों के लिए जिला कलेक्टर के पास, जिन्हें इस इंजेक्शन के वितरण का नोडल अफसर बनाया गया है, अपनी मांग दर्ज करवाना अनिवार्य है. सरकार ने रेमडेसिविर की 8,00,000 शीशियों की आपूर्ति के लिए दो बार टेंडर बुलाए लेकिन खाद्य और दवा प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे कहते हैं कि सरकार द्वारा तय 1,656 रुपए की दर से इंजक्शन सप्लाई करने में कंपनी की दिलचस्पी नहीं थी. शिंगणे बताते हैं, ''एक कंपनी 30 मई के बाद ही शीशियां दे सकेगी. दूसरी रोज केवल 500 शीशियां दे सकती है.''

महामारी पर नियंत्रण की कोशिशें मुंबई-पुणे इलाके के इर्द-गिर्द सिमटी हैं, जबकि विदर्भ इलाका सबसे ज्यादा तकलीफ झेल रहा है. 19 अप्रैल को नागपुर जिले में राज्य भर में सबसे ज्यादा 113 मौतें दर्ज की गईं. 17 अप्रैल को बॉम्बे हाइकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह नागपुर को रेमडेसिविर की 10,000 शीशियों मुहैया करे.

महाराष्ट्र में मेडिकल ऑक्सीजन की भी कमी है. राज्य कोविड के मरीजों के लिए रोज 1,200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा है, पर ये कुल जरूरत से 500 मीट्रिक टन कम है. उम्मीद है कि विशाखापत्तनम और नवी मुंबई के बीच चलाई जा रही 'ऑक्सीजन एक्सप्रेस' रेल अप्रैल के आखिर तक कमी को पूरा कर देगी.

राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वाडेट्टीवार कहते हैं कि नए मामलों में कमी नहीं आई तो सरकार मई के पहले हफ्ते से कड़ी पाबंदियां लग सकती है. महाराष्ट्र 19 अप्रैल तक करीब 1.30 करोड़ लोगों को कोविड टीके लगा चुका था. तोपे कहते हैं कि वैक्सीन की सप्लाई पर्याप्त हो तो रोज 8,00,000 लोगों को टीके लगाए जा सकते हैं.

—किरण डी. तारे

मेडिकल ऑक्सीजन की रोजाना कमी 500 मीट्रिक टन की है. यह कमी अप्रैल अंत तक दूर होने की उम्मीद

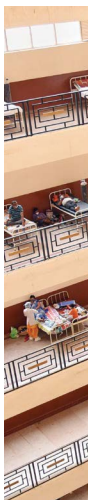

उत्तर प्रदेश

मनीष अग्निहोत्री

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में बिलखते परिजन

पॉजिटिव दर
(20 अप्रैल)
14.79%

सक्रिय मामले
(1 मार्च से 20 अप्रैल तक)
305,797

कोविड से मौत
(1 मार्च से 20 अप्रैल तक)
1,432

लखनऊ के 65 वर्षीय वी.के. श्रीवास्तव 6 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव निकले जो उनके लिए सदमा था लेकिन इससे भयावह समय उन्होंने तब देखा जब उन्होंने अपना इलाज कराना चाहा. अस्पताल में भर्ती होने के लिए उन्होंने लखनऊ के कोविड कंट्रोल रूम में बेहिसाब फोन किए पर वे दाखिले की पर्ची नहीं पा सके. 17 अप्रैल को उनका निधन हो गया. जाने-माने इतिहासकार 82 वर्षीय योगेश प्रवीण भी 12 अप्रैल को इसी नियति को प्राप्त हुए. कई घंटे एंबुलेंस का इंतजार करने के बाद उनके घरवाले उन्हें किसी निजी गाड़ी से लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में ले गए, तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) संजय भटनागर कहते हैं, ''हम दिन-रात मरीज भर्ती करने का प्रयास करते हैं पर बिस्तर तो उपलब्ध होना चाहिए.'' लखनऊ में 19 अप्रैल को शहर में कोविड से 22 मौतें और संक्रमण के 5,897 नए मामले दर्ज हुए. इस तरह लगातार सातवें दिन संक्रमण के रोजाना 5,000 से अधिक नए मामले दर्ज हुए. उस दिन उत्तर प्रदेश में 28,287 नए मामले और 167 मौत दर्ज हुई थी. तेजी से हो रही मौतों के कारण अंतिम संस्कार में भी घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है. पिछले पखवाड़े से लखनऊ के भैंसा कुंड श्मशान घाट और ऐशबाग कब्रिस्तान में हर रोज 150-180 शव आ रहे हैं. 20 अप्रैल को अपने पिता की अंत्येष्टि करने वाले आदेश अग्रवाल कहते हैं, ''करीब 3-4 घंटे का इंतजार करना पड़ता है. अंत्येष्टि टोकन नंबर के हिसाब से होती है.''

लखनऊ में 96 अस्पतालों को अब अधिकृत कोविड इलाज केंद्र बना दिया गया है. लेकिन लखनऊ के पूर्व डिप्टी सीएमओ रमेश कुमार वर्मा का कहना है कि मरीज को पहले इंटीग्रेटेड कमांड ऐंड कंट्रोल रूम में संपर्क करके किसी कोविड अस्पताल में दाखिले की पर्ची हासिल करनी पड़ती है. वे कहते हैं, ''इसके बजाय मरीजों का पहले अस्पताल में दाखिला होना चाहिए और उसके बाद कमंड सेंटर को सूचना भेज दी जानी चाहिए.'' ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर जैसी दवाओं की मांग होने के कारण इनी कालाबाजारी हो रही है. लखनऊ के अमीनाबाद के एक निवासी का कहना है कि 6,000 रु. कीमत के एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए उनसे सप्लायर ने 40,000 रुपये की मांग की. लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन के सी.एम. दुबे के मुताबिक, ''कोविड की दवाइयां खत्म हो गई हैं या उनकी सीमिति सप्लाई ही है. विटामिन-सी, जिंक और पैरासिटामोल के टैबलेट भी मुश्किल से मिल रहे हैं.''

—आशीष मिश्र

रोहित जैन पारस

जयपुर में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी के कॉरीडोर में लगाए गए कोविड बेड

पॉजिटिव दर
(20 अप्रैल)
14.21%

सक्रिय मामले
(1 मार्च से 20 अप्रैल तक)
118,330

कोविड से मौत
(1 मार्च से 20 अप्रैल तक)
481

राजस्थान

बीते 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक कोविड समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें डॉक्टरों, नौकरशाहों और कुछ मंत्रियों ने संपूर्ण लॉकडाउन की सिफारिश की. अर्द्धरात्रि को गहलोत ने राजस्थान में आंशिक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया. कोविड की दूसरी लहर ने राजस्थान के स्वास्थ्य ढांचे को चरमरा दिया है. सरकार अधिक से अधिक अस्पतालों को कोविड केंद्रों में बदलने और कोविड रोगियों के लिए निजी अस्पतालों में 25 प्रतिशत बिस्तर आरक्षित करने के लिए मजबूर हुई है. मार्च में राजस्थान में कोविड से 31 मौत दर्ज की गई थी. 20 अप्रैल को ही 64 लोगों की मौत हुई. मौजूदा महीने में मौत का आंकड़ा 450 तक पहुंच गया है.

ऐसी आशंका है कि सक्रिय मामलों की कुल संख्या 19 अप्रैल के 76,000 से बढ़कर महीने के अंत तक 1,30,000 हो सकती है. 20 अप्रैल को राज्य में 12,201 नए मामले दर्ज किए. ठीक होने की दर मार्च में 98 प्रतिशत थी, जो घटकर 81 प्रतिशत पर आ गई है. 20 अप्रैल को जयपुर जिले में 2,011 मामले (अब तक सर्वाधिक), जोधपुर में 1,641 मामले और कोटा में 1,307 मामले दर्ज किए गए.

राज्य में दैनिक परीक्षण क्षमता 77,000 है, जिसे 100,000 तक बढ़ाया जा रहा है. निजी प्रयोगशालाओं में परीक्षण शुल्क 350 रुपए निर्धारित किया गया है. 60 प्रतिशत से अधिक सक्रिय मामले 45 वर्ष से कम आयु के लोगों में हैं, अप्रैल में जितने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से एक चौथाई पॉजिटिव मामला 21-30 आयु वर्ग का है. जयपुर में स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (आरयूएचएस) के कोविड अस्पताल में मार्च के औसत 30 मरीज के मुकाबले 19 अप्रैल को सभी 1,200 बिस्तर भरे हुए थे. कॉरीडोर में लगे करीब 150 बिस्तरों पर भी मरीज थे.

राज्य का दावा है कि उसके पास 3,000 वेंटिलेटर हैं पर से दो तिहाई काम कर रहे हैं. जिस गति से मामले बढ़ रहे हैं, गंभीर संकट आने वाला है. सरकार 12 जगहों पर प्लाज्मा थेरेपी उपलब्ध करवा रही है और 1,500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की प्रक्रिया चल रही है. सप्लाई में कमी का मतलब है कि कुछ अस्पताल भरे सिलेंडर ही दे रहे हैं.—रोहित परिहार

लंबा खिंचा संकट

पिछले वर्ष लॉकडाउन के बाद बड़े पैमाने पर उनके पलायन ने आम तौर पर अदृश्य रहने वाले कार्यबल के संकटों के बारे में हमारी आंखें खोली थीं. क्या उनकी दुर्दशापूर्ण स्थिति में कोई सुधार हुआ है?

कौशिक डेका

थककर चूर महाराष्ट्र से लौटे प्रवासी कामगार 10 अप्रैल 2021 को पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर आराम करते हुए

दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक कमरे की झुग्गी में रह रहे बिहार के बहादुरपुर गांव के 24-वर्षीय चंदर कुमार को एक सप्ताह से अधिक समय से लग रहा है कि वह अतीत को दोहराकर जी रहा है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एक घर में घरेलू कामगार के रूप में काम करने वाले कुमार का स्मार्ट फोन उसे दिल्ली में कोविड-19 मामलों की लगातार बदलती स्थिति की जानकारी देता रहता है. वह भ्रमित है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली नहीं छोड़ने की अपील के बावजूद वह और उसके दोस्त राष्ट्रीय राजधानी में 20 अप्रैल को घोषित सप्ताह भर के बंद के बारे में चिंतित हैं.

सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, सभी भारतीय शहरों में प्रवासी कामगार कोविड मामलों की ऊंची होती लहर और आंशिक लॉकडाउन तथा रात के कर्फ्यू जैसे प्रतिबंधों का बढ़ना देख कर आशंकित हैं. वायरस के डर से अधिक उन्हें आर्थिक अनिश्चितता का भय सता रहा है. पिछले मार्च की यादें अभी भी उनके दिमाग में ताजा हैं जब अचानक तालाबंदी ने उन्हें रोजगारहीन, भोजनहीन और घर वापसी के लिए साधनहीन बना दिया था. हताश होकर उनमें से अनेक लोग अपनी छोटी सी गृहस्थी और परिवार को साथ लेकर पैदल ही चल पड़े थे. इस बार वे कोई चूक नहीं करना चाहते. महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु और कर्नाटक में वे पहले से ही ट्रेन आरक्षण काउंटर पर कतार में लगे हैं. कुमार बताते हैं, ''मैंने

संतोष कुमार/गेट्टी इमेजेज

अगले हफ्ते का टिकट भी खरीद लिया है. उम्मीद करता हूं कि ट्रेनें रद्द नहीं होंगी.'' दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान भी अंतरराज्यीय ट्रेनें और बसें चलती रहेंगी, जिससे राहत मिलेगी. उधर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही बिहारी प्रवासियों से कोविड की उग्र होती दूसरी लहर के मद्देनजर जल्द लौटने का अनुरोध करते हुए कहा है कि सरकार वापसी करने वालों के लिए काम की व्यवस्था करेगी.

यहां तक कि आधिकारिक सूत्र भी स्वीकार करते हैं कि पिछले साल लॉकडाउन ने प्रवासियों की घर वापसी का ऐसा सिलसिला शुरू किया था जिसके परिणामस्वरूप विभाजन के बाद दूसरा सबसे बड़ा सामूहिक स्थान परिवर्तन हुआ. विभाजन के बाद 1.4 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे जबकि कौशल विकास मंत्रालय के डेटाबेस के अनुसार, पिछले साल के लॉकडाउन में छह राज्यों के 116 जिलों में 67 लाख प्रवासियों ने घर वापसी की थी. स्वतंत्र अनुमानों के अनुसार यह संख्या इससे बहुत ज्यादा, लगभग छह करोड़ या आधिकारिक गणना से नौ गुना अधिक थी.

आइसीआरआइईआर (इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस) और आइएसएसआरएफ (इनफरेंशियल सर्वे स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च फाउंडेशन) के एक

67
लाख
प्रवासी लॉकडाउन के बाद छह राज्यों के 116 जिलों में अपने घर लौटे, केंद्र सरकार के मुताबिक.

6
करोड़
प्रवासी श्रमिक लॉकडाउन के दौरान शहरों को छोड़कर गए, स्वतंत्र अनुमान के मुताबिक.

10
करोड़
करोड़ प्रवासी वर्ष 2016 में कार्यबल में शामिल थे, जैसा कि मार्च, 2020 में संसद में जानकारी दी गई.

11.17
करोड़
लोगों को वर्ष 2020-21 में मनरेगा से सहायता दी गई, जबकि 2019-20 में यह संख्या 7.88 करोड़ थी.

प्रवासियों की पहचान के प्रयास

पिछले साल लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को राहत देने के लिए कई अस्थायी योजनाएं शुरू की गई थीं, लेकिन एक व्यापक नीतिगत ढांचा विकसित होना बाकी है. इस दिशा में कुछेक कदम उठाए जा रहे हैं

- असंगठित श्रमिकों के एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस पर काम हो रहा है. परियोजना की अनुमानित लागत 704 करोड़ रुपये है
- प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और उनकी नौकरी की वरीयताओं का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है
- नीति आयोग ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक अंब्रेला पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया है-प्रवासी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना. नीति के समन्वित कार्यान्वयन के लिए यह एक प्रशासनिक ढांचा और अंतर्राज्यीय प्रवास के प्रबंधन के लिए एक तंत्र का प्रस्ताव करता है. इन प्रस्तावों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

हालिया अध्ययन में, छह राज्यों—उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जहां कुल कामगारों के दो तिहाई ने वापसी की थी- के 2,917 प्रवासियों का सर्वेक्षण कर लॉकडाउन के दौरान, उससे पहले और उसके बाद उनकी स्थिति का आकलन करने का प्रयास किया. अध्ययन में पाया गया कि 38.6 प्रतिशत लोगों को घर लौटने के बाद कोई काम नहीं मिला और घरेलू आय में लॉकडाउन के तत्काल बाद 85 प्रतिशत की गिरावट आई.

उत्तर प्रदेश के 32 साल के निर्माण मजदूर मनोज कुमार का ही मामला लीजिए जिन्हें लॉकडाउन में दिल्ली में नौकरी खोनी पड़ी थी. एक महीने तक घर लौटने के लिए संघर्ष करने के बाद जब आखिरकार मई के अंत में वे संत रविदास नगर जिले में अपने गांव कसिदहा पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वहां उनके लिए कोई काम नहीं था. जुलाई तक वे दिल्ली वापस आ गए थे. अंबेडकर नगर जिले के अन्नूपुर गांव के उनके मित्र चमन कुछ अधिक भाग्यशाली थे. घर पहुंचने के दो हफ्तों के भीतर चमन को राज्य के अधिकारियों ने मनरेगा (महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005) के तहत काम का प्रस्ताव किया था.

प्रवासियों की दुर्दशा को देखते हुए नीतिगत हस्तक्षेप और उनकी जीवन-दशाओं में सुधार के लिए दीर्घकालिक उपायों के लिए पिछले दिनों काफी शोरगुल हुआ था. भारत में इस बेआवाज जनसांख्यिकीय वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कभी कोई व्यापक कानून ही नहीं था; अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (सेवा का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 के प्रावधान केवल किसी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती किए गए लोगों पर लागू होते हैं. गत 29 सितंबर को इस अधिनियम को एक अधिसूचना के माध्यम से व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें (ओएसएच) संहिता, 2020 के अधीन लाया गया था. संहिता में अच्छी कार्यदशाओं, न्यूनतम मजदूरी, शिकायत निवारण तंत्र, दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा तथा प्रवासी श्रमिकों सहित संगठित और असंगठित सभी श्रेणियों के श्रमिकों के कौशल तथा सामाजिक सुरक्षा के संवर्धन की व्यवस्था की गई है. यह संहिता हर उस प्रतिष्ठान पर लागू होती है जिसमें पिछले साल में एक भी दिन 10 या उससे अधिक अंतर-राज्य प्रवासियों की नियुक्ति रही हो.

इसके अलावा, केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष कुमार गंगवार ने 22 मार्च को लोकसभा में जो कहा उसके अनुसार, ''प्रवास संबंधी समस्याओं के निदान के लिए बहुमुखी कार्रवाई की जानी है जिसमें ग्रामीण विकास, बेहतर बुनियादी सुविधाएं, क्षेत्रीय विषमताएं दूर करने के लिए संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा, रोजगार सृजन, भूमि सुधार, साक्षरता उन्नयन, वित्तीय सहायता और विभिन्न सरकारी कल्याण व सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शामिल हैं.''

गंगवार के मंत्रालय के अनुरोध पर नीति आयोग ने 'प्रवासी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना' नामक छत्र नीति का ढांचा तैयार किया है. इसमें सामाजिक संरक्षण की स्थान-परिवर्तनीयता, मताधिकार, नगरीय अधिकार तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास सुविधाओं को उनकी जीवन दशाओं में सुधार के मुख्य बिंदुओं के रूप में पहचाना गया है. नीति आयोग का मसौदा इसके समन्वित कार्यान्वयन के लिए एक शासनिक ढांचे की भी संस्तुति करता है जिसमें श्रम मंत्रालय को नोडल बिंदु बना कर उसके अधीन एक समर्पित इकाई की स्थापना की जाएगी जो अंतर-मंत्रालय तथा केंद्र-राज्य समन्वय पर ध्यान केंद्रित करेगी. इसमें विशेष रूप से प्रमुख प्रवास गलियारों पर अंतर-राज्य प्रवास के संबंध में होने वाले प्रयासों को समन्वित करने के तंत्र का भी प्रस्ताव किया गया है.

आलोचकों का कहना है कि नीति आयोग का मसौदा प्रवासियों की क्षमताओं के दोहन के लिए उन्हें सुविधाएं देने या नगदी हस्तांतरण जैसे उपायों के बजाए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की वकालत तो करता है, लेकिन उनका संकट कम करने के लिए संरक्षित मजदूरी तक पहुंच के सवाल को संबोधित नहीं करता. यह एक हद तक प्रवास रोकने के लिए स्रोत राज्यों को न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए कहता है लेकिन सामाजिक सुरक्षा कवर के रूप में किसी तरह की न्यूनतम वेतन गारंटी की बात नहीं करता.

यह चुप्पी महत्वपूर्ण है, विशेषकर लॉकडाउन के बाद की अवधि में जब कई राज्यों ने आर्थिक पुनरुत्थान को आसान बनाने के लिए श्रम सुरक्षा ढांचे को कमजोर कर दिया. अक्सर तर्क दिया जाता है कि गारंटीशुदा मजदूरी के कारण व्यवसाय बंद हो जाएंगे और रोजगार का नुक्सान होगा जबकि पर्याप्त रूप से इसके विपरीत साक्ष्य मौजूद हैं. आर्थिक सर्वेक्षण (2019) सहित सरकार की रिपोर्टें इस तथ्य को उजागर करती हैं कि वास्तविक मजदूरी में ठहराव से गरीबों की खपत क्षमता घटी है, जिससे अर्थव्यवस्था में मंदी आई है. रिसर्च ऐंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज (आरआईएस) के विशिष्ट फेलो प्रो. अमिताभ कुंडू कहते हैं, ''उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने श्रम कानूनों को सीमित कर

> प्रवासी मजदूरों के लिए **राष्ट्रीय कार्ययोजना में न्यूनतम वेतन** गारंटी पर चुप्पी खतरनाक है, वह भी ऐसे समय में जब राज्य **श्रम कानून शिथिल** कर रहे हैं

दिया है. कठिनाई से मिले श्रमिक अधिकारों को कमजोर कर दिया गया है. राज्यों को औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानूनों में दी गई छूटों पर पुनर्विचार करना चाहिए.''

प्रवासियों की गणना

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत का योगदान देने के बावजूद प्रवासियों के काम और रहने तथा उनकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में कहीं कोई दस्तावेज नहीं है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल 20 मई को यह बात स्वीकार की थी, जब उन्होंने कहा था कि सरकार के पास प्रवासियों का कोई आंकड़ा नहीं है. इसी वजह से नीति आयोग के मसौदे में जिन बातों की सबसे पहले संस्तुति की गई है उनमें प्रवासियों पर एक केंद्रीय डेटाबेस बनाना शामिल है. गंगवार का कहना है कि सरकार लगभग 704 करोड़ रुपए की लागत से असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) विकसित कर रही है जिसमें प्रवासी श्रमिक शामिल होंगे. 31 मार्च को केंद्र सरकार ने प्रवासी कामगारों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और काम के मामले में उनकी बदलती प्राथमिकताओं को समझने के लिए एक सर्वेक्षण शुरू किया है. सर्वेक्षण के सह-अध्यक्ष प्रो. कुंडू कहते हैं, ''हमारा सर्वेक्षण तीन चित्र देगा. पहला, पिछले साल फरवरी-मार्च में कोविड फैलने के पहले की स्थिति. दूसरा, सितंबर-अक्तूबर 2020 में जब कोविड का प्रभाव चरम पर था और तीसरा, मौजूदा स्थिति. हम यह भी देखने में सक्षम होंगे कि इस तरह की स्वास्थ्य आपदाएं अनौपचारिक श्रमिकों को कैसे प्रभावित करती हैं.'' असंगठित श्रमिकों पर आंकड़े एकत्र करने और उनके स्वास्थ्य, आवास, कौशल, बीमा, वित्तीयन और भोजन पर नीतियां बनाने के लिए सूचना पोर्टल स्थापित करने की दिशा में यह पहला कदम हो सकता है.

पैसे कहां हैं?

वित्तमंत्री सीतारमण ने इस वर्ष के बजट में प्रवासियों का संकट कम करने के लिए उपायों की घोषणा की थी. इनमें 'एक देश, एक राशन कार्ड' प्रस्ताव था जो एक स्थान-परिवर्तन योजना है जिसके माध्यम से गरीब प्रवासी देश में कहीं भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से सब्सिडी वाले खाद्यान्न ले सकते हैं. हालांकि, यह योजना अब तक सभी राज्यों ने लागू नहीं की है.

लेकिन फिर, एक कदम पीछे जाते हुए नीति आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी 75 से घटाकर 60 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 50 से कम कर 40 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव रखा है. नवंबर 2020 में, केंद्र ने पीडीएस के माध्यम से अतिरिक्त खाद्यान्न की आपूर्ति भी बंद कर दी. सेंटर फॉर वूमेंस डेवलपमेंट स्टडीज की पूर्व निदेशक, इंदु अग्निहोत्री कहती हैं, ''पीडीएस के माध्यम से मिलने वाले खाद्यान्नों के पैमाने और आपूर्ति में कमी बहुत चौंकाने वाली है.'' आइसीआरआइईआर-आइएसएसआरएफ के अध्ययन में यह भी कहा गया है कि सर्वेक्षण में शामिल 74 फीसदी प्रवासियों को ही सब्सिडी वाले खाद्यान्न मिला जबकि केवल 12 फीसदी को सब्सिडी वाली दाल मिली थी. पिछले साल लॉकडाउन के दौरान जब केंद्र ने कोविड राहत पैकेज में 80 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को प्रति माह बिना राशन कार्ड के पांच किलो गेहूं और एक किलो दाल बांटी थी, तब भी बहुत से लोग इससे वंचित रह गए थे. उदाहरण के लिए ओडिशा के केंद्रपाड़ा के प्लंबर अजय (38) लॉकडाउन के दौरान दो महीने तक दिल्ली में बेरोजगार रहे, लेकिन दो बार फॉर्म भरने के बावजूद उन्हें और उनके भाई प्रमोद

सभी फोटोः राजवंत रावत

केस स्टडी

मनोज कुमार 32 वर्ष और चमन 18 वर्ष

पेशाः निर्माण श्रमिक

रोजगार का शहरः दिल्ली

मूल राज्यः उत्तर प्रदेश

2020 के लॉकडाउन में हुई मुश्किल : दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक साथ रहने वाले ये दोनों श्रमिक दो महीने तक बिना नौकरी के दिल्ली में फंसे रहे. बाद में दोनों ट्रेन से उत्तर प्रदेश चले गए, लेकिन दो महीने के भीतर ही मनोज दिल्ली लौट आया, क्योंकि उसे अपने गांव में उसे कोई काम नहीं मिला. चमन ने मनरेगा के तहत काम किया और फिर नवंबर में दिल्ली लौट आया. इस साल घर जाने का उनका कोई इरादा नहीं है.

सरकारी सहायताः दोनों को अनाज की कोई सहायता नहीं मिली.

को राशन नहीं मिला. लेकिन दिल्ली के लालबाग में रहने वाले 33 वर्षीय निर्माण श्रमिक सूर्य नाथ भाग्यशाली रहे क्योंकि उन्हें दो महीने तक खाद्यान्न मिला. उन्हें रात में 2 बजे से लाइन में खड़े होना पड़ता था, लेकिन पत्नी, नौ साल की बेटी और तीन साल के बेटे समेत चार लोगों के उनके परिवार के लिए यह जीवनदायी रहा.

इस साल, अब तक, केंद्र ने प्रवासियों के लिए किसी पैकेज की घोषणा नहीं की है. महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में 15 दिन का कर्फ्यू लगाने से एक दिन पहले 14 अप्रैल को 5,476 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की. इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत सात करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल, प्रति दिन 200,000 मुफ्त लंच पैकेट और पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, हॉकरों और ऑटोरिक्शा चालकों को एकमुश्त भुगतान के रूप में 1,500 रुपए दिए जाने हैं. दिल्ली सरकार ने भी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है. इस तरह के उपायों का स्वागत है, लेकिन इनका लक्ष्य लाभार्थियों तक पहुंचना चुनौती बना हुआ है. महाराष्ट्र में, 2016 में लगभग 560,000 पंजीकृत निर्माण श्रमिक थे, लेकिन उनमें से 50 प्रतिशत पिछले साल अमान्य पाए गए थे. वास्तव में, भारत भर में अधिकांश निर्माण श्रमिक अपंजीकृत हैं. यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण शुरू किया है, जिससे नए पंजीकृत लोग भी लाभान्वित हो सकते हैं.

केंद्र का मानना है कि आत्मनिर्भर भारत और सेक्टर-विशेष पर जोर देने का प्रवासियों को सीधा लाभ मिल सकता है. गंगवार कहते हैं, ''आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत रु. 27 लाख करोड़ का वित्तीय पैकेज दिया गया है जिससे अन्य चीजों के अलावा प्रवासी तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को रोजगार देने, एमएसएमई को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का काम होगा.''

बजट में अन्य योजनाएं भी थीं. कृषि, विनिर्माण, सार्वजनिक सेवाएं और निर्माण जैसे प्रवासी श्रमिकों को बड़ी संख्या में सेवायोजित करने वाले 13 क्षेत्रों समेत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए पांच वर्षों में 1.97 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित है. निर्माण उद्योग में लगभग 5.1 करोड़ कामगार हैं, जिनमें से लगभग आधे के मौसमी प्रवासी होने का अनुमान है. फिर कपड़ा क्षेत्र है जो भारत में रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है जिसके दिल्ली, तिरुपुर तथा बेंगलूरू जैसे बड़े परिधान केंद्रों में 70 प्रतिशत कर्मचारी चक्रीय या अस्थायी प्रवासी हैं (2017 आइएलओ रिपोर्ट). आगामी तीन वर्षों में सात मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना के साथ इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 700 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें प्रवासी मजदूरों को काम मिल सकता है. परंतु, पर्यटन और आतिथ्य जैसे महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों को कोई सीधी मदद नहीं मिली.

बजट में सबसे बड़ी निराशा प्रवासी संकट के उपरिकेंद्र रहे शहरी क्षेत्रों के लिए बहुत कम वित्त पोषण की रही है. श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम, रोजगार और कौशल विकास पर खर्च में लगभग 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है, लेकिन कुल रु. 54,581 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ शहरी विकास को कुल बजट का मात्र 1.5 प्रतिशत मिला है. वास्तव में, शहरी स्थानीय निकायों का कुल परिव्यय पिछले साल के रु. 25,098 करोड़ की तुलना में वर्तमान में रु. 22,114 करोड़ ही रह गया है. आवासन क्षेत्र को देखें तो जून 2020 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना की उप-योजना के रूप में सस्ते किराये वाले आवासीय संकुलों की योजना की घोषणा की थी. योजना का लक्ष्य 300,000 लाभार्थी थे. योजना में मार्च 2022 तक कर अवकाश दिया गया है, लेकिन महामारी में यह अब केवल कागज पर है.

देश में **95%** प्रवासियों ने लॉकडाउन में रोजगार गंवाया और उबारने के प्रयासों में केवल **7%** को ही मनरेगा का लाभ मिला

बचाव के लिए मनरेगा

देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा एक सुरक्षा जाल के रूप में उभरा है. 2020-2021 में 1 अप्रैल 2021 तक 11.17 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया जबकि 2019-20 में लाभार्थियों की संख्या 7.88 करोड़ थी. फिर भी, पिछले साल अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के एक अध्ययन से पता चला है कि लॉकडाउन के दौरान जब भारत के 95 प्रतिशत आंतरिक प्रवासियों की नौकरी चली गई थी, तब मनरेगा के माध्यम से उन्हें काम देने के प्रयासों से केवल 7 प्रतिशत लाभान्वित हुए. यह निष्कर्ष आइसीआरआइईआर-आइएसएसआरएफ के अध्ययन से भी निकला था. हालांकि मनरेगा के तहत मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए प्रति दिन कर दी गई थी, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि शहरी श्रमिकों के लिए यह अपर्याप्त है. शायद यह भी एक कारण है कि ओडिशा के नाथ और उनके भाइयों ने घर वापस जाने का फैसला करने के पहले इंतजार करने का फैसला किया है. अजय और प्रमोद कहते हैं, ''वापस जाना कोई समाधान नहीं है क्योंकि हम अपने गांव में पर्याप्त कमाई नहीं

केस स्टडी

अजय 38 वर्ष

पेशा: प्लंबर

रोजगार का शहर: दिल्ली

मूल राज्य: ओडिशा

2020 के लॉकडाउन में हुई मुश्किल: वह अपने भाई के साथ दिल्ली के मसूदपुर में रहता है. लॉकडाउन के दौरान वे तीन महीने तक बेरोजगार रहे. उसका भाई घर चला गया, लेकिन गांव में उसे कोई काम नहीं मिला. अक्तूबर में वह दिल्ली लौट आया. इस साल, वे इंतजार करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है.

सरकारी सहायता: कोई सहायता नहीं मिली.

केस स्टडी

सूर्यनाथ 33 वर्ष

पेशा: निर्माण श्रमिक

रोजगार का शहर: शहर-दिल्ली

मूल राज्य: ओडिशा

2020 के लॉकडाउन में हुई मुश्किल: वे अपनी पत्नी, नौ साल की बेटी और तीन साल के बेटे के साथ दिल्ली के लालबाग इलाके में रहते हैं. लॉकडाउन के दौरान तीन महीने तक बेरोजगार रहे और 25,000 रुपये उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा. हालांकि वे पिछले जून में बिहार में अपने गांव गए थे, लेकिन एक महीने के भीतर ही वे लौट आए, क्योंकि मनरेगा से कमाए पैसे उनके परिवार के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं थे.

सरकारी सहायता: सरकार की तरफ से दो महीने का अनाज-गेहूं और दाल-मिला.

कर सकते.'' यहां तक कि उत्तर प्रदेश के दो निर्माण मजदूरों- मनोज और चमन- ने भी कम से कम एक सप्ताह के लिए कार्यस्थल पर ही रहने का फैसला किया है.

सेंटर फॉर माइग्रेशन ऐंड इनक्लूसिव डेवलपमेंट के सह-संस्थापक और कार्यकारी निदेशक बेनॉय पीटर कहते हैं, ''अगर किसी श्रमिक को अपने घर के पास मजदूरी के रूप में औसतन करीब 10,000 रुपए महीने मिलें, तो उनमें से ज्यादातर शहर नहीं जाएंगे जहां उनके साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार होता है. लेकिन भारत के गांवों में 10,000 रुपए मिलना भी अभी दूर का सपना है. प्रवासन घटाने के लिए मनरेगा के तहत काम कोई हल नहीं है क्योंकि उसमें बहुत कम मजदूरी, भ्रष्टाचार, संवितरण की धीमी प्रक्रिया और ग्रामीण परिवारों का सीमित वित्तीय समावेशन है.''

महामारी के कारण कामगारों की घर वापसी सरकार के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण, आजीविका के अवसरों का सृजन और ग्रामीण शासन में सुधार लाने के साथ ही बेहतर कृषि नीति लाने का एक अवसर थी. प्रो. अग्निहोत्री कहते हैं, ''हमें यह पूछने की जरूरत है कि क्या इस मूलभूत समस्या के समाधान के लिए कोई उपाय किए गए.

गरीब कल्याण रोजगार अभियान ऐसा ही एक उपाय था. जून, 2020 में शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे और गावों में इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाओं का निर्माण करना था. इसमें ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को घर के करीब रोजगार पाने की संभावना बढ़ाने के लिए उनका कौशल मानचित्रण भी किया जाता है. 50,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ, यह योजना छह राज्यों में 116 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने और बुनियादी ढांचा बनाने के 25 लक्ष्य-संचालित कार्यों के कार्यान्वयन पर केंद्रित है. गंगवार का दावा है कि इस अभियान से अब तक 50.8 करोड़ मानव-दिवसों के रोजगार का सृजन हुआ है. मनरेगा के तहत कार्यदिवसों की संख्या को दोगुना करके 200 प्रति वर्ष प्रति परिवार करने की भी मांग होती रही है. फिर भी, इन रोजगार योजनाओं से बहुतों को लाभ हुआ नहीं लगता क्योंकि ये या तो प्रवासियों तक पहुंचने में विफल रही हैं, या फिर जैसा कि आइएलओ अध्ययन कहता है, घर वापसी करने वाले प्रवासी मनरेगा के काम नहीं करना चाहते.

सीमित विकल्पों के कारण बहुत से लोग प्रवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रावधान के रूप में शहरी रोजगार गारंटी योजना की वकालत करते हैं. वास्तव में, अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों में सामाजिक सुरक्षा सार्वभौमिक मानवीय अधिकार है और भारत इसका हस्ताक्षरी है. 2004 में स्थापित असंगठित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यम आयोग (एनसीईयूएस) ने 2006 में साबित किया था कि न्यूनतम स्तर पर सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना आर्थिक रूप से संभव है. आयोग ने सार्वभौमिक पंजीकरण प्रणाली और स्मार्ट सामाजिक सुरक्षा कार्डों की भी संस्तुति की, लेकिन उन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है.

परंतु इस क्षेत्र के हितधारकों को जल्द ही बदलाव की उम्मीद है. पीटर कहते हैं कि ''हालांकि ऐसा बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, फिर भी भारत ने प्रवासियों के काम और जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस संकट का लाभ उठाया है. ये कदम देरी से उठाए गए हैं, परंतु सरकार ने उनकी परेशानियां कम करने के लिए कई उपाय किए हैं. मेरे हिसाब से यह अच्छी शुरुआत है.'' बहरहाल, चुनौती इस गति को बनाए रखने की है, विशेष रूप से तब जबकि एक और गंभीर कोविड लहर आर्थिक स्थितियों में सुधार को धक्का पहुंचा सकती है. ■

कोविड की काली छाया

दूसरी लहर में कोविड-19 के मामलों पर काबू के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाने से इनकार किया है लेकिन कई राज्यों में कड़ी पाबंदियां लागू होने से कारोबार पहले से मुश्किल का सामना कर रहे हैं

श्वेता पुंज और एम.जी. अरुण

कोविड-19 की तुलना अक्सर स्पेनिश फ्लू से की गई है, जिसमें 1918 से 1920 के बीच करीब 5 करोड़ लोग मारे गए थे. उस फ्लू की एक मनहूस खासियत संक्रमण की एकाधिक विनाशकारी लहरें थीं, कुछ उसी तरह जैसे कोरोनावायरस के मामले में देखा जा रहा है. इस साल फरवरी में जब यूरोप कोविड-19 के मामलों की दूसरी जबरदस्त लहर की चपेट में था, भारत अपनी पीठ थपथपा रहा था, यह सोचकर कि उसने वायरस पर काबू पा लिया है और 2020-21 की पहली छमाही में मंदी झेलने के बाद देश आर्थिक बहाली की राह पर है. मध्य मार्च आते-आते वह उजला आशावाद झूठा साबित हुआ, जब भारत में भी कोविड के मामले एक बार फिर उछाल भरने लगे. 20 अप्रैल को भारत में महज 24 घंटों के भीतर 2,59,000 नए मामले और 1,761 मौतें दर्ज की गईं.

कई राज्य सरकारें अब सार्वजनिक आवाजाही पर पाबंदियां लगा रही हैं. (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

आर्थिक दुष्प्रभावों के डर से केंद्र सरकार राष्ट्रीय लॉकडाउन **लगाने के प्रति उत्सुक नहीं दिख रही है**

20 अप्रैल को दिल्ली के थोक बाजार सदर में पसरा हुआ सन्नाटा

राजवंत रावत

3.3
करोड़
लोग मध्यवर्ग में घट गए साल 2020 में(अनुमानित), पहले ये संख्या 9.9 करोड़ थी दैनिक आय के आधार पर

7.5
करोड़
बढ़ गई भारत में गरीबों की संख्या (अनुमानित) 2020 में दैनिक आय के आधार पर

20 अप्रैल को नए राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाने की बात नकार चुके हैं) ऐसे में कई लोग पूछ रहे हैं कि भारत की नाजुक आर्थिक बहाली पर इसके क्या नतीजे होंगे. इसमें कोई शक नहीं कि स्वास्थ्य सर्वोपरि है. अब भी कमजोर मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर से लड़खड़ाती हुई केंद्र और राज्य सरकारें जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद में लगी हैं. वहीं लॉकडाउन की आर्थिक कीमत समझी जा चुकी हैं और इसे लागू करना बहुत सख्त विकल्प होगा.

पिछले साल भारत ने दुनिया का एक सबसे कठोर लॉकडाउन लगाया था, ताकि चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को पराजित होने से बचाया सके और राज्य तथा निजी क्षेत्र को वायरस से निपटने के लिए चिकित्सा क्षमताएं बढ़ाने का वक्त मिल सके. इसका नतीजा यह हुआ कि भारत 40 सालों में अपनी पहली मंदी में धंस गया और वित्त वर्ष 2021 की पहली और दूसरी तिमाहियों में जीडीपी ग्रोथ ढहकर क्रमश: -23.9 और -7.5 फीसद पर आ गई. इसकी मानवीय कीमत में लाखों नौकरियों का जाना भी शामिल था. प्यू रिसर्च सेंटर का 18 मार्च का एक विश्लेषण अनुमान जाहिर करता है कि भारत के मध्य वर्ग यानी रोज 10-20 डॉलर (750-1,500 रुपए) कमाने वालों की तादाद 2020 में 3.2 करोड़ घट गई. वहीं भारत के गरीबों (2 डॉलर या 150 रुपए या उससे भी कम कमाने वालों) की तादाद 7.5 करोड़ बढ़ गई. सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनोमी (सीएमआईई) का कहना है कि पिछले साल अप्रैल और सितंबर के बीच 1.9 करोड़ वेतनभोगी अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे, जबकि एसकेओसीएच या स्कॉच ग्रुप के सर्वे का अनुमान है

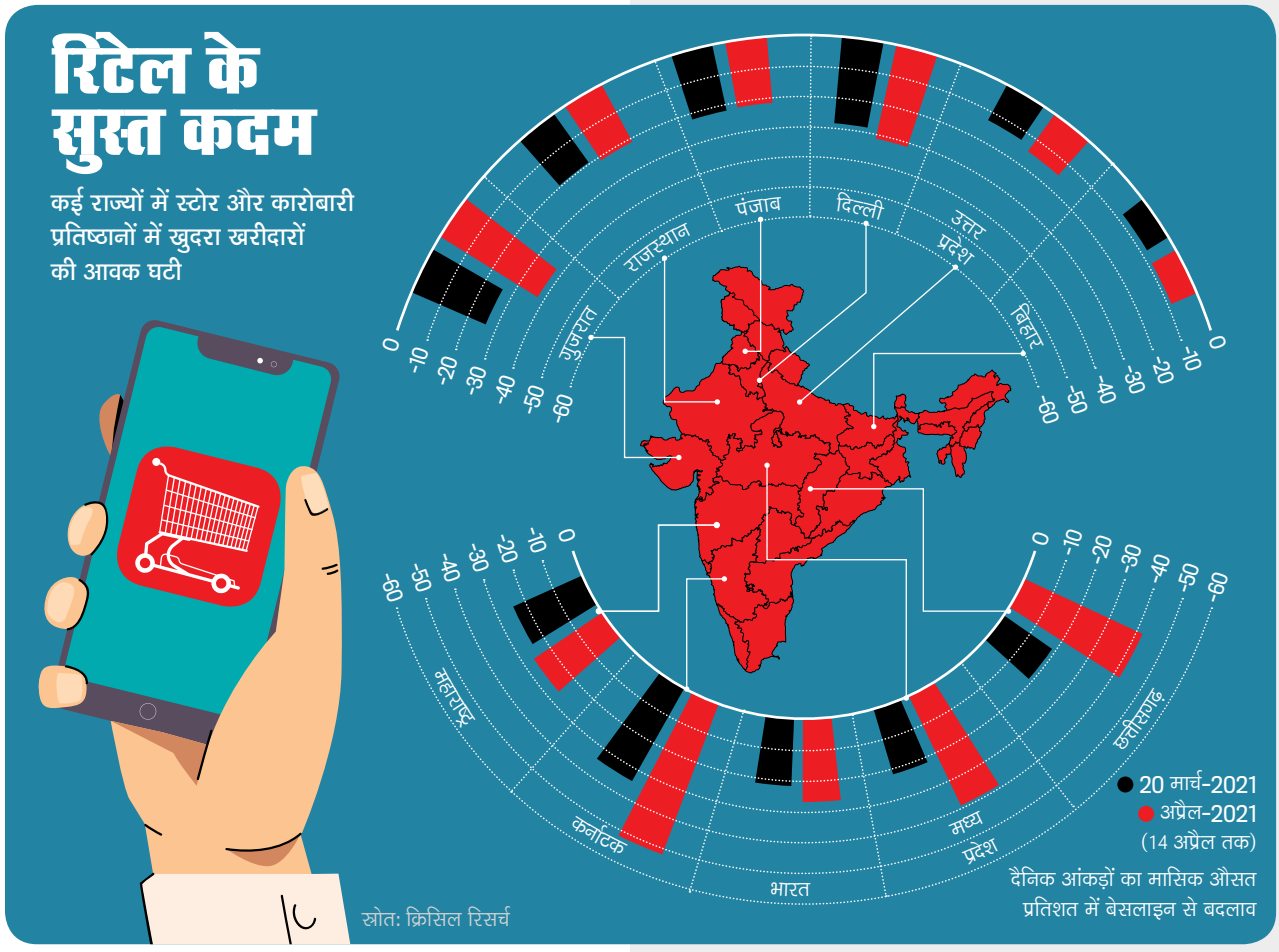

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

कि जून 2020 के आखिर तक एसएमएमई (सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों) में 2.5-3 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गईं. दरकिनार समूहों के लिए कार्यरत एनजीओ ऐक्शनऐड इंडिया का डेटा कहता है कि पिछले साल लॉकडाउन के चलते अनौपचारिक क्षेत्र के 80 फीसद कामगार अपने काम-धंधे गंवा बैठे.

एक अनियोजित लॉकडाउन के परिणाम देख चुके नीति निर्माता अब इसे अंतिम उपाय के रूप में अपनाने के सिवाय लागू करने के प्रति अनिच्छुक दिखे. 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय लॉकडाउन से इनकार करते हुए कहा कि ये आखिरी विकल्प होना चाहिए और राज्य सरकारों से अपील की कि वे बुरी तरह प्रभावित जिलों के लिए माइक्रो कंटेनमेंट रणनीति अपनाएं. केंद्र आगे बढ़कर औद्योगिक समूहों के पास भी पहुंचा और उन्हें भरोसा दिलाया कि राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं किया जा रहा है. 18 अप्रैल को एमएसएमई इकाइयों के मालिकों के साथ बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन बनाने पर ध्यान दिया जाएगा.

भारतीय उद्योग जगत के लोग भी पूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ हैं. सीआइआइ (कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) के 710 सीईओ के एक हालिया सर्वे ने बताया कि उनमें से 93 फीसद आंशिक लॉकडाउन के खिलाफ थे. उनमें से तीन-चौथाई ने कहा कि औद्योगिक उत्पादन पर इसका अच्छा-खासा असर पड़ेगा और इसके बजाय सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करवाना चाहिए. उद्योग की संस्था फिक्की ने 25 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर किसी भी किस्म के लॉकडाउन से बचने का आग्रह किया और कहा कि कोविड की शृंखला को ज्यादा टेस्ट, ज्यादा अमल और जन जागरूकता अभियानों के जरिए तोड़ना चाहिए. वर्ल्ड बैंक ग्रुप के चीफ इकॉनोमिस्ट कारमेन रेनहार्ट ने हाल के एक इंटरव्यू में कहा कि भारत सरीखे विकासशील देशों के लिए कठोर लॉकडाउन कोई उपाय नहीं है और ''कुछ लचीलेपन की मोहलत देने वाली कम कठोर (वायरस

50 से 60 फीसदी कर्मचारी अब हमारी फैक्ट्री में ही रह सकते हैं. ऐसे में **उत्पादन बाधित नहीं हुआ है.**

—राकेश छाबड़ा, प्रेसिडेंट, राई इंडस्ट्रियल एरिया, सोनीपत और सदस्य, एफआइएमएसएमई बोर्ड

प्रबंधन नीतियों)'' का सुझाव दिया.

भारत के जीडीपी में करीब 15 फीसद का योगदान देने वाले महाराष्ट्र ने, जहां नए कोविड मामले देश में सबसे ज्यादा हैं, अभी तक सबसे कठोर उपाय लागू किए हैं. सप्ताहांत में लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू के साथ अप्रैल के आखिर तक गैर-अनिवार्य सेवाएं बंद कर दी गई हैं. 14 अप्रैल से महाराष्ट्र में 1 मई तक पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिससे केवल अनिवार्य सेवाओं और निर्यात इकाइयों को छूट दी गई है. 17-18 अप्रैल को सप्ताहांत कर्फ्यू के बाद दिल्ली में 19 अप्रैल की शाम से सप्ताह भर लंबा कर्फ्यू शुरू हो गया, जबकि पड़ोसी उत्तर प्रदेश ने 17 अप्रैल से 35 घंटे के कर्फ्यू का ऐलान किया. भोपाल, इंदौर और बेंगलूरू सरीखे कई शहरी केंद्रों के स्थानीय प्रशासनों ने कर्फ्यू लगा दिए.

इस बार कर्फ्यू से लक्ष्यबद्ध छूट दी गई है. महाराष्ट्र ने अनौपचारिक क्षेत्र के सबसे बड़े रोजगार प्रदाता निर्माण क्षेत्र के कार्य जारी रखे हैं (अगर कामगार निर्माण स्थल पर ही रह रहे हों और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया गया हो). महाराष्ट्र से आने और जाने वाले ट्रकों की आवाजाही कर्फ्यू के बाद आधी रह गई है, जिसका असर फल, सब्जियों और कच्चे माल सरीखी जरूरी चीजों की ढुलाई पर पड़ा है. ट्रांसपोर्ट कंपनियां ड्राइवरों की कमी बता रही है, जब लोग कोविड के डर से राज्य छोड़कर जा रहे हैं.

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वित्त वर्ष 2021-22 के आंकड़ों का अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन वे बताते हैं कि अगले कुछ महीने बेहद अहम होंगे. शीर्ष ब्रोकरों ने मोटे तौर पर 1 फीसद की चपत लगने का अनुमान जताया है. केयर रेटिंग्ज के चीफ इकॉनोमिस्ट मदन सबनवीस कहते हैं, ''(अगर पाबंदियां जारी रहीं)ग्रोथ 10 फीसद से भी नीचे गिर सकती है.'' (जीडीपी ग्रोथ पिछले साल के आंकड़े में बदलाव के रूप में आंकी जाती है. नाम भर के लिए ऊंची दर—10 फीसद—पिछले साल के निचले आधार का नतीजा है, मजबूत वृद्धि का नहीं.) शेयर बाजार पहले ही दहशत में मालूम देते हैं. सेंसेक्स 12 अप्रैल को 1,707.94 अंकों की भारी गिरावट का शिकार हुआ, जो 26 फरवरी के बाद इसकी सबसे बड़ी गिरावट थी. फरवरी के आइआइपी (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक) के आंकड़े भी छह महीनों से सबसे निचले स्तर -3.6 फीसद पर आ गए, जो बताते हैं कि भारत की आर्थिक बहाली कितने नाजुक दौर में है.

फोर्ब्स मार्शल के चेयरमैन नौशाद फोर्ब्स ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा, ''महाराष्ट्र में तमाम गैरजरूरी चीजों की बंदी अगर 1 मई तक ही जारी रहती है, तो यह (बहुत ज्यादा) नुक्सानदेह नहीं होगी. उपभोक्ता शर्ट या टीवी की खरीदारी तीन हफ्तों के लिए बस टाल भर रहे होंगे. लेकिन अगर यह 1 मई के बाद भी जारी रहती है तो नतीजे कहीं ज्यादा बड़े होंगे.'' आइसीआरए में चीफ इकॉनोमिस्ट अदिति नैयर कहती हैं, ''धारणाओं के बिगड़ने के साथ 2022 के वित्त वर्ष के पहले आधे हिस्से में मांग में कुछ कमी आ सकती है और साल के पहले हिस्से की कुछ मांग साल के दूसरे हिस्से में जा सकती है.'' आइसीआरए ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ के करीब 10-10.5 फीसद रहने की उम्मीद जाहिर की है, जो उसके पहले के 10-11 फीसद के अनुमान से कम है.

आर्थिक विकास पर संशय

भारत में आर्थिक विकास दर के अनुमान घटा दिए गए हैं, सतर्क आशावादी संकेतों के साथ

विकास के अनुमान
(वित्त वर्ष 2022, आकलन)

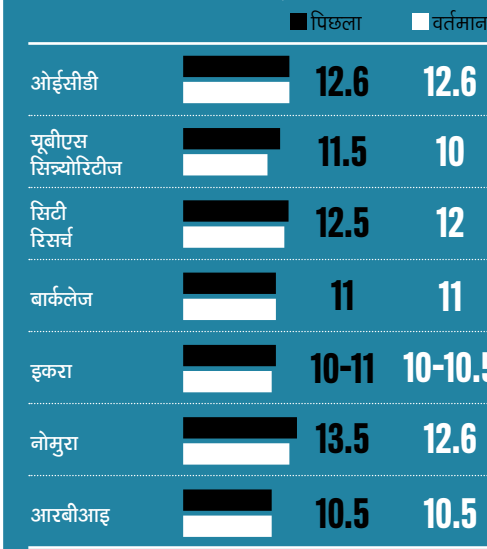

ईवाइ इंडिया के पॉलिसी एडवाइजर डी.के. श्रीवास्तव कहते हैं कि पहली तिमाही के वृद्धि के अनुमान घटाकर कम करने पड़ सकते हैं, जिससे वित्तीय साल 2021-22 के समग्र पूर्वानुमान भी कम हो जाएंगे. वे कहते हैं, ''भारत में वैक्सीन का (राष्ट्रीय) वितरण अभीष्ट से बहुत कम साबित हो रहा है. हम उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन की जरूरत अगले पांच सालों तक बनी रहेगी. इसे दुरुस्त करना बेहद जरूरी है.'' पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का अनुमान है कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही की वृद्धि 2019-20 के वित्त वर्ष से भी कम रहेगी. वे कहते हैं, ''हमें रोज 4,00,000 केसों के लिए तैयार रहना चाहिए.'' जहां हाई फ्रीक्वेंसी या उच्च आवृत्ति संकेतक तत्काल चिंताजनक नहीं हैं, वहीं कुछ संकेतक खुदरा आवाजाही (स्टोर और मनोरंजन स्थलों पर आने वाले उपभोक्ताओं की तादाद) में गिरावट दिखा रहे हैं. उम्मीद है कि कृषि एक बार फिर अकेला उजला आर्थिक क्षेत्र साबित होगा, जिसकी वृद्धि 2021-22 में 3.5 फीसद रहने का अनुमान है.

सच यह है कि सत्ता प्रतिष्ठान संक्रमणों की दूसरी लहर के लिए कतई तैयार नहीं थे. पिछले साल की पहली पूर्णबंदी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था खासी तेजी से खुली और मॉल, जिम के साथ धार्मिक मेलों तथा राजनैतिक रैलियों सरीखी गतिविधियों के ऊंची जोखिम वाले क्षेत्रों से पाबंदियां हटाई जा रही थीं. ऐसे में मास्क लगाने के अनुशासन में ढिलाई आ गई जबकि वैक्सीन की शुरुआत गड़बड़ा गई. दि न्यूयॉर्क टाइम्स का अनुमान है कि इजराइल की करीब 56

धीमे पड़ते माल परिवहन के पहिए

परिवहन नियमों के सुचारू होने से पहले अप्रैल के मध्य से ई-वे बिल में तेज गिरावट देखने को मिली.

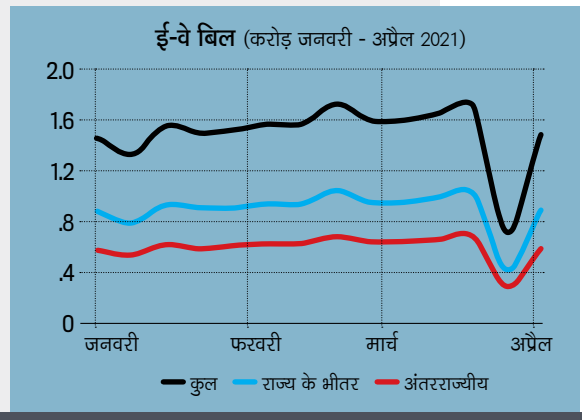

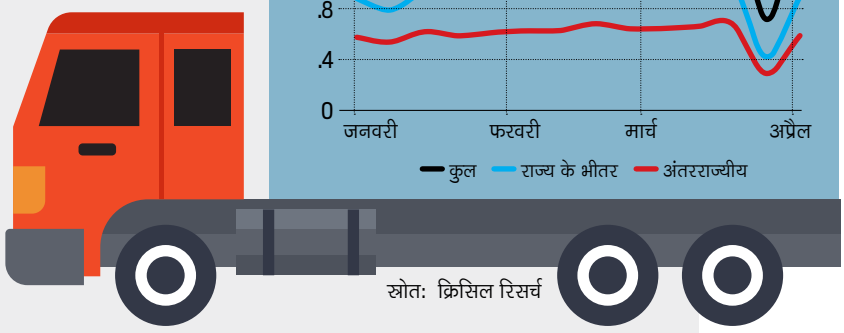

स्रोत: क्रिसिल रिसर्च

घटी बिजली की खपत

बिजली की खपत का घटना अर्थिक गतिविधियों में धीमेपन को दर्शा रहा है

स्रोत- क्रिसिल रिसर्च

फीसद आबादी को पूर्ण टीका लग गया है जबकि भारत में यह 1.3 फीसद है. नई मेडिकल और आर्थिक दहशत को रोकने के लिए टीकाकरण बेहद अहम है.

कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट के एमडी नीलेश शाह कहते हैं, ''आर्थिक गतिविधियों पर अभी तक बुरा असर नहीं पड़ा है. लेकिन सब कुछ वैक्सीन लगने और क्षेत्रीय लॉकडाउन पर निर्भर करेगा. अगर कोविड पर तेजी से काबू पा लिया जाता है, तो अर्थव्यवस्था बाल-बाल बच निकलेगी. अगर लंबे या बड़े लॉकडाउन लगते हैं, तो हम जून 2020 की तिमाही दोहराई जाती देखेंगे. हमारे लिए अप्रैल के आखिर तक (नए मामलों को सख्ती से रोकना) जरूरी है.'' सरकारी सूत्रों का कहना है कि मई या जून के आखिर तक वैक्सीन की इतनी कमी नहीं रह जाएगी. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया महीने में 7 करोड़ और भारत बायोटेक 1 करोड़ वैक्सीन बनाएगी और 5 करोड़ रूस की स्पुतनिक वैक्सीन के साथ महीने में कुल 13 करोड़ या जून तक 30 करोड़ के आसपास वैक्सीन होंगी. वितरण के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिहाज से शाह हॉटस्पॉट के लोगों को पहले वैक्सीन लगाने का सुझाव देते हैं.

जहां तक वित्तीय जवाब की बात है, केंद्र की खर्च की क्षमता में फिलहाल सुधार आया है. पिछले साल भारत के कर संग्रह बजट अनुमान से बेहतर रहे. मार्च 2021 में माल और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 1.23 लाख करोड़ रुपए रहा जो जीएसटी आने के बाद सबसे ज्यादा था. मगर जल्द किसी केंद्रीय राहत पैकेज की उम्मीद कम ही लोग कर रहे हैं. सबनवीस कहते हैं, ''जब तक पूर्ण लॉकडाउन (केंद्र की तरफ से) नहीं होता, (केंद्रीय) राहत का कोई सवाल ही नहीं है.'' वे यह भी कहते हैं कि राहत के खर्चों के लिए राज्य सरकारों की क्षमताएं अलग-अलग हैं, ''महाराष्ट्र सरीखे राज्य का बजट ज्यादा बड़ा है, लिहाजा 5,500 करोड़ रुपए चुकाना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है. दूसरे राज्यों को ऐसे उपाय मुश्किल लग सकते हैं.'' ज्यादातर राज्य पहले ही भारी उधारियां ले रहे हैं. केयर रेटिंग्ज के मुताबिक, 2021 के वित्तीय साल में 28 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने कुल 7.98 लाख करोड़ रुपए उगाहे, जो 2022 के वित्तीय साल के 6.35 लाख करोड़ रुपए से 26 फीसद ज्यादा थे. 2021-22 की पहली तिमाही में महाराष्ट्र पर सबसे ज्यादा 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज माना जाता है.

लॉकडाउन से वाकई फायदा उठाने वाला ई-कॉमर्स है, जिसमें पिछले साल बड़ी वृद्धि देखी गई. मगर जब महाराष्ट्र सरीखे राज्य गैरजरूरी वस्तुओं की ढुलाई पर भी पाबंदियां लगा रहे हैं, ऑनलाइन बिक्री भी दबाव में है. कुछ मैन्यूफैक्चरिंग फर्म बेहतर ढंग से तैयार हैं क्योंकि कामगार उनकी फैक्ट्रियों के परिसरों में ही रह रहे हैं. फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल ऐंड मीडियम एंटरप्राइजेस (एफआइएमएसएमई) के बोर्ड सदस्य और सोनीपत हरियाणा के राय औद्योगिक क्षेत्र के प्रेसीडेंट राकेश छाबड़ा कहते हैं, ''हमने अपने 50-60 फीसद कामगारों के फैक्ट्रियों में ही रह सकने का इंतजाम किया है, ताकि उत्पादन न रुके. हमने टेस्टिंग भी खुली रखी है और हर हफ्ते टीका शिविर लगा रहे हैं.''

आने वाले हफ्तों में सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि भारत कितनी तेजी से मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है और टीके कितने असरदार ढंग से लगाए जाते हैं. केंद्र को राज्यों के साथ तालमेल बनाकर रोजगार सुरक्षा जाल भी बनाने पड़ेंगे. भारत को एक और आर्थिक धक्का गवारा नहीं. ■

कोविड पर अगर जल्द काबू पा लिया गया तो हम बड़े **आर्थिक नुक्सान** से बच जाएंगे. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम **जून 2020 जैसी तिमाही** फिर देख सकते हैं.

—नीलेश शाह, प्रबंध निदेशक, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट

वसीम अंदराबी/गेट्टी इमेजेज

श्रीनगर के एक प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग में प्रवेश से पहले तापमान की जांच करवाते पंक्ति में खड़े बच्चे

फिर से आंकने का वक्त

कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने या टाल दिए जाने से परेशान छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने भविष्य की योजनाओं की खातिर विभिन्न शिक्षा बोर्ड की ओर उम्मीद भरी नजर लगाई

कौशिक डेका और शेली आनंद

जब देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पस्त होने लगा, तब 14 अप्रैल को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने और बारहवीं कक्षा की परीक्षा को टाल देने का फैसला किया, जो 4 मई से 10 जून के बीच होने वाली थी. यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की मौजूदगी में एक बैठक में किया गया. एक अन्य अखिल भारतीय बोर्ड, भारतीय विद्यालय प्रमाणन परीक्षा परिषद (सीआइएससीई) ने भी कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दीं और 12वीं परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं. द इंटरनेशनल बैकलॉरिएट (आइबी) बोर्ड ने एक कदम आगे बढ़कर अपनी 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दीं और ऐलान किया कि वह भारत में बगैर परीक्षा वाला तरीका अपनाएगा. कई राज्य बोर्ड भी अपनी परीक्षाएं रद्द कर चुके हैं या फिर उस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं.

हालांकि, ये कदम उन अभिभावकों के लिए राहत की तरह हैं, जिन्हें अपने बच्चों के लिए इस वायरस के संक्रमण का डर सता रहा था, लेकिन 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को लेकर अनिश्चितता ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की परेशानी बढ़ा दी है. कई लोगों को लगता है कि इस बार भी पिछली बार जैसी स्थिति दोहराई जाएगी, जब दसवीं और बारहवीं के छात्र परीक्षा सत्र के बीच में थे और तभी देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी. जून, 2020 में, सीबीएसई ने घोषणा की थी कि बोर्ड बाकी बचे प्रश्न-पत्रों के लिए परीक्षा का आयोजन नहीं करेगा और छात्रों

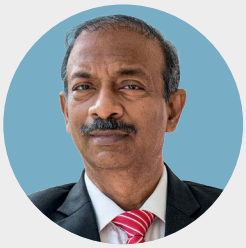

"**नई शिक्षा नीति** ने पहले ही परीक्षा प्रक्रिया में **व्यापक सुधारों** का प्रस्ताव रखा है. उसे लागू करते हुए हमें **दीर्घकालिक योजना** की जरूरत होगी और यह महामारी इस दिशा में उत्प्रेरक का काम कर सकती है."

अमित खरे, *सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय*

का मूल्यांकन वैकल्पिक अंक प्रणाली के जरिए किया जाएगा. दिल्ली के प्रुडेंस स्कूल की 12वीं के छात्र अद्वित बजाज कहते हैं, "साफ-साफ किसी फैसले के अभाव में हमें भ्रम और घबराहट हो रही है."

अनिश्चित भविष्य

हालांकि, इस पर सबकी सहमति है कि परीक्षाएं रद्द करना सही दिशा में उठाया गया कदम है, अभिभावक और छात्र अधिकारियों की तरफ से एक निश्चित रोडमैप की उम्मीद कर रहे हैं. बेंगलूरू में दसवीं कक्षा के एक छात्र के पिता को लगता है कि इस कदम से कड़ी मेहनत करने वाले कई बच्चों का दिल टूट गया है क्योंकि स्कूल की आंतरिक परीक्षाओं में भेदभाव मुमकिन है. नाम न छापने की शर्त पर एक अभिभावक कहते हैं, "कई छात्रों के लिए आंतरिक परीक्षाएं बस तैयारी का हिस्सा थीं, जिसका नतीजा उन्हें बोर्ड परीक्षा में दिखाना था." कुछ लोग तो ऐसी परिस्थिति का अनुमान लगा पाने में नाकाम रहने के लिए, खासतौर पर पिछले साल के तजुर्बे के बाद, बोर्ड पर तोहमत लगा रहे हैं. एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक जे.एस. राजपूत कहते हैं, "सीबीएसई को वैकल्पिक योजना तैयार रखनी चाहिए थी." यही नहीं, बारहवीं की कक्षा के लिए भी आंतरिक परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन की संभावना से कइयों में बेचैनी है.

बहरहाल, शिक्षा मंत्री के मुताबिक, "अगर कोई छात्र मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है, तो वह स्थिति के सामान्य होने के बाद परीक्षा में बैठ सकता है." शिक्षा मंत्री ने कहा कि दसवीं कक्षा के नतीजे बोर्ड की ओर से 'वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर' तैयार किए जाएंगे.

दिल्ली के रहने वाले रूपेश कपूर, जिनकी दो बेटियां दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाली थीं, को लगता है कि अंतिम परिणाम तैयार करने के लिए आंतरिक मूल्यांकन का इस्तेमाल करने से हमेशा एक 'कमी का अंदेशा' बना रहेगा. कई शिक्षकों को भी लगता है कि शायद छात्रों के प्रदर्शन का संपूर्ण मूल्यांकन संभव न हो पाए. पिछले अकादमिक सत्र में शिक्षकों और छात्रों के बीच संपर्क की संभावना भी सीमित ही रही.

कपूर कहते हैं, "स्कूलों को अब बस प्रमाणपत्रों पर पास या फेल लिखना चाहिए क्योंकि कक्षा 10 के अंक शायद ही कहीं उपयोगी साबित होते हैं." कई विशेषज्ञ भी कपूर की बातों से सहमत दिखते हैं और कहते हैं कि कक्षा 10 की परीक्षाओं की अहमियत को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया है. प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की सीईओ रुक्मिणी बनर्जी पूछती हैं, "आखिर दसवीं के लिए बोर्ड परीक्षा की जरूरत ही क्या है? नौवीं या ग्यारहवीं में क्यों नहीं?" दिल्ली के वसंत वैली स्कूल की प्रिंसिपल रेखा कृष्णन इस बात से सहमत हैं और इसे सीबीएसई और दूसरे बोर्ड के लिए एक अवसर के मौके पर देख रही हैं कि वे दसवीं की बोर्ड परीक्षाएं खत्म ही कर दे. वे कहती हैं, "चीजें बदल गई हैं और स्कूल तथा छात्रों को अब तीसरे पक्ष की (बोर्ड परीक्षाएं) जरूरत नहीं है कि उन्हें बताए कि वह विज्ञान, वाणिज्य या मानविकी पढ़ें."

अब क्या होगा?

दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का क्या होगा?

- सीबीएसई ने 2021 में होने वाली दसवीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है और बारहवीं की परीक्षा स्थगित कर दी है
- शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि दसवीं के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेड दिए जाएंगे लेकिन इसके वस्तुनिष्ठ मानक सीबीएसई की ओर से तय किए जाएंगे
- बारहवीं की परीक्षा के लिए 1 जून को परिस्थितियों की समीक्षा के बाद निर्णय लिया जाएगा

"चीजें बदल गई हैं. छात्रों को अब विज्ञान, कॉमर्स या आर्ट्स चुनने के लिए **सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की जरूरत नहीं है.**"

रेखा कृष्णन, *प्रिंसिपल, वसंत वैली स्कूल, दिल्ली*

बारहवीं की परीक्षा के लिए, 1 जून को समीक्षा कर फैसला लिया जाएगा. पिछले साल, सीबीएसई ने उन विषयों के लिए एक वैकल्पिक अंक प्रणाली निकाली थी, जिसकी परीक्षा में छात्र नहीं शामिल हो पाए थे—बाकी बचे हर विषय के अंक छात्रों के अन्य विषयों के अंकों के आधार पर निकाले गए थे. इसमें जिन छात्रों ने चार विषयों की परीक्षा दी थी, उनके तीन सबसे अच्छे विषयों में हासिल अंकों का औसत निकाला गया था, जो तीन विषयों की परीक्षा दे चुके थे उनके सर्वश्रेष्ठ दो विषयों का औसत निकाला गया था. जिन छात्रों ने दो या कम विषयों की परीक्षा दी थी उनके लिए आंतरिक अंक भी शामिल किए गए थे. बाद में, सितंबर 2020 में, बोर्ड ने वैकल्पिक 'सुधार परीक्षाएं' आयोजित की थीं.

इस साल, अभी तक कोई परीक्षा नहीं हो पाई है. ऐसे में, कक्षा 12 के छात्र मूल्यांकन के एक नए तरीके की संभावना को लेकर चिंतित हैं. वे सरकार से इस बात का आश्वासन चाहते हैं कि परीक्षाएं हों, चाहे बाद ही में क्यों न हो. दिल्ली के राजकमल

सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल की 12वीं की कॉमर्स की छात्रा निमिरा फातिमा कहती हैं, ''हम तैयारी करते रहेंगे, लेकिन बाद में जाकर हमसे यह न कह जाए कि परीक्षाएं नहीं होंगी.'' दिल्ली के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की बारहवीं की कॉमर्स की छात्रा सिया मल्होत्रा फातिमा के सामान्य बोर्ड परीक्षाओं के उत्साह से सहमत नहीं हैं. मल्होत्रा कहती हैं, ''हम लोग मार्च, 2020 से ऑनलाइन कक्षाएं कर रहे हैं. एकाउंटेंसी जैसे विषयों में ऑनलाइन तरीके से उसके व्यावहारिक तौर-तरीकों को समझना बेहद मुश्किल है. यही नहीं, आंतरिक मूल्यांकन में हमें गूगल फॉर्म्स पर जाकर विषयनिष्ठ सवाल हल करने होते हैं. अब बिना अभ्यास के हमसे लंबे प्रश्नों के जवाब लिखने की उम्मीद की जा रही है.''

शिक्षा क्षेत्र के कई विशेषज्ञ उनकी चिंता से सहमत हैं. हालांकि कुछ लोग इशारा करते हैं कि वे अभी भी सरकारी स्कूलों और ग्रामीण इलाके के बच्चों की तुलना में बेहतर स्थिति में है. जम्मू-कश्मीर के स्कूली शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव और नवोदय विद्यालय समिति के पूर्व कमिश्नर विश्वजीत कुमार सिंह कहते हैं, ''दूरदराज के इलाकों के छात्रों के पास तो ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच ही नहीं है. इसलिए, अधिकतर तो नियमित परीक्षाओं के लिए भी तैयार नहीं हैं.'' राजपूत के लिए, छात्रों की शिक्षा के साथ समझौता करना गंभीर मसला है. हालांकि, सीबीएसई ने 2020-21 के अकादमिक सत्र के लिए सिलेबस को 30 फीसद कम कर दिया है, तो भी इस घटे हुए सिलेबस को पूरा करना कइयों के लिए चुनौती बना हुआ है. वे कहते हैं, ''अगर किसी चमत्कार के जरिए कोविड दुनिया से गायब भी हो जाए, तो भी अधिकतर छात्र परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं हैं.'' परीक्षाओं को लेकर अनिश्चितता का असर कॉलेजों, खासकर अंतरराष्ट्रीय संस्थानों, में दाखिले पर भी पड़ा है.

इस बीच, स्कूल और अधिकारी स्थिति को सहज बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और निष्पक्ष और साफ-सुथरी मूल्यांकन प्रणाली का वादा कर रहे हैं. लखनऊ में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल कुंवर्स ग्लोबल स्कूल के संस्थापक और प्रबंध निदेशक राजेश कुंवर सिंह कहते हैं, ''मुझे भरोसा है कि चाहे बोर्ड कोई भी हो, सभी छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ रास्ता निकाला जाएगा. अधिक संभावना इस बात की है कि छात्रों को ऑनलाइन मूल्यांकनों, पूर्व की परीक्षाओं, कक्षा में सहभागिता और उनके आंतरिक काम के जरिए अंक दिए जाएंगे.''

आगे की राह

शिक्षाविदों और प्रशासकों का मानना है कि यह संकट शिक्षा के मूल्यांकन और सुधारों की दिशा में तेज कदम बढ़ाने का अच्छा मौका है. कृष्णन कहते हैं, ''हमें इन बोर्ड परीक्षाओं को अहम मानने की आदत हो गई है. लेकिन अब स्कूली शिक्षा से कॉलेज में दाखिले के लिए ये कोई बेंचमार्क नहीं रह गए हैं.'' केंद्रीय उच्च शिक्षा के सचिव अमित खरे भी यह मानते हैं कि तीन घंटे की परीक्षा में किसी छात्र के स्कूल में सीखी बातों का मूल्यांकन नहीं हो सकता, लेकिन वे आश्वासन देते हैं कि जुलाई, 2020 में लागू की गई नई शिक्षा नीति परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार की बात करती है. खरे कहते हैं, ''यह महामारी इस दिशा में उत्प्रेरक का काम कर सकती है.''

प्रथम की बनर्जी ने तो 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की प्रासंगिकता पर भी सवाल किए हैं क्योंकि पेशेवर पाठ्यक्रमों में शामिल होने वाले छात्रों को तो हर हालत में प्रवेश परीक्षा में बैठना ही होता है. खरे बताते हैं कि नई शिक्षा नीति के मुताबिक, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी अगले साल से अंडर-ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए कॉमन टेस्ट आयोजित करेंगे. बनर्जी कहती हैं, ''अन्य विश्वविद्यालय और संस्थान भी इस प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं. स्कूल के स्तर पर, इस मूल्यांकन का यही सही वक्त है कि हम क्यों और कैसी बोर्ड परीक्षाएं चाहते हैं.'' वे एक और क्रांतिकारी विचार पेश करती हैं—ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने की बजाए, हर शिक्षक कम से कम 10 छात्रों को एक दिन में फोन करे और उनके साथ विस्तार से बात करे और उन्हें काम दें और उनका अंतिम मूल्यांकन के लिए तैयार करे. इस बात की भी मांग उठी थी कि बोर्ड परीक्षाएं ऑन-डिमांड ऑनलाइन टेस्टों के आधार पर आयोजित की जाएं.

> ''अगर हम इतनी बड़ी आबादी का **तयशुदा समय और स्थान पर टीकाकरण कर सकते हैं** तो फिर हम उसी तरीके से परीक्षाएं क्यों नहीं आयोजित कर सकते?''
>
> **रुक्मिणी बनर्जी,** *सीईओ, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन*

बहरहाल, भारत में डिजिटल खाई एक बहुत बड़ी समस्या है. भारत की टेलिकॉम स्टेटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट, 2019 के मुताबिक, ग्रामीण भारत में हर 100 व्यक्तियों पर 25.36 इंटरनेट उपभोक्ता हैं. जबकि शहरों में यह संख्या 97.94 है. लेकिन राजपूत के पास एक कार्ययोजना तैयार है. वे कहते हैं, ''2003 में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने मांग के आधार पर परीक्षाओं की अवधारणा को मजबूत किया, जिसमें छात्र ऑनलाइन परीक्षा और केंद्र का चयन अपने हिसाब से कर सकता है. अगर अधिकारियों ने पिछले वर्षों में क्षमता का विकास कर लिया होता, तो हमें उस बाधा का सामना नहीं करना होता, जिसका हम अभी कर रहे हैं.'' बनर्जी उनकी बात से सहमत हैं, ''अगर हम इतनी बड़ी आबादी का तयशुदा समय और स्थान पर टीकाकरण कर सकते हैं, तो हम उसी तरीके से छात्रों की परीक्षाएं क्यों नहीं करवा सकते?''

शिक्षाविद् इस बात पर एकमत हैं कि मूल्यांकन के विकेंद्रीकृत मॉडल की जरूरत है जिसमें स्कूलों को बड़ी भूमिका निभानी होगी. विश्वजीत कुमार सिंह कहते हैं, ''हमें अपने स्कूलों को वह आजादी देनी होगी कि वे प्रौद्योगिकी का अपने मन मुताबिक इस्तेमाल कर पाएं और मूल्यांकन के अपने मॉड्यूल तैयार कर सकें. यह चीज ऊपर से थोपी नहीं जानी चाहिए क्योंकि हर स्कूल को अलग किस्म के मसले पेश आते हैं और स्कूल वाले खुद जानते हैं कि उन्हें कैसे सुलझाया जाए.''

असल में, कुछ बोर्ड पहले से ही स्कूल आधारित वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं, मसलन आइबी, जो मूल्यांकन जारी करता है इसमें सिर्फ फाइनल परीक्षाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है. कैंब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन से मान्यता प्राप्त मुंबई की आइबी स्कूल आदित्य बिड़ला वर्ल्ड एकाडेमी की प्रिंसिपल राधिका सिंह कहती हैं, ''इससे यह तय होता है कि छात्रों को वह ग्रेड मिलता है जिसके वे लायक होते हैं.'' बेंगलूरू के आइबी स्कूल नींव एकाडेमी की संस्थापक और प्रमुख कविता गुप्ता सभरवाल कहती हैं, ''आइबी जैसे बोर्ड पढ़ाई का मूल्यांकन करते हैं, जो लंबे समय में यानी एक-दो साल में संपन्न होता है. और उसके बाद इसकी देखरेख और ग्रेड बोर्ड तय करता है. पढ़ाई का मूल्यांकन जैसी चीज भारत में अधिक चलन में नहीं है और इसकी जरूरत आगे सीखने की योजना के लिए होती है.''

हालांकि, एक अच्छी खबर है कि नई शिक्षा नीति का मकसद मूल्यांकन की एक व्यवस्था तय करने का है. खरे कहते हैं, ''हालांकि, दीर्घकालिक योजना पाठ्यक्रमों पर है, हम छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की विभिन्न विधियों पर भी विचार कर रहे हैं, जबकि हम उनकी सेहत को सबसे अधिक प्राथमिकता पर रख रहे हैं. जून में जब परिस्थितियों की समीक्षा करते हुए आखिरी योजना तैयार की जाएगी तब सभी पक्षों की चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा.'' फिलहाल तो छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की दुविधा मिटाने की दरकार है. ■

टोक्यो के लिए तैयार

इस साल ओलिंपिक की तैयारियों के क्रम में भारतीय खिलाड़ी असाधारण बाधाओं से जूझ रहे

खेल के लिए खुद को तैयार रखते खिलाड़ी
(बाएं से) टेबिल टेनिस खिलाड़ी जी. साथियन, शटलर जी. साई प्रणीत, तीरंदाज दीपिका कुमारी और बॉक्सर अमित पंघाल (नीले कपड़ों में)

जब पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन लगा तो दीपिका कुमारी अपने मंगेतर (अब पति) अतनु दास के कोलकाता स्थित घर में फंस गई थीं. दोनों तीरंदाजों ने टोक्यो ओलिंपिक के लिए क्वॉलिफाई कर लिया था पर इस अचानक आई बाधा से उनकी तैयारियों को झटका लगा. कुछ दिनों तक दोनों ने योग और इंडोर कसरत की. दीपिका तीन मीटर दूर रखे निशाने पर तीरंदाजी अभ्यास में व्यस्त रहीं. उन्होंने छत पर दौड़ने की कोशिश की पर पीठ में चोट लगने के बाद वे रुक गईं.

उधर, चेन्नै में, टेबल टेनिस खिलाड़ी जी. साथियन ने स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच रामजी श्रीनिवासन के बनाए कार्यक्रम का पालन करने का फैसला किया. उन्होंने पानी की बोतलों, कुर्सियों और स्कूली बस्तों से फिटनेस कायम रखा. लॉकडाउन हटा तो एथलीट ट्रैक पर आए. पिछले कुछ महीनों को देखा जाए तो स्पष्ट है कि ओलंपिक का आयोजन असाधारण परिस्थितियों में होने जा रहा है.

महीनों के इंतजार के बाद, जब अमित पंघाल रिंग में उतरे तो वे किसी अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में शिरकत को बेताब थे. उन्होंने फ्रांस में सोना जीता और कोलोन विश्व कप में भी स्वर्ण पदक हासिल किया जबकि उनकी बॉक्सिंग टीम बाकी सदस्य बार-बार कोविड पॉजिटिव निकलते रहे. पंघाल कहते हैं, ''मानसिक रूप से, बॉक्सिंग इतना टफ है कि मैं सब झेल लेता हूं. इसलिए, मेरे लिए कुछ नहीं बदला है. मैं प्रशिक्षण के दौरान यही चीजें करता रहा, हालांकि, अब हम स्वास्थ्य और सुरक्षा के मानकों का कड़ाई से पालन करते हैं.''

शटलर बी. साई प्रणीत के पिछले साल के प्रदर्शन पर बिना साझीदार के प्रशिक्षण का असर साफ दिखा था. प्रतिस्पर्धा के दोबारा शुरू होने का भी कोई फायदा नहीं हआ ₹ योंकि एक के बाद एक टूर्नामेंट या तो स्थगित होते गए या फिर रद्द कर दिए गए. वे कहते हैं, ''यह बड़ा हताशा भरा है कि आप टूर्नामेंट

शारीरिक क्षमताओं के साथ भारतीय एथलीट मानसिक रूप से सुदृढ़ होने पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं

अपने खेल के उस्ताद

एथलीट जिनमें पताका फहराने का है माद्दा

बजरंग पूनिया
विश्व चैंपियनशिप में तीन पदक जीतनेवाले भारत के पहले पहलवान, बजरंग पूनिया ने रोम में माटेयो पेलिकोन रैंकिंग श्रृंखला में स्वर्ण पदक जीतकर धमाकेदार वापसी की है. वे 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग के शीर्ष दावेदारों में से एक हैं.

मनु भाकर
मार्च में विश्व कप में निशानेबाज मनु भाकर ने ओलंपिक स्पर्धाओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य में से प्रत्येक में कुल पांच पदक जीते. 19 साल की उम्र में, वे ओलिंपिक में भारत की सबसे कम उम्र की पदक विजेता हो सकती हैं.

की मानसिकता में आ जाएं और फिर देखें कि यह आयोजित ही नहीं हो रहा है. ''

जनवरी में योनेक्स थाईलैंड ओपन खेलने के बाद उनका कार्यक्रम कुछ दिनों के बाद टोयोटा थाईलैंड ओपन खेलने का था. बहरहाल, जांच में कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें नाम वापस लेकर घर लौटना पड़ा. साई प्रणीत कहते हैं, ''बदकिस्मती थी. अब मैंने उसे पीछे छोड़ दिया है और आगामी तीन टूर्नामेंट पर ध्यान केंद्रित किया है. मैं उसमें क्वॉलिफाई करने के लिए मजबूत स्थिति में रहना चाहता हूं.''

यह शटलर अपनी मानसिक तैयारी पर भी खासा ध्यान दे रहा है. इस बात की संभावना कम ही है कि स्टैंड में भारतीय समर्थक मौजूद होंगे, क्योंकि बाहरी दर्शकों को अनुमति नहीं है, उन्हें लगता है कि यही अहम साबित होगा.

तीरंदाजी के दल में टीकाकरण के दो दौर हो चुके हैं, जो दास के लिए राहत की बात है. पुणे के कैंप में, दीपिका ने खुद को गर्मी में भी मास्क के साथ अभ्यास करने के लिए ढाल लिया. अब उनकी निगाहें ग्वाटेमाला में आयोजित इस सीजन की पहली प्रतियोगिता विश्व कप पर टिकी है. दीपिका कहती हैं, ''किसी स्पर्धा में खेले हुए हमें साल भर हो गया है. मुझे किसी टूर्नामेंट की सख्त जरूरत महसूस हो रही है और उनका आयोजन ओलिंपिक से पहले पर्याप्त रूप से नहीं हो रहा है. इसलिए बेहतर है कि हम स्थितियों को स्वीकार करें और अपनी तैयारी करें.''

—शैल देसाई

सखोम मीराबाई चानू

चोटों ने सखोम मीराबाई चानू की राह में बाधाएं खड़ी की हैं. लेकिन अमेरिका में पुनर्वास और प्रशिक्षण कार्यशाला के बाद वे अब ओलंपिक में छाप छोड़ने की उम्मीद कर रही हैं. उत्तर कोरिया के पीछे हटने के साथ, चानू अब 49 किलोग्राम वर्ग में दूसरे स्थान पर मौजूद भारोत्तोलक हैं.

खेल

बांध लिए पाल

पिछले महीने, ओमान में मुसानाह ओपन चैंपियनशिप में, **नेत्रा कुमानन** लेजर रेडियल क्लास में महज एक पॉइंट से सोने से चूक गई थीं. लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इतिहास तो रच ही दिया. वे ओलंपिक में क्वॉलिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बन गईं. लगता है, महज 23 साल की कुमानन के कंधों में गजब का दमखम है.

● लॉकडाउन के दौरान आपने अपना फिटनेस कैसे बरकरार रखा?

हमने कोच (तमस एस्जेस) के साथ वीडियो कॉल किए और दिन में दो बार फिटनेस सत्र रखे—एक बाइक पर और दूसरा घर पर बने इनडोर जिम में.

● नौकायन में मानसिकता की क्या भूमिका होती है? आपने इस पर कैसे काम किया?

नौकायन असल में अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक होना है—हवा, मौसम—और दूसरी नावों के प्रति भी. इसमें लगातार फैसले लेना भी शामिल है. अगर आपका नजरिया सही नहीं होगा और हर पल पर आपका फोकस नहीं होगा, तो आप गलत फैसले लेंगे या फिर फैसला ही नहीं ले पाएंगे. आत्मविश्वास बनाने के लिए मैं इज्राइल के एक मनोवैज्ञानिक के साथ काम कर रही हूं. निरंतरता बनाए रखने के मसले पर इससे बहुत फर्क पड़ा है. और इसी वजह से मैं खुद को पदकों की दौड़ में बनाए रख पाई हूं.

● ओलंपिक में जाने का मतलब क्या है?

इससे इस खेल की ओर ध्यान जाएगा. उम्मीद है कि ज्यादा लोग इसे अपनाएंगे. ओलिंपिक में जाना सपने के सच होने सरीखा है. और यह पदक हासिल करने की दिशा में एक कदम आगे की ओर है. हम पेरिस 2024 से पदक हासिल करने की ओर तैयारी कर रहे हैं.

● नौकायन से इतर आप क्या करती हैं?

सामान्य परिस्थितियों में मैं स्पेन से घर आ जाती हूं या यात्राएं करती हूं. इस साल, हम बाइक यात्राओं पर गए, सूर्यास्त देखते रहे या बस यूं ही घूमते रहे और मजे किए. यहां तक कि पढ़ाई भी मेरा ध्यान नौकायन से दूर ले जाती है.

—शैल देसाई

संगीत

महामारी में संगीत बना सहारा

नवीन कुमार

कोरोना महामारी से परेशान लोग राहत पाने के लिए संगीत का भी सहारा ले रहे हैं. ऐसे में ताजा रचे जा रहे गानों की मांग बढ़ गई है. नतीजतन डूबती म्युजिक इंडस्ट्री में नई जान आ गई है. संगीत के कारोबार को बढ़ावा देने में डिजिटल प्लेटफार्म का साथ मिल गया है. यही वो आज का तकनीकी माध्यम है जहां से लोग अपनी पसंद के गाने डाउनलोड करके सुनते हैं, वीडियो देखते हैं और हिट्स के हिसाब से म्युजिक कंपनियों के एकाउंट में सीधे पैसे आने से कमाई हो रही है. सारेगामा इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम मेहरा इसे कुछ यूं बयान करते हैं, ''इन दिनों लोग घर में झाड़ू लगाते हुए, ऑफिस का काम करते हुए या फिर बस, ट्रेन में या परिवार के साथ बैठकर पुराने और ताजा आ रहे गाने सुन रहे हैं. गानों की खपत बहुत बढ़ गई है. इसका फायदा म्युजिक इंडस्ट्री को हो रहा है.'' संगीत के डिजिटल कारोबार की लोकप्रिय म्युजिक कंपनी टी-सीरीज सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज के सीएमडी भूषण कुमार विषय के कैनवस को थोड़ा और फैलाते हुए कहते हैं, ''पूरी फिल्म बिरादरी के लिए 2020 की शुरुआत अच्छी नहीं थी. लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से लोगों ने गानों को देखा, सुना और पसंद किया, उससे हमें संगीत बनाने के लिए प्रोत्साहन मिला और हमने उनके मनोरंजन के लिए अच्छा म्युजिक रचा.'' टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कुमार तौरानी ने भी अच्छे संगीत के प्रति श्रोताओं-दर्शकों के मूड को भांपते हुए गानों में जबरन कोरोना शब्द डालने से इन्कार कर दिया ''क्योंकि लोग दुखी हैं, सहमे हुए हैं. उनके लिए तो हौसला बढ़ाने वाला गाना बनाना चाहिए. हमने सकारात्मक सोच के साथ गाने बनाए और लोगों ने उसे पसंद किया.''

पहले ही महामारी की मार से परेशान श्रोता-दर्शक उदासी भरे संगीत को सुनने से इन्कार कर रहे हैं. बडोला म्युजिक कंपनी के म्युजिक डायरेक्टर डी.जे. शेजवुड का अपना फीडबैक हैः ''लोगों ने घरों में बैठकर मेलोडी, रोमांटिक और डांस नंबर ज्यादा सुने हैं.'' अल्ट्रा मीडिया ऐंड इंटरटेनमेंट ग्रुप के सीईओ सुशील कुमार अग्रवाल का मानना है कि ''महामारी में घरों में बंद लोगो के लिए म्युजिक अच्छा दोस्त बन गया.''

महामारी से पहले लोग ज्यादातर फिल्मी गाने सुनते थे. अब उनकी पसंद बदल गई है. अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान गैरफिल्मी गाने पसंद किए गए. मजे की बात है कि जिस डिजिटल माध्यम ने म्युजिक इंडस्ट्री का भट्ठा बैठाया था, पायरेसी से सब सत्यानाश किया था, आज उसी माध्यम के जरिए लोगों तक ये गाने पहुंच रहे हैं. मेहरा स्पष्ट करते हैं कि कस्टमर क्या बदलेगा? वह तो बादशाह है. बदलना कंपनियों को है. ''अच्छी बात यह है कि गाना सुनने की आदत नहीं बदली. आज भी संगीतप्रेमी

मानते हैं कि साहिर लुधियानवी, आनंद बक्शी, गुलजार और जावेद अख्तर जो लिखते थे वे गाने होते थे.'' इस बीच म्युजिक का ऑडिएंस बेस बढ़ने से हुआ यह है कि किसी भी अच्छे एल्बम को छह महीने में अच्छा नतीजा आ जाता है. 2001-02 में कैसेट, सीडी वाला म्युजिक बिजनेस खत्म हो गया था. 2010-11 के बाद तो यूट्यूब और सावन जैसे प्लेटफॉर्म्स ने म्युजिक इंडस्ट्री को बचाया. फेसबुक, इंस्टाग्राम, गाना के साथ ओटीटी वाले आए तो लोगों को भरपूर ही गाना सुनने को मिलने लगा. अब हर किसी के हाथ में ही म्युजिक है. एक मोटे अंदाज के अनुसार, दुनिया में रोज यही कोई 60,000 गाने रिलीज होते हैं. भूषण भी स्वीकारते हैं कि डिजिटलाइजेशन के साथ पहुंच बढ़ने से मनोरंजन उद्योग को आर्थिक लाभ मिल रहा है. ''हमारी सामग्री विभिन्न ऑडियो स्ट्रीमिंग और वीडियो प्लेटफार्मों के माध्यम से दर्शकों-श्रोताओं तक एक क्लिक में पहुंच जाती है.''

आजकल एल्बम नहीं बल्कि गाने लांच होते हैं. पिछले साल रिलीज फिल्में थिएटर की बजाय सीधे डिजिटल पर चली गईं तो कोरोना काल में म्युजिक कंपनियों ने गैरफिल्मी गानों पर फोकस किया. मेहरा बताते हैं, ''सारेगामा ने बड़े टाइअप करके गैरफिल्मी गाने, वह भी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भोजपुरी और तमिल भाषाओं में लांच करने की कोशिश की. इस कंपनी के हिंदी में *मजा* (बी प्राक और जानी), *आज सजेया* (गोल्डी सोहेल और अलाया एफ) और *रंग लगेया* (रोचक कोहली और मोहित चौहान) चर्चित हैं. हमने घर बैठे आर्टिस्टों मीका सिंह, सनम पुरी और पलाश सेन के साथ पुराने गानों का रिइंटरप्रेटेशन

श्रोताओं-दर्शकों की पसंद को भांपते हुए म्युजिक कंपनियों ने महामारी के दौरान मूड को हल्का करने वाले संगीत रचने पर ध्यान दिया और जिसे काफी पसंद भी किया गया

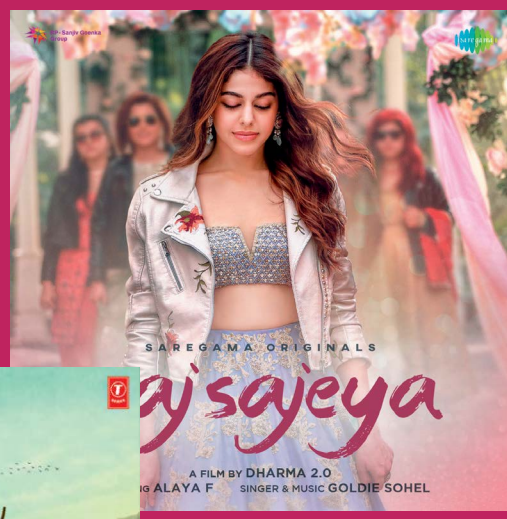

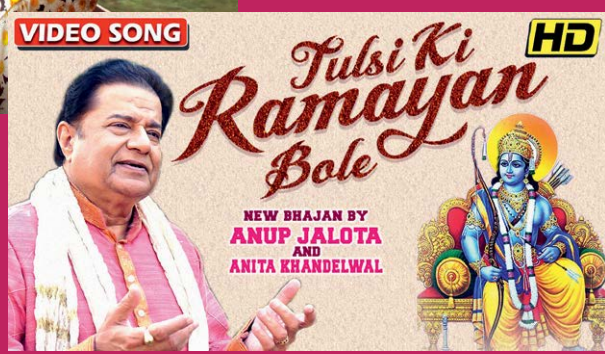

किया.'' ऐसे कलाकारों की भी खोज हुई जिनके गले में दम है पर उन्हें मौका नहीं मिल रहा था. गुजराती में काजल माहेरिया (*हवे मलवानी आशा ना रखो*) और हिंदी में गोल्डी सोहेल को पेश किया गया. तमिल में यूट्यूब पर कारवां लाउंज नाम से प्रॉपर्टी तैयार हुई जिसमें विजय अंटोनी सहित कई बड़े गायकों से तमिल के पुराने गाने नए ढंग से पेश कराए गए. अमेजन इसमें बतौर एडवरटाइजर जुड़ा. सारेगामा के हिंदी में *एक्सोन* (पेपोन), *चमन बहार* (सोनू निगम), भोजपुरी में *अपनी तो जैसे तैसे* (खेसारी लाल यादव), *गोरकी पतरकी रे* (रितेश पांडे), गुजराती में *कोना रे भरोसे* (राकेश बारोट), *मारु आ दिल तारा बाप नी जगीर नथी* (जिग्नेश बारोट) और पंजाबी में *धुंद दी खुशबू* (काका) तथा *नीट* (परमीश वर्मा) जैसे हिट गाने हैं.

महामारी के दौरान म्युजिक कंपनियां थोड़ी संवेदनशील भी रही हैं. सारेगामा ने अपने कारवां विंग के तहत लॉकडाउन के समय दो ऐसे नए प्रॉडक्ट लांच किए जो परिवार और बच्चों को कोरोना से बचाव में मददगार साबित हो रहे हैं. एक है कारवां मिनी किड्स जो अभिभावकों की परेशानी को समझ कर बाजार में लाए गए. अभिभावक अपने दस साल की उम्र तक के बच्चों को दिनभर मोबाइल और घर से बाहर खेलने नहीं देना चाहते. उनके लिए यह छोटा कारवां म्युजिक के साथ मोबाइल की जगह खेलने और पढ़ने का लोकप्रिय सामान बन गया. इसमें छह बच्चों के क्रिएटिव्स भी डाले गए हैं. *लकड़ी की काठी* जैसे गाने हैं तो कहानियां और कविताएं भी. गणित भी गाने से पढ़ाई जाती है. नर्सरी की लाइंस और गायत्री मंत्र समेत और भी चीजें हैं. दूसरा प्रोडक्ट है पोर्टेबल म्युजिक प्लेयर कारवां कराओके. उसमें 5,000 सदाबहार गानों के अलावा एक हजार प्री-लोडेड कराओके ट्रैक हैं. यह उनके लिए है जो कोरोना से बचने के लिए इस समय रेस्त्रां या होटल में जाकर पार्टी नहीं करना चाहते. इसमें एक स्क्रीन पर गाना चलता रहता है और दो लोग माइक्रोफोन पर उसे देखकर अपनी पसंद के सिंगर के गाने गा सकते हैं. साथ ही घर में मित्रों-रिश्तेदारों के साथ पार्टी भी चलती रहेगी.

सारेगामा की तरह टिप्स ने भी नए गायकों की खोज की और हिंदी सहित छह क्षेत्रीय भाषाओं में गैरफिल्मी गाने बनाए. उसने समीर खान, साहिल खान, संजीव राठौड़ (मुंबई), बंदिश वाज (अहमदाबाद), सोनू सिंह (दिल्ली) आदि के साथ 20 गाने तैयार किए हैं. यूट्यूब पर टिप्स इबादत, टिप्स भक्ति प्रेम, टिप्स मराठी के साथ गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी भाषा के चैनल हैं. टिप्स का मुख्य चैनल है टिप्स ऑफिशियल. टिप्स इबादत के लिए 15 गाने बनाए गए हैं. बीते एक साल में भोजपुरी और हरियाणवी गाने सबसे ज्यादा हैं. पंजाबी और हिंदी गाने थोड़े कम हैं. डिजिटल पर सबसे बड़ा प्लेटफार्म यूट्यूब है. यहां कभी-कभी छह महीने के बाद भी गाने हिट होते हैं. बकौल तौराणी, अलका याज्ञनिक, कुमार सानू, सोनू निगम, खेसारीलाल यादव टिप्स के टॉप टेन सिंगरों में हैं. *जीनियस* फिल्म के गाने *तेरा फितूर, दिल मेरी ना सुने* और *जिन्ने मेरा दिल लुटिया, कुली नंबर-1* का *हुस्न है सुहाना* हिट लिस्ट में हैं. *ईश्वर का वो सच्चा बंदा* (सोनू निगम) को दस लाख से ज्यादा दर्शक देख चुके हैं. कैलाश खेर का *सतगुरु मेहेर कर* (आठ लाख दर्शक) और समीर अनजान का लिखा *हरे कृष्णा हरे कृष्णा* इसी साल रिलीज हुआ है. इसे अब तक एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है.''

म्युजिक बाजार में टी-सीरीज भी बड़ा खिलाड़ी है. नए सिंगरों को पेश करने के साथ गाने बेचने में अव्वल है. महामारी के दौरान उसके जारी किए गए *लुट गए, मेरी आशिकी, तारों के शहर, दिल तोड़ के, बेबी गर्ल, तेरी आंखों में* और *नाम* जैसे गानों को सभी वीडियो और ऑडियो स्ट्रीमिंग साइटों पर पसंद किया गया. 2020-21 के दौरान 60 से अधिक एकल म्युजिक जारी किए गए. यूट्यूब और अन्य ऑडियो प्लेटफार्म से बेहतर फीडबैक मिले हैं. अपने गानों से 4 अरब से ज्यादा लोगों को मोहित करने वाले जुबिन नौटियाल इस समय सबसे सफल गायकों में से एक हैं.

म्युजिक के एक अन्य खिलाड़ी अल्ट्रा ने अप्रैल 2020 से अब तक 250 से ज्यादा म्युजिक एल्बम निकाले हैं. इनमें 60 हिंदी पॉप और धार्मिक, 170 मराठी के लोकसंगीत और धार्मिक, 6 गुजराती के और 29 बंगाली के लोक और धार्मिक हैं. अनूप जलोटा के हिंदी *भजन तुलसी की रामायण बोले*, मराठी में *चंदाचे आई बनानी* और *चल इश्काची वाट धारु* के साथ गुजराती में *सजन तारा संभारना* टॉप फाइव में जगह बनाए हुए हैं. अल्ट्रा के म्युजिक वीडियो और एलबम अल्ट्रा बॉलीवुड, अल्ट्रा भक्ति, अल्ट्रा गुजराती, कृणाल म्युजिक, अल्ट्रा बंगाली पोस्ट के अलावा गाना, सावन, स्पॉटिफाइ, अमेजन म्युजिक, विंक ऐप पर भी हैं.'' हरिद्वार के रहने वाले म्युजिक डायरेक्टर शेजवुड बताते हैं कि बडोला म्युजिक ने भी दर्जन भर से ज्यादा गाने बनाए हैं जिसमें बब्बू मान का *मेरी जन्नत* और *बारिश की बूंदें* काफी लोकप्रिय हैं.'' म्युजिक इंडस्ट्री को जिस तरह से संवरने का मौका मिल रहा है उससे इंडस्ट्री के लोग अब अच्छा म्युजिक बनाने पर फोकस कर रहे हैं. ■

अब नए खेल में

क्रिकेटर **इरफान पठान** के लिए साल 2021 काफी हलचल भरा रहा. जनवरी में उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की और मार्च में उन्हें कोविड संक्रमण हो गया. अब तमिल फिल्म *कोबरा* से वे अभिनय में पदार्पण करने जा रहे हैं

● आखिर किस वजह से आपने इस साल रिटायर्मेंट की घोषणा कर दी?

मैं 2016-17 में ही रिटायर होना चाहता था. 2016 के अच्छे सीजन के बाद में चुने जाने की प्रतीक्षा कर रहा था. मैं नंबर 1 था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे लेकिन इस सबसे कुछ हासिल नहीं हुआ, लिहाजा मैंने सोचा, यही सही वक्त है. लेकिन मैं इस खेल को कुछ वापस देना चाहता था. मैंने दो साल जम्मू-कश्मीर क्रिकेट के साथ काम किया और फिर रिटायर होने का फैसला किया.

● बतौर कमेंटेटर काम में आनंद आता है?

यह मेरा आइपीएल का चौथा सीजन है. यह काम वास्तव में बेहद रोमांचक है. बारीकियों का बखान करना मुझे अच्छा लगता है जो शायद मैच देख रहा एक फैन पकड़ न पाए. विशेषज्ञ के नजरिये से हमें दर्शकों को बेहतर एहसास कराना चाहिए.

● अभिनय में हाथ आजमाने का पहला तजुर्बा कैसा रहा?

बहुत बढ़िया. मैंने निर्देशक (आर. अजय ज्ञानमुतु) से पूछा कि मुझे ही क्यों लिया? मैं कैमरे का सामना करता रहा हूं लेकिन अभिनय अलग चीज है. पर वे अडिग रहे. मुझे लालच था ए.आर. रहमान का. रहमान के साथ कौन काम नहीं करना चाहेगा? मैं नर्वस था लेकिन [कोई] मुझे अभिनय में मदद करता रहा. मुझे इसमें बहुत आनंद आया.

● महामारी जैसी आपदा एक प्रोफेशनल एथलीट के करियर में कितनी परेशानी पैदा करती है?

सिर्फ क्रिकेट या खेल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर कोरोना का असर है. अभी सूरज ढल रहा है लेकिन कल फिर सुबह होगी. चीजें ठीक हो जाएंगी, ये भरोसा रखना महत्वपूर्ण है.

—भाव्या डोरे

सुजीत जायसवाल/गेट्टी इमेजेज

आज तक

देश का नं. 1 हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है

IndiaContent

SEARCH FOR EDITORIAL IMAGES ENDS HERE